अंक 64
जनवरी - दिसंबर 2023

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ISSN . 0972-5881

ग्रामीण विकास समीक्षा

ग्रामीण उद्यम और रोजगार विशेषांक

2023

राग्राविपंरासं
NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद - 500030, भारत
www.nirpr.org.in

ग्रामीण विकास समीक्षा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद - 30 (तेलंगाना) द्वारा प्रकाशित एक अर्ध वार्षिक पत्रिका है ।

पत्रिका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में अध्ययन और अनुसंधान को बढावा देना है । यह सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण के बीच एक सुदृढ संयोजन स्थापित करता है तथा ग्रामीण विकास से जुडे नीति निर्माताओं, कार्यपालकों तथा विभिन्न समाजविज्ञान आयामों में विचार विनिमय का एक मंच उपलब्ध कराता है ।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार है और इनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान संस्थान (हैदराबाद) किसी भी प्रकार जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं है ।

अध्यक्ष

डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार

महानिदेशक

सदस्य

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडीसी)

सदस्य

डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर

एसोसिएट प्रोफेसर (सीडब्ल्यूई एवं एल)

संपादक

श्रीमती अनिता पांडे

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सहायक संपादक

श्री ई. रमेश

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

ग्रामीण विकास समीक्षा सहयोगी लेखकों के लिए

प्रकाशन की निरंतरता को बनाये रखने के लिए लेखकों से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मौलिक, अनुसंधानात्मक तथा विश्लेषणात्मक मौलिक लेख प्रेषित करने की कृपा करें ताकि इस ज्ञान गांगा को जन साधारण तक ले जाया जा सके । फलत: ऐसे लेखों की भाषा सरल एवम् बोधगम्य हो तथा आंकडो एवं सारणियों का कम से कम प्रयोग हो । लेख टंकित होना चाहिए, हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किये जायेंगे । इस संबंध में यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो संपादक से संपर्क किया जा सकता है ।

ग्रामीण विकास समीक्षा

ग्रामीण उद्यम और रोजगार

विशेषांक

जनवरी – दिसंबर 2023

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500030 (भारत)

ग्रामीण विकास समीक्षा

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1	ग्रामीण जीवन के बदलते स्वरूप में उत्कृष्टता की खोज: स्व-सहायता समूह उद्यमियों के मन की बात मामले * *वानिश्री जोसेफ, जी. नरेंद्र कुमार, एन. वी. माधुरी, अरुणा जयमणि, लखन सिंह, प्रत्यूस्ना पटनायक, रत्ना भुयान और वेंकटमल्लू थडाबोइना*	1
2	अमृत सरोवरों के माध्यम से विकास की परिकल्पना: जल भंडारण और संरक्षण के पुनरुद्धार के लिए मन की बात मामलों का एक अध्ययन * *सोनल मोबार रॉय, सी. धीरजा, दिगंबर ए. चिमनकर, अनुराधा पल्ला, राज कुमार पम्मी, और जी. नरेंद्र कुमार*	29
3	उत्तराखंड में मनरेगा कार्यान्वयन - एक बहुआयामी स्थानिक विश्लेषण * *स्तुति गुप्ता, शिखा आनंद, पी. लक्ष्मी थनमई, के.एम. रेड्डी और टी. रविशंकर*	48
4	क्या भारत में महिलाएं सशक्त हैं? भारत के राजस्थान के लाडनू ब्लॉक से मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का एक परिप्रेक्ष्य * *हेमन्त कुमार मिश्रा और बिजयलक्ष्मी पांडा*	66
5	उद्यमशीलता प्रवृत्ति: असम में आदिवासी उद्यमियों पर एक अध्ययन * *बिनीता टोपनो और आर. ए. जे. सिंगकोन*	81
6	ओडिशा में महिला स्व-सहायता समूहों और उनके उद्यमों की स्थिरता को मापना * *नवीन कुमार राजपाल और शर्मिला तमांग*	98
7	पुस्तक समीक्षा: व्हाट वर्क्स: जेंडर इक्वैलिटी बाय डिज़ाइन बाय आइरिस बोहनेट, * *अनुराधा पल्ला*	123

ग्रामीण जीवन के बदलते स्वरूप में उत्कृष्टता की खोज: स्व-सहायता समूह उद्यमियों के मन की बात मामले

वानिश्री जोसेफ, जी. नरेंद्र कुमार, एन. वी. माधुरी, अरुणा जयमणि, लखन सिंह,
प्रत्यूस्ना पटनायक, रत्ना भुयान और वेंकटमल्लू थडाबोइना

सारांश

भारत के प्रधान मंत्री ने अपने मन की बात (एमकेबी) संबोधनों के विभिन्न कड़ियों में स्व-सहायता समूह के सदस्यों की उद्यमशीलता की भावना, समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके द्वारा किए गए नवाचारों को मान्यता दी। एसएचजी महिला समूहों का मितव्ययिता से सूक्ष्म उद्यम की ओर आंदोलन उन्हें पूंजी, साझा संसाधनों और एकत्रित ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। इस शोध अध्ययन में छह एसएचजी की सफल उद्यमशीलता गतिविधियों के पीछे के कारकों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है, जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री के मन की बात संबोधन में किया गया था। इन एसएचजी उद्यमों का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, यह प्रपत्र सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने में मन की बात के प्रभाव की जांच करता है। अध्ययन किए गए एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों की सामान्यताओं, विविधताओं और सफलता कारकों को सामने लाने के लिए क्रॉस-केस तुलना की जाती है।

इस अध्ययन से यह पता चला है कि कई समूहों वाले क्लस्टर-आधारित एसएचजी उद्यम व्यक्तिगत उद्यमों की तुलना में अधिक सफल हैं। इन उद्यमों ने अक्सर अपनी गतिविधियों को उत्पादों के एक समूह के आसपास व्यवस्थित किया है, जिनमें से कुछ एकल उत्पादों से अलग, पारंपरिक कौशल से विकसित किए गए हैं। अधिकांश एसएचजी उद्यमों को अपने दम पर शुरू से अंत तक परिचालन करना पड़ता है और समूहकों से बहुत कम समर्थन मिलता है। वे एसएचजी उद्यम जो स्थापित विपणन मंचों से जुड़ सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्षमताएँ सफलता का एक प्रमुख घटक हैं। यदि क्षमताएं पारंपरिक व्यवसायों पर आधारित हों तो बेहतर है, और यदि ऐसी क्षमताएं उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य अनूठी उत्पादन क्षमताओं को हासिल करने की आवश्यकता है।

मामला अध्ययनों में पाया गया कि मन की बात संबोधन के बाद एसएचजी सदस्यों के बीच प्रेरणा के स्तर में वृद्धि हुई है। एसएचजी सदस्यों की सामाजिक मान्यता और समर्थन आधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मन की बात संबोधन के बाद एसएचजी सदस्यों ने व्यक्तिगत और समूह में वित्तीय मजबूती का अनुभव किया। इससे कुछ एसएचजी की गतिविधियों पर कई गुना प्रभाव पड़ा है, खासकर उनकी जो एक क्लस्टर में काम कर रहे थे, इस प्रकार उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिली, जिनकी पहुंच नहीं थी।

मुख्य शब्द: मन की बात, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म उद्यम, सामाजिक पूंजी, उत्पादक समूह।

---

*सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

**महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

***एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

****अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

प्रस्तावना

पिछले 10 वर्षों में भारत ने एक विकसित राष्ट्र, 'विकसित भारत' बनने के लक्ष्य के साथ कम विकसित देश से मध्यम आय वाले देश की ओर बढ़ते हुए उल्लेखनीय प्रगति देखी है। यह प्रगति 'सबका साथ-सबका विश्वास-सबका विकास' की अवधारणा पर आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है और 2022 में वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान से आगे बढ़कर यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गई है।

हालाँकि देश के बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास देश की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारकों में से एक है, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसे मिशनों ने भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वृद्धि और विकास की यह तेज़ गति न केवल भारत की शासन क्षमता पर निर्भर करती है, बल्कि भारत के विकास पदाधिकारियों की नवीनीकृत ऊर्जा एवं अभियान और नए भारत के दृष्टिकोण और मिशन के साथ उनके संरेखण पर भी निर्भर करती है। इसके बावजूद, सवाल उठते रहे हैं कि क्या यह वृद्धि समान रूप से वितरित है। इसे अक्सर अमीरों का पक्ष लेते देखा जाता है। हालाँकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय में वृद्धि हुई है, लेकिन जब आर्थिक विकास का लाभ उठाने की बात आती है तो ग्रामीण भारत पीछे छूटता हुआ प्रतीत होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास का बड़ा अवसर मिलता है।

विकास कार्यकर्ताओं को उनके दृष्टिकोण को समझने और लोगों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 से नियमित रूप से मन की बात (एमकेबी) रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में वे देश के कोने-कोने से बदलाव के प्रेरक उदाहरण पेश करते हैं। यह प्रपत्र श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मन की बात संबोधन में उल्लिखित ग्रामीण परिवर्तन के कुछ मामलों का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय मीडिया में छपने के बावजूद ऐसे अकादमिक शोध की कमी है जो इन मामलों की सफलता के कारकों का पता लगाता हो। यह प्रपत्र भारत की गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उद्यमशीलता कार्यों पर गौर करता है, जो मन की बात संबोधन में शामिल हुए हैं।

साहित्य की समीक्षा

ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एसएचजी एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, क्योंकि वे ग्रामीण महिलाओं के लिए पूंजी और ऋण तक पहुंचने का एक प्रभावी तरीका हैं। छोटे और सूक्ष्म उद्यम कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लाखों लोगों के लिए आय और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। स्वयं-सहायता समूहों को इन छोटे व्यवसायों के विकास का समर्थन करने के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें संसाधनों को एकत्रित करने और व्यवसाय शुरू करने से जुड़े जोखिम को साझा करने का अवसर मिलता है।

समूह सामंजस्य:

समूह सामंजस्य आम तौर पर समानांतर तथा उर्ध्व नेटवर्क पर आधारित होता है (सेवर्ट और एस्ट्राडा, 2015)। समानांतर समूहों और साथियों से युक्त एसएचजी का समानांतर नेटवर्क उनके बीच सामंजस्य बढ़ाने में सहायक था। इस बीच, उर्ध्व नेटवर्क ने सदस्यों को बैंकों और संघों से वित्तीय पूंजी तक पहुंचने और सरकारी संस्थानों की मदद से बेहतर मानव पूंजी विकसित करने में मदद की। सबसे विशेष रूप से, आपसी समर्थन, समूह संपार्श्विक, पेशेवर अनुशासन और सदस्यों तथा संस्थानों के बीच विश्वास में वृद्धि के कारण सामाजिक पूंजी में उल्लेखनीय सुधार देखा गया (अलरेफ़ेई और अन्य, 2022)।

नेतृत्व:

प्रमुख एसएचजी पदाधिकारियों के बीच नेतृत्व गुणों को समूह की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। अच्छा नेतृत्व समूह की गतिविधियों के लोकतांत्रिक प्रबंधन में योगदान देता है जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर संस्थागत स्थिरता और वित्तीय प्रदर्शन होता है (सुप्रभा के.आर., 2014)। सदस्यों की विशेषताओं और क्षमताओं तथा परिवार और समूह के भीतर उनकी स्थिति के अलावा, कुछ बाहरी कारक भी एसएचजी के भीतर नेताओं के उद्भव में योगदान करते हैं जैसे औपचारिक संस्थानों के नियम और कानून और सरकारी नीतियां (योक और चेसलर, 1985)। नेतृत्व विविधीकरण एसएचजी के अस्तित्व और स्थिरता में अत्यधिक योगदान देता है (विट तथा अन्य, 2002)। नेतृत्व पर समय-समय पर प्रशिक्षण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने में प्रभावी है, क्योंकि नेतृत्व का अनुभव न केवल आत्मविश्वास में सुधार करता है बल्कि महिलाओं के जीवन में प्रमुख निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है; जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने और आय स्रोतों में विविधता लाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (वेरे और किमारू-मुचाई, 2021)।

आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक परिणाम:

स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी का रोजगार के अवसरों के निर्माण, आय सृजन और इन समूहों की महिला सदस्यों के लिए प्रबंधन कौशल के विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जो सभी आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े हैं। इसके अलावा, इन महिलाओं को सामाजिक रूप से मान्यता मिली है और वे अपने एसएचजी के माध्यम से प्राप्त क्षमता और तकनीकी ज्ञान के कारण कई सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम हुई हैं (शर्मा और जौहरी, 2020)। स्व सहायता समूह द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों का उनके सदस्यों के परिवारों की बढ़ी हुई आय और बेहतर व्यय पैटर्न पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, ये व्यवसाय सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमों से पूरक आय प्राप्त हुई तो उनके व्यय पैटर्न में काफी सुधार हुआ (सिंह एवं अन्य, 2013)।

दुनिया भर में यह देखा गया है कि जब महिलाएं शामिल होती हैं तो परिवार अधिक प्रभावी ढंग से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने से पहले बचत करने और सुरक्षा बनाने में सक्षम होते हैं। गरीबी कम करने में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारक है, हालाँकि यह एकमात्र कारक नहीं है (डाइनिंगर और लियू, 2013)। शोध से पता चला है कि गरीबी को कम करने और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाने से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

विपणन:

स्वयं सहायता समूहों में विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करके बड़े ग्राहकों तक पहुंचने और अपना स्वयं का बाजार बनाने की क्षमता है। हालाँकि, उनकी सफलता अक्सर कुछ कारकों से बाधित होती है। इनमें उनके सदस्यों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, आधुनिक विपणन तकनीकों का अपर्याप्त ज्ञान, वितरण चैनलों तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त उत्पादन सुविधाएं और गुणवत्ता नियंत्रण उपाय, विपणन और ब्रांडिंग पद्धतियों का अभाव, प्रचार तकनीकों की कमी, और अनुचित मूल्य निर्धारण तकनीक शामिल हैं (जोस और अन्य, 2019)।

अनुसंधान अध्ययनों ने अपने उत्पादों के विपणन में स्वयं सहायता समूहों की भेद्यता पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो उनकी पहुंच और लाभप्रदता बढ़ाने के प्रमुख कारक हैं। दृश्यमान समस्या समूहों को लाभ समूहों में बदलने के लिए, शोध में एसएचजी की कार्यक्षमता पर उचित ध्यान देने, बाजार तक पहुंच प्रदान करने, मध्यस्थों को शामिल करने और सरकारी निकायों से वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया गया है (चक्रवर्ती तथा अन्य, 2022)।

सामाजिक उद्यमिता:

सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थानों से महिला उद्यमियों को मिलने वाले समर्थन का महिला उद्यमिता के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (अग्रवाल एवं लेंका, 2016)। इसी संदर्भ में, एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि सरकार से आर्थिक सहायता, उद्यमिता गतिविधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण महिला उद्यमियों के विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं (कपूर, 2019)।

हालाँकि बचत और किफायती गतिविधियों और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए बैंक वित्त के साथ जुड़ने के मामले में प्रगति हुई है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए इन एसएचजी की क्षमता को पर्याप्त रूप से महसूस नहीं किया गया है। भारत में एसएचजी पर अध्ययन से सकारात्मक सामाजिक परिणाम सामने आए, जैसा कि बेहतर सामाजिक पूंजी और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ बेहतर पोषण संकेतकों से पता चलता है। सामाजिक पूंजी के पृथक्करण से पता चलता है कि सबसे प्रमुख परिवर्तन महिलाओं की बचत करने, गाँव में स्वतंत्र रूप से घूमने और दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता में थे।

देश के कुछ हिस्सों में, स्व सहायता समूह ऐसी भूमिकाएँ निभाने लगे हैं जो आजीविका और व्यावसायिक संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं (मिनिमोल, 2020)। इसका तात्पर्य उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और एसएचजी सदस्यों को उनकी उद्यमशीलता का समर्थन करने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्मुख करने की आवश्यकता है।

हाल के दशक में, महिलाओं की सामाजिक उद्यमिता एक अवधारणा है जो अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। यह इस विचार पर केंद्रित है कि महिलाएं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अपने उद्यमशीलता कौशल का उपयोग कर सकती हैं। इसमें ऐसे व्यवसाय बनाना शामिल है जो महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, शिक्षा और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं, और पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान उद्योगों में महिलाओं के लिए नौकरियां और अवसर पैदा करते हैं।

समूह-आधारित मॉडल का मुख्य लाभ महिलाओं के बड़े समूहों को तुरंत संसाधन, जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता प्रतीत होता है। भले ही समूहों के माध्यम से किए गए कार्यक्रम विविध थे, फिर भी उनके परिणामस्वरूप आमतौर पर समूह के उद्देश्य से सीधे जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की भलाई में थोड़ा सुधार हुआ। उदाहरण के लिए, आर्थिक और वित्तीय समूहों (माइक्रोक्रेडिट समूह, बचत समूह और स्वयं सहायता

समूह) ने महिलाओं को वित्तीय संसाधनों (क्रेडिट या संपत्ति) तक पहुंच प्रदान करके आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाई (डियाज़-मार्टिन और अन्य, 2023)।

महिलाओं के लिए सामाजिक उद्यमिता में ऐसे संगठनों का निर्माण भी शामिल हो सकता है जो लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करके, महिलाएं अपने समुदायों पर एक शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें सामाजिक उद्यम में प्रवेश करने का अवसर दिया है। इन उद्यमों को सफल बनाने के लिए, उन्हें सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना होगा और सख्त वित्तीय प्रतिबंधों का पालन करना होगा। अंतिम लक्ष्य मौजूदा प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलकर, लोगों के एक विशिष्ट समूह के जीवन में सुधार करना है। किसी उद्यम की लागत कम होनी चाहिए क्योंकि इससे अधिक लोगों को लाभ होता है ताकि जैसे-जैसे इसका विस्तार हो, यह सरकारी वित्त पोषण पर कम निर्भर हो सके (ऑस्बर्ग और मार्टिन, 2015)।

साहित्य सर्वेक्षण से पता चला है कि कठिनाइयों के बावजूद स्वयं सहायता समूह बचत से उद्यमिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक सफल सूक्ष्म-उद्यम चलाने के लिए समूह सामंजस्य, नेतृत्व गुण, समर्थन संरचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, विपणन कौशल, नेटवर्किंग और उद्यमशीलता की भावना बहुत आवश्यक है। कई मोर्चों पर कठिनाई और खामियों के बीच, कुछ एसएचजी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। उन स्वयं सहायता समूहों पर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं गया। उनके मन की बात संबोधन में उनका उल्लेख मिला। मन की बात संबोधनों से संकेत लेते हुए, यह प्रपत्र एसएचजी की सफल उद्यमशीलता गतिविधियों के पीछे के कारकों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है, जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री के मन की बात संबोधनों में भी पाया गया है।

अनुसंधान क्रियाविधि

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) की अध्ययन टीमों ने एक समान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मामले का अध्ययन किया। अनुसंधान का उद्देश्य निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर देना था:

(i) क्या मन की बात में स्व सहायता समूह द्वारा ग्रामीण परिवर्तन की पहल का उनके आसपास के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की ऐसी पहलों पर मन की बात के प्रभाव का परिमाण

ग्रामीण परिवर्तन पहल के प्रभाव का आकलन करने के लिए, स्व सहायता समूह पर छह मामलों को जानबूझकर चुना गया था जिनका उल्लेख प्रधान मंत्री के मन की बात संबोधन में किया गया था। वे नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1: एमकेबी में उल्लिखित स्व सहायता समूह मामलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जिला	स्थान	एपिसोड और तारीख	एमकेबी में उल्लिखित स्व सहायता समूह की गतिविधियाँ
1.	बिहार	मुजफ्फरपुर	आनंदपुर	53वां एपिसोड - 24 फरवरी, 2019	स्व सहायता समूह - किसान चाची
2.	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	कादीपुर	60वां एपिसोड - 29 दिसंबर, 2019	स्व सहायता समूह - चप्पल बनाने की इकाई
3.	असम	बारपेटा	भालुकी	67वां एपिसोड - 26 जुलाई, 2020	स्व सहायता समूह - बांस शिल्प और पानी की बोतलें
4.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	चिचगांव	73वां एपिसोड - 31 जनवरी, 2021	स्व सहायता समूह - चावल मिल
5.	तमिलनाडु	तंजावुर	तंजावुर	89वां एपिसोड - 29 मई, 2022	स्व सहायता समूह - खिलौने और हस्तशिल्प कियॉस्क
6.	ओडिशा	केंद्रपाड़ा	गुलनगर	98वां एपिसोड - 26 फरवरी, 2023	स्व सहायता समूह - अपशिष्ट से धन पहल
स्रोत: https://www.pmindia.gov.in/en/mann-ki-baat/					

अध्ययन टीमों ने मामले के अध्ययन के लिए साक्ष्य तैयार करने के लिए एक समान कार्यप्रणाली को शामिल करते हुए एक व्यापक अनुसंधान प्रोटोकॉल अपनाया। इस प्रोटोकॉल में मुख्य सूचनादाता साक्षात्कार, केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी), क्षेत्र अवलोकन और हस्तक्षेप के दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से डेटा संग्रह शामिल था। प्रतिक्रियाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एमकेबी ग्रामीण परिवर्तन पहल के डेस्क अध्ययन के आधार पर टीमों द्वारा प्रश्नावली तैयार की गईं। डेटा संग्रह चरण के बाद, टीमों को एक साथ जानकारी दी गई और कारण-प्रभाव संबंधों, पैटर्न के गठन और तर्क मॉडल के विकास के आधार पर एक गुणात्मक मामला विश्लेषण ढांचा विकसित किया गया। एसएचजी सूक्ष्म-उद्यम पहल पर जोर देते हुए व्यक्तिगत मामले की रिपोर्टों का क्रॉस-केस तुलना परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया गया।

स्व सहायता समूह मामले का अध्ययन: बचत से उद्यमिता की ओर बदलाव:

83.4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों और 8 करोड़ सदस्यों के साथ, ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों का प्रसार पर्याप्त रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों को एसएचजी से संतृप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रत्येक ग्रामीण गरीब महिला एसएचजी का हिस्सा बन सके। स्व-रोज़गार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला से उभरे इस आंदोलन को अपनी बचत और बचत गतिविधियों में काफी सफलता मिली है, जिसमें एसएचजी सदस्यों ने बैठक कर अपनी छोटी-छोटी बचत को आपस में उधार देने के लिए एकत्रित किया, जिससे सूदखोर साहूकार दूर रहे। हालाँकि इनमें से बड़ी संख्या में एसएचजी छोटी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपनी बचत को बढ़ाने के लिए बैंक वित्त से जुड़ने में सक्षम हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए ऐसे छोटे एसएचजी सदस्य व्यवसायों की क्षमता सीमित है। यह एसएचजी

के व्यापक नेटवर्क के बावजूद है जो पूरे देश में काफी हद तक स्थिरता बनाए रखते हुए आवधिक बैठकों और खातों जैसी संस्थागत प्रक्रियाओं का पालन करता है। इसे देखते हुए, एसएचजी के व्यापक दायरे से सूक्ष्म उद्यमों का उद्भव सीमित हो गया है, जिससे एसएचजी सदस्यों के बीच उद्यमशीलता की भावना को जगाने की आवश्यकता है, इसके अलावा उन्हें उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्मुख करने की आवश्यकता है जो उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एसएचजी पर अपने विभिन्न मन की बात संबोधनों में यही बात कही थी, जब उन्होंने एसएचजी सदस्यों की उद्यमशीलता की भावना, समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके द्वारा लाए गए नवाचारों को पहचाना था। एसएचजी महिला समूह का मितव्ययिता से सूक्ष्मउद्यम की ओर बढ़ना पूंजी, साझा संसाधनों और एकत्रित ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। इस बदलाव में न केवल व्यवसाय, वित्त, विपणन और संचालन की बुनियादी बातें सीखना शामिल है, बल्कि ग्राहक सेवा, समस्या-समाधान और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करना भी शामिल है।

अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री ने एसएचजी सदस्यों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मक विचारों पर प्रकाश डाला। एनआईआरडीपीआर टीमों द्वारा विकसित विस्तृत केस अध्ययन रिपोर्टों पर आधारित मामलों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद एक क्रॉस-केस तुलना की गई है, जिसमें अध्ययन किए गए एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों की समानताएं, विविधताएं तथा सफलता कारक और प्रधान मंत्री के मन की बात में उल्लिखित निष्कर्ष के प्रभाव सामने लाए गए हैं।

मामला 1: तंजावुर के गुड़िया विक्रेता: गरीबी से समृद्धि तक परिवर्तन की यात्रा

29 मई 2022 (89वें एपिसोड) को, प्रधान मंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित सामानों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तंजावुर प्रशासन द्वारा स्थापित हस्तशिल्प कियोस्क की प्रशंसा की। महिला स्वयं सहायता समूह की "थारागैगल कैविनाई पोरुतकल विरपनाई अंगदी" पहल फरवरी 2022 में शुरू की गई थी।

इस समूह का मुख्य लक्ष्य एसएचजी महिलाओं को उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से अपना सामान सीधे ग्राहकों को बेचने में मदद करना था। हालाँकि निर्माता समूह एसएचजी विभिन्न हस्तशिल्प और कलाकृतियाँ बनाने में अच्छे हैं, लेकिन उनके माल का विपणन एक समस्या थी। इस पृष्ठभूमि में, तंजावुर जिले के जिला प्रशासन ने समूह को एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए एक कियोस्क (रूर्बन क्लस्टर के तहत) की स्थापना की सुविधा प्रदान की और अब ये एसएचजी कियोस्क एसएचजी उत्पादक समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं।

इस पर प्रधानमंत्री का ध्यान तब गया जब विक्रेता एसएचजी ने भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग वाली तंजावुर गुड़िया और उत्पाद प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे। मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री की इस सराहना के बाद कियॉस्क ने जनता, अधिकारियों और बैंकरों का ध्यान आकर्षित किया। इससे बिक्री और उसके बाद के प्रभाव में बड़ा अंतर आया। मन की बात संबोधन के तुरंत बाद, तंजावुर में रेलवे स्टेशन ने 'वन स्टेशन' 'एक उत्पाद' के तहत एक दुकान के लिए जगह की पेशकश की। 10 महीनों के दौरान अन्य एसएचजी सदस्यों को शामिल करके तीन और दुकानें अस्तित्व में आईं और वर्तमान में, समूह पांच दुकानें चलाता है। दस उत्पादक समूह तेजी से बढ़कर 22 हो गए। इसके बाद, लगभग एक साल में उत्पादन और बिक्री बढ़कर कुल मिलाकर 55 लाख रुपये हो गई। विक्रेता और निर्माता एसएचजी के प्रयासों के इस सामंजस्य ने एक सकारात्मक विकास चक्र बनाया और उनके बीच एक बंधन बनाया।

बैंकरों ने समूहों को उनके निवेश के लिए बिना गारंटी के ऋण देकर समर्थन दिया और इन ऋणों को तुरंत चुका दिया गया। समूहों के समूह ने अब तंजावुर गुड़िया, नृत्य गुड़िया, तंजावुर प्लेट, जूट बैग, रेक्सिन बैग,

टेराकोटा कलाकृतियाँ, फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद और साबुन जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण - मामला 1

शक्तियाँ

- अच्छी तरह से विकसित सामाजिक नेटवर्क हों;
- वितीय संसाधनों तक पहुंच;
- लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की क्षमता;
- उत्पादन और संचालन की कम लागत;
- बेहतर आत्म-सम्मान और अन्य सकारात्मक परिणाम
- पारंपरिक उत्पादों का मूल्यवर्धन
- एमकेबी कवरेज से लाभान्वित
- सरकार से समर्थन

कमजोरियाँ

- समूह के सदस्यों का नेतृत्व उद्यमशील सदस्य द्वारा किया जाता है;
- व्यवसाय विकास सेवाओं तक सीमित पहुंच;
- कार्यस्थलों में कमी;
- बड़े बाजारों तक पहुंच की कमी से उच्च लाभ की संभावना कम हो जाती है; और
- बाज़ार से विकास में बाधाएँ

अवसर

- एसएचजी अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं;
- एसएचजी उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है;
- नवीन उत्पाद बनाने की क्षमता;
- सशक्तिकरण की भावना और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास;
- पूंजी, बाज़ार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि; और
- नेटवर्किंग और परामर्श अवसरों तक पहुंच में वृद्धि
- सामाजिक उद्यमशीलता के अवसरों में वृद्धि
- ऑनलाइन मार्केटिंग

खतरें

- कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव;
- कम लागत वाली नकल से बढ़ी प्रतिस्पर्धा;
- उद्यमी के हटने से समूह में अव्यवस्था आ सकती है
- उद्यम का अनुचित विनियमन

सकारात्मक **नकारात्मक**

मामला 2: बांस जैसा लचीला: असम के भालूकी बांस क्लस्टर की कहानी

मन की बात के 37वें और 67वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने बांस से बने हस्तशिल्प के महत्व पर प्रकाश डाला। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) ने असम के बारपेटा जिले के भालुकी सलमारा जैसे गांवों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच क्लस्टर पहल शुरू की। इसने बांस आधारित आजीविका गतिविधियों के माध्यम से एसएचजी सदस्यों के आर्थिक सशक्तिकरण को सक्षम बनाया।

2019-20 में, एएसआरएलएम ने भालुकी सलमारा को बांस-आधारित हस्तशिल्प गतिविधियों का केंद्र घोषित किया और शिल्प में शामिल एसएचजी को समर्थन देने के लिए गांव को चुना। क्लस्टर-आधारित बांस शिल्प गतिविधियों के माध्यम से एसएचजी महिला कारीगरों का आर्थिक सशक्तिकरण शुरू किया गया। एएसआरएलएम और त्रिपुरा बांस और बेंत विकास केंद्र (टीआरआईबीएसी) के बीच एक समझौता किया गया, जिसके परिणामस्वरूप टीआरआईबीएसी ने लगभग 200 एसएचजी सदस्यों से गठित 21 एसएचजी के बांस-आधारित क्लस्टर के रूप में गांव के विकास की सुविधा प्रदान की।

एएसआरएलएम ने समूहों को कच्चे माल प्राप्त करने और उपकरण खरीदने जैसे परिचालन खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए वित्तीय और बचत सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरस मेले में कई कारीगरों ने भाग लिया। उन्होंने मेघालय में खासी एम्पोरियम, असम में पूरबश्री और कलाक्षेत्र जैसे सरकारी आउटलेट्स और गुवाहाटी, मुंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, शिल्पराम्म क्राफ्ट विलेज, हैदराबाद और उससे आगे में बेंत और बांस उत्पादों के निजी वाणिज्यिक आउटलेट्स तक पहुंचने का भी प्रयास किया। वे दिल्ली स्थित एक एक्सपोर्ट हाउस की मदद से 2021-22 में मध्य पूर्व के लिए नौ लाख रुपये के निर्यात ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम थे। यह खेप मेड इन इंडिया स्टिकर के साथ भेजी गई थी। वे अब तीन लाख रुपये का एक और ऑर्डर पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

<u>एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण - मामला 2</u>

शक्तियाँ

- अच्छी तरह से विकसित सामाजिक नेटवर्क हैं;
- वित्तीय संसाधनों तक पहुंच;
- लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की क्षमता;
- उत्पादन और संचालन की कम लागत;
- बेहतर आत्म-सम्मान और अन्य सकारात्मक परिणाम
- सरकार से समर्थन

कमजोरियाँ

- व्यवसाय विकास सेवाओं तक सीमित पहुंच;
- कार्यस्थलों में कमी;
- बड़े बाजारों तक पहुंच की कमी से उच्च लाभ की संभावना कम हो जाती है; और
- बाज़ार से विकास में बाधाएँ

अवसर	**खतरें**
• एसएचजी अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं; • एसएचजी उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है; • नवीन उत्पाद बनाने की क्षमता; • सशक्तीकरण की भावना और आत्मविश्वास में वृद्धि; • पूंजी, बाज़ार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि; • सामाजिक उद्यमशीलता के अवसरों में वृद्धि; • ऑनलाइन मार्केटिंग	• कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव; • कम लागत की सीमाओं से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि;
सकारात्मक	**नकारात्मक**

मामला 3: अपशिष्ट से संपत्ति: श्रीमती कमला मोहराना की प्रेरक कहानी

26 फरवरी 2023 को प्रधान मंत्री के मन की बात के 98वें एपिसोड के बाद, श्रीमती कमला मोहराना और एसएचजी के लिए चीजें पूरी तरह से अलग मोड़ ले गईं। थानापति शक्ति दल, एसएचजी, का गठन 2002 में मिशन शक्ति के समर्थन से, शुरुआत में 17 सदस्यों के साथ किया गया था। हालाँकि एसएचजी के सात सदस्य वृद्धावस्था में चले गए, अन्य लोगों ने समूह के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कमला के साथ प्रयास किया। 2014 में, श्रीमती कमला मोहराना ने खैराबाद के स्थानीय घरों और कचरा स्थलों से अपशिष्ट प्लास्टिक पाउच और बैग इकट्ठा करने की पहल की; और अपशिष्ट से संपत्ति बनाने की पहल शुरू की। उनके नक्शेकदम पर चलते हुए पांच अन्य सदस्यों ने यह गतिविधि शुरू की।

यह अभिनव एसएचजी पहल जो अब तक नौ वर्षों तक अज्ञात थी, फरवरी 2023 के प्रधान मंत्री के मन की बात संबोधन के बाद सामने आई। इसके बाद, जिला प्रशासन ने ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी (ओआरएमएएस), मिशन शक्ति के सक्रिय सहयोग से, एक उत्पादक समूह का गठन किया, जिसमें 23 सदस्य शामिल थे और संस्थागत निर्माण, क्षमता निर्माण और उपकरण समर्थन लागत के लिए उत्पादक समूह को 2.04 लाख रुपये मंजूर किए। भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफटी), कोलकाता के सहयोग से डिजाइन विकास प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन डिजाइन विकास प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए उनके गांव में एक खाली स्कूल भवन उपलब्ध कराने के लिए आगे आया। कुल मिलाकर, एसएचजी के लिए अब स्थिति काफी अच्छी है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण - मामला 3

शक्तियाँ

- अच्छी तरह से विकसित सामाजिक नेटवर्क हैं;
- लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की क्षमता;
- उत्पादन और संचालन की कम लागत;
- कम लागत वाले कच्चे माल तक पहुंच
- बेहतर आत्म-सम्मान और अन्य सकारात्मक परिणाम
- कम लागत वाला कच्चा माल
- नवीन उत्पाद बनाना
- अपशिष्ट को संपत्ति में परिवर्तित करना
- एमकेबी कवरेज से लाभान्वित
- मजबूत समूह सामंजस्य

कमजोरियाँ

नये बाज़ारों में विस्तार;

समूह के सदस्यों का नेतृत्व उद्यमशील सदस्य द्वारा किया जाता है;

व्यवसाय विकास सेवाओं तक सीमित पहुंच;

उद्योग नेटवर्क तक सीमित पहुंच;

बाज़ारों और ग्राहकों तक सीमित पहुंच;

पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रबंधन ज्ञान का अभाव;
सीमित प्रौद्योगिकी और आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं का ज्ञान; और

अवसर

- एसएचजी अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं;
- एसएचजी उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है;
- नवीन उत्पाद बनाने की क्षमता;
- सशक्तीकरण की भावना और आत्मविश्वास में वृद्धि;
- पूंजी, बाज़ार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि; और
- नेटवर्किंग और परामर्श अवसरों तक पहुंच में वृद्धि
- सामाजिक उद्यमशीलता के अवसरों में वदधि

खतरें

उत्पादन का निम्न स्तर
अपशिष्ट-से-संपत्ति उत्पादों के लिए बाजार का अभाव
सरकारी सहायता वापस लेना

सकारात्मक **नकारात्मक**

मामला 4: सम्मान अर्जित करना: कादीपुर के चप्पल बनाने वाले स्वयं सहायता समूहों की कहानी

29 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन के बाद कादीपुर गांव की चप्पल बनाने वाली इकाई सुर्खियों में आई। 2017 में कुंभ मेले की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री महिलाओं के एक समूह द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प और मोमबत्तियाँ बेचने वाले एक स्टाल पर गए। उनकी सादगी, प्रेरणा और कड़ी मेहनत ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन का सहयोग लेने के लिए निर्देशित किया। वह घटना गेम चेंजर साबित हुई और कादीपुर की इन महिलाओं की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हुई।

अनुसूचित जाति से स्नातक श्रीमती पल्लवी परमार उन कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं, जिन्होंने कादीपुर में उद्यमिता को अपनाया। सबसे पहले, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हस्तशिल्प बनाकर आय उत्पन्न करने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने गाँव के लाभ के लिए एक नए कार्य या उद्यम पर विचार किया, और फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसकी सभी को आवश्यकता थी। बहुत विचार-विमर्श के बाद, उन्होंने तय किया कि चप्पल बनाना सबसे अच्छा विकल्प है। निर्णय लेने के बाद इन महिलाओं ने पल्लवी की मदद से यूट्यूब से चप्पल बनाने के लिए सभी जरूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने चप्पल बनाने वाली इकाई स्थापित करने के लिए जिला अधिकारियों को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन ने दो लाख रुपये दिए, जिसका उपयोग उन्होंने एक इकाई स्थापित करने के लिए किया, 1.5 लाख रुपये कच्चे माल में निवेश किया और पचास हजार रुपये किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए अपने पास रखे।

प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात संबोधन में उल्लेख किए जाने के बाद, महिलाओं के चप्पल बनाने वाले समूह ने केवल तीन वर्षों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिससे उनकी अपनी ग्राम पंचायत और पड़ोसी क्षेत्रों की महिलाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिली। स्कूली छात्रों, पुलिस कर्मियों और सरकारी अधिकारियों ने चप्पलों के थोक ऑर्डर दिए। उन्होंने 60 से 80 रुपये तक की कीमत पर 24,350 जोड़ी चप्पलें बेचीं और 2 लाख रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाया।

इन महिलाओं के प्रति सम्मान इतना बढ़ गया कि उनके अनुरोध पर सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को अन्य स्थानों से जोड़ने वाली ऐसी सड़कें बनवाई गईं जो पहले अस्तित्व में नहीं थीं। ये सड़कें अब गांव में शादी की बारातों को वंचित अनुसूचित जाति के घरों तक पहुंचने में सक्षम बना रही हैं, जिनमें इस समूह की अधिकांश एसएचजी महिलाएं शामिल थीं। इस प्रकार, मन की बात के उल्लेख ने उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाया और उन्हें समुदाय में सम्मान दिलाया।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण - मामला 4

शक्तियाँ	**कमजोरियाँ**
• अच्छी तरह से विकसित सामाजिक नेटवर्क और सरकारी अधिकारियों के साथ नेटवर्क हो; • वित्तीय संसाधनों तक पहुंच; • लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की क्षमता; • उत्पादन और संचालन की कम लागत; • बेहतर आत्म-सम्मान और अन्य सकारात्मक परिणाम • सरकार से समर्थन	• समूह के सदस्यों का नेतृत्व उद्यमशील सदस्य द्वारा किया जाता है; • व्यवसाय विकास सेवाओं तक सीमित पहुंच; • उद्योग नेटवर्क तक सीमित पहुंच; • बाज़ारों और ग्राहकों तक सीमित पहुंच; • पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रबंधन ज्ञान का अभाव; सीमित प्रौद्योगिकी और आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं का ज्ञान; और • खंडित आपूर्ति श्रृंखला • कार्यक्षेत्र में कमी • कम व्यावसायिक कौशल; • बड़े बाजारों तक पहुंच की कमी से उच्च लाभ की संभावना कम हो जाती है
अवसर	**खतरे**
• एसएचजी अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं; • एसएचजी उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है; • नवीन उत्पाद बनाने की क्षमता; • सशक्तीकरण की भावना और आत्मविश्वास में वृद्धि; • पूंजी, बाज़ार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि; • सामाजिक उद्यमशीलता के अवसरों में वृद्धि	• जोखिम और दृश्यता की कमी; • उत्पादन का निम्न स्तर; • उद्यमी के हटने से समूह में अव्यवस्था आ सकती है
सकारात्मक	**नकारात्मक**

मामला 5: किसान चाची: श्रीमती राजकुमारी देवी की सफलता की कहानी

प्रधान मंत्री ने 24 फरवरी 2019 के अपने मन की बात कार्यक्रम के 53वें एपिसोड में प्रेरणादायक सफलता की कहानी का आभार प्रकट किया और श्रीमती राजकुमारी देवी द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया, जिन्हें प्यार से 'किसान चाची' कहा जाता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम ने राजकुमारी देवी को उन्नत कृषि पद्धतियों की ओर उन्मुख किया और उन्होंने अपनी भूमि पर पपीता और जैतून की खेती शुरू की। वह अपनी साइकिल पर घर-घर जाकर अपनी उपज बेचती थीं। बाद में, उन्होंने केवीके सरैया में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जहां उन्हें कृषि-आधारित मूल्य-संवर्धन गतिविधियों में

प्रशिक्षित किया गया। समय के साथ, उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता वाले अचार बनाना शुरू कर दिया जो अब न केवल बिहार में बल्कि राज्य की सीमाओं से परे भी प्रसिद्ध हैं।

किसान चाची, जिन्होंने महिलाओं को एसएचजी बनाने के लिए प्रेरित किया, अब एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में काम करती हैं, जो पापड़, जैम और जेली जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा अचार बनाने के लिए आनंदपुर गांव और उसके आसपास की महिलाओं को रोजगार देती हैं। वर्तमान में, किसान चाची द्वारा गठित ज्योति जीविका एसएचजी की 18 महिलाएं मौसमी उत्पादों का मूल्य संवर्धन करती हैं। किसान चाची इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री का प्रबंधन करती हैं। उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए श्रीमती राजकुमारी देवी को 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण - मामला 5

शक्तियाँ

- प्रेरित कार्यबल
- घरेलू वस्तुओं का उत्पादन और व्यंजनों का ज्ञान
- किसान चाची का ब्रांड नाम
- मजबूत नेतृत्व
- सरकार सहित हितधारकों से समर्थन
- अच्छी तरह से विकसित सामाजिक नेटवर्क हैं;
- वित्तीय संसाधनों तक पहुंच;
- बेहतर आत्म-सम्मान और अन्य सकारात्मक परिणाम
- सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का लाभ उठाने की क्षमता

कमजोरियाँ

- कच्चे माल की उपलब्धता की मौसमी स्थिति
- नेतृत्व का कोई दूसरा चरण नहीं
- समूह के सदस्यों का नेतृत्व उद्यमशील सदस्य द्वारा किया जाता है;
- पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रबंधन ज्ञान का अभाव;
- सीमित प्रौद्योगिकी और आधुनिक व्यावसायिक पद्धतियों का ज्ञान;
- खंडित आपूर्ति श्रृंखला
- कार्यक्षेत्र में कमी

अवसर

- अतिरिक्त सदस्यों की भागीदारी से उत्पादन में वृद्धि
- उत्पादन प्रणाली में मशीनरी का उपयोग
- ऑनलाइन मार्केटिंग के रास्ते तलाशना
- घरेलू उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में बदलाव
- एसएचजी अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं;
- नवीन उत्पाद बनाने की क्षमता;
- पूंजी, बाज़ार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि; और
- नेटवर्किंग और सदस्यता अवसरों तक पहुंच में वृद्धि

खतरें

- बड़े उद्यमों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा;
- उद्यमी के हटने से समूह में अव्यवस्था आ सकती है
- एकल चरण नेतृत्व

सकारात्मक **नकारात्मक**

मामला 6: सहयोग से सामूहिक कार्य तक: चिचगांव की योग्यता आजीविका एसएचजी की यात्रा

31 जनवरी, 2021 को प्रसारित अपने 73वें "मन की बात" के दौरान, प्रधान मंत्री ने "योग्यता" एसएचजी समूह की प्रशंसा की, जिसने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिचगांव गांव में एक चावल मिल खोली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजीविका की सहायता से एसएचजी महिलाएं चावल मिल की मालिक बन गई हैं, जहां वे पहले दैनिक मजदूरी के लिए काम करती थीं। कोरोनोवायरस महामारी से पहले, योग्यता एसएचजी सदस्य एक छोटे पतवार और चक्की के साथ धान और हल्दी के प्रसंस्करण में भाग ले रहे थे। लॉकडाउन के दौरान कच्चे माल और परिवहन की कमी के कारण उनका परिचालन बाधित हुआ। 2020 में, योग्यता आजीविका एसएचजी समूह ने एक चावल मिल खरीदने और विस्तार करने के लिए एसएचजी की अपनी बचत से 60,000 रुपये के अलावा सामुदायिक निवेश निधि के 40,000 रुपये और 2,00,000 रुपये का नकद क्रेडिट ऋण जुटाया जिसे पहले एसएचजी सदस्यों में से किसी एक और उनके पति द्वारा छोटे पैमाने पर चलाया जा रहा था।

इन एसएचजी महिलाओं द्वारा किए गए प्रयास को एक अखबार ने प्रकाशित किया और इसे प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया, जिन्होंने इसे अपने मन की बात संबोधन में उल्लेख किया। इससे वे बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हो गए और उनके उद्यम को हर तरफ से समर्थन मिलना शुरू हो गया। अब ये महिलाएं कर्ज चुकाने के लिए काफी उत्सुक हैं और मुनाफे में से सिर्फ 250 रुपये दैनिक वेतन के रूप में लेती हैं। अब समूह ने धान की भूसी निकालने वाली चावल मिल से लेकर हल्दी और मिर्च प्रसंस्करण तक अपना व्यवसाय धीरे-धीरे बढ़ाया है।

इस समूह ने जो रास्ता अपनाया वह कम सफ़र वाला रास्ता है, जिसमें गरीब एसएचजी महिलाओं का एक समूह अपने समुदाय और खुद के लिए फायदे की स्थिति बनाने के लिए कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में एक असफल चावल मिल को बचाने के लिए आगे आया।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण - मामला 6

शक्तियाँ

- अच्छी तरह से विकसित सामाजिक नेटवर्क हैं;
- वित्तीय संसाधनों तक पहुंच; लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं;
- बेहतर आत्म-सम्मान और अन्य सकारात्मक परिणाम

कमजोरियाँ

- नये बाज़ारों में विस्तार;
- समूह के सदस्यों का नेतृत्व उद्यमशील सदस्य द्वारा किया जाता है;
- व्यवसाय विकास सेवाओं तक सीमित पहुंच;
- बाज़ारों और ग्राहकों तक सीमित पहुंच;
- पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रबंधन ज्ञान का अभाव;
- सीमित प्रौद्योगिकी और आधुनिक व्यावसायिक पद्धतियों का ज्ञान;
- खंडित आपूर्ति श्रृंखला;
- कम व्यावसायिक कौशल;
- उद्यम की मौसमीता

अवसर

- एसएचजी अपने सदस्यों को उनके व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं;
- नवीन उत्पाद बनाने की क्षमता;
- सशक्तीकरण की भावना और आत्मविश्वास में वृद्धि;
- पूंजी, बाज़ार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि; और
- नेटवर्किंग और सदस्यता अवसरों तक पहुंच में वृद्धि

खतरें

- कम लागत वाली नकल से बढ़ी प्रतिस्पर्धा;
- जोखिम और दृश्यता की कमी;
- उद्यमी के हटने से समूह में अव्यवस्था आ सकती है
- लाभप्रदता का अभाव
- मशीनरी का कम उपयोग
- प्राकृतिक आपदाएं

सकारात्मक **नकारात्मक**

क्रॉस-केस विश्लेषण

मन की बात के विभिन्न एपिसोड में उल्लेखित उपरोक्त सूक्ष्म-उद्यम मामलों के क्रॉस-केस अध्ययन के आधार पर, एसएचजी की उद्यमशीलता की सफलता के कई कारण सामने आए। क्लस्टर-आधारित एसएचजी उद्यम व्यक्तिगत उद्यमों की तुलना में अधिक सफल हैं। क्रॉस-केस विश्लेषण ने प्रत्येक मामला अध्ययन के एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण को भी आधार बनाया।

क्लस्टर विकास के लिए तंजावुर और भालुकी में एसएचजी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण छत्रपति द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण के समान है: "उद्यम निर्माण के लिए लोक-केंद्रित, प्रक्रिया-केंद्रित दृष्टिकोण, जो उनकी स्वदेशी प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता का दोहन करते समय स्थानीय समुदाय की बाधाओं को ध्यान में रखता है। " अनेक समूहों वाले उद्यम उन उद्यमों की तुलना में अधिक सफल होते हैं जो अकेले स्वयं सहायता समूहों पर आधारित होते हैं। अधिक सफल एसएचजी उद्यमों ने अपनी गतिविधियों को एक या अधिक विविध उत्पादों से अलग उत्पादों के समूह के आसपास व्यवस्थित किया है।

अधिकांश एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों ने अपने अस्तित्व के कम से कम छह वर्षों के बाद उत्पादन-आधारित गतिविधियों में कदम रखा क्योंकि एसएचजी ज्यादातर बचत और बचत गतिविधियों में शामिल होते हैं। एसएचजी उद्यमशीलता गतिविधि में शामिल अधिकांश महिलाएं मध्यम आयु वर्ग की हैं और उनकी कुल औसत आयु 39 वर्ष है। सभी एसएचजी उद्यमों ने एसएचजी सदस्यों की बचत सहित वित्त के विविध स्रोतों को आकर्षित किया। अध्ययन किए गए अधिकांश एसएचजी उद्यमों ने नेतृत्व-संचालित गतिविधि दिखाई, हालांकि समूह के अन्य सदस्यों को भी पर्याप्त लाभ हुआ। तालिका 2 इस प्रपत्र में अध्ययन किए गए एसएचजी की संगठनात्मक संरचना का अवलोकन देती है।

तालिका संख्या 2:

संगठनात्मक संरचना: एसएचजी का क्रॉस-केस विश्लेषण

क्रॉस केस संकलन	**तमिलनाडु - तंजावुर**	**असम - भालूकी**	**ओडिशा - गुलनगर**	**उत्तर प्रदेश - कादीपुर**	**बिहार - किसान चाची**	**मध्य प्रदेश - चिचगांव**
एसएचजी की प्रकृति	एसएचजी का समूह	एसएचजी का समूह	व्यक्तिगत एसएचजी	व्यक्तिगत एसएचजी	एसएचजी का समूह	व्यक्तिगत एसएचजी
समूह सामंजस्य	22 एसएचजी	21 एसएचजी - बांस आधारित गतिविधि क्लस्टर	एक एसएचजी	एक एसएचजी	36 एसएचजी	एक एसएचजी
नेतृत्व	नेतृत्व संचालित	सामूहिक गतिविधि	प्लास्टिक कचरे का पुन: उपयोग करने की व्यक्तिगत रुचि	नेतृत्व संचालित	नेतृत्व संचालित	नेतृत्व संचालित
वित्त के स्रोत	स्वयं की बचत, सीआईएफ और बैंक ऋण	स्वयं की बचत, सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ), बैंक ऋण, एनईडीएफआई, और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	स्वयं की बचत, सीआईएफ, जोखिम न्यूनीकरण निधि और बैंक ऋण	सीआईएफ और बैंक ऋण	स्वयं की बचत, सीआईएफ और बैंक ऋण	स्वयं की बचत, सीआईएफ और बैंक ऋण
उत्पादन की विविधता	तंजावुर गुड़िया, नृत्य गुड़िया, तंजावुर प्लेटें, जूट बैग, रेक्सिन बैग, टेराकोटा कलाकृतियाँ, गढ़वाले खाद्य उत्पाद और साबुन	ट्रे, पेन स्टैंड, वॉल फ्लावर पॉट, रिक्लाइनर, टेबल, चूड़ियाँ, हेयर क्लिप, हैंगिंग लैंप, टेबल लैंप, लेटरबॉक्स, टोकरी, मैगजीन होल्डर, कप और मग	टोकरियाँ, चटाइयाँ, मोबाइल होल्डर और सजावटी शिल्प वस्तुएँ	चप्पलें	अचार, पापड़, मशरूम, जैम और जेली	धान की भूसी
एसएचजी की दीर्घायु	9 वर्ष (2014)	9 वर्ष (2014)	2002 में गठित लेकिन 2014 से सक्रिय	6 वर्ष (2017)	9 वर्ष (2014)	6 वर्ष (2017)
लाभार्थियों की औसत आयु	37	37	56	36	42	35

सरकारी कार्यक्रमों ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, स्थायी आजीविका में सुधार और महिला उद्यमिता विकास की दृष्टि से परिवारों के व्यक्तिगत सदस्यों को एसएचजी में संगठित करने में मदद की। इस अध्ययन ने गुप्ता और राठौड़ के निष्कर्षों की पुष्टि की और बताया कि सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षित एसएचजी ने अधिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण दिखाया है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश सफल एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों को किसी न किसी रूप में सरकारी एजेंसियों से समर्थन प्राप्त हुआ।

एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों की स्केलेबिलिटी मजबूत विपणन तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करने, उनकी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार पैदा करने के अवसरों का दोहन करने पर निर्भर करती है। इस अध्ययन में, यह पाया गया कि जो स्वयं सहायता समूह स्थापित विपणन प्लेटफार्मों से जुड़ सकते हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालाँकि, अधिकांश एसएचजी उद्यम अपने दम पर शुरू से अंत तक संचालन कर रहे हैं और एग्रीगेटर्स से बहुत कम समर्थन प्राप्त करते हैं। क्षमताएँ सफलता का एक प्रमुख घटक हैं। यदि क्षमताएं पारंपरिक व्यवसायों पर आधारित हों तो बेहतर है, और यदि ऐसी क्षमताएं उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य अद्वितीय उत्पादन क्षमताओं को हासिल करने की आवश्यकता है। एसएचजी सदस्यों के पारंपरिक जीवन पर आधारित उद्यमशीलता गतिविधियाँ लंबे समय में अधिक स्थायी प्रतीत होती हैं। अधिकांश एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों ने किसी न किसी प्रकार का नवाचार दिखाया। एसएचजी की मापनीयता क्षमता की तुलना तालिका - 3 में दी गई है।

तालिका 3:

मापनीयता क्षमता: एसएचजी का क्रॉस-केस विश्लेषण

क्रॉस केस संकलन	तमिलनाडु - तंजावुर	असम - भालूकी	ओडिशा - गुलनगर	उत्तर प्रदेश - कादीपुर	बिहार - किसान चाची	मध्य प्रदेश - चिचगांव
परिचालन चरण	कच्चे माल का संग्रह - तैयारी - मोल्डिंग - फिनिशिंग - पैकेजिंग - मार्केटिंग	कच्चे माल का अधिग्रहण - डिजाइन और निर्माण - फिनिशिंग-विपणन और वितरण	संग्रह - छँटाई - प्रीप्रोसेसिंग - डिज़ाइन - क्राफ्टिंग - फिनिशिंग - मार्केटिंग - वितरण - पुन: उपयोग	कच्चा माल अधिग्रहण - डिजाइन विकास - विनिर्माण - गुणवत्ता नियंत्रण - पैकेजिंग - वितरण	संघटक सोर्सिंग - उत्पादन - पैकेजिंग - वितरण - खुदरा	सुखाना - परिवहन - भूसी निकालना - ग्रेडिंग
सरकारी सहायता	टीएनएसआरएलएम	असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, त्रिपुरा बांस और बेंत विकास केंद्र	ओ आर एम ए एस	यूपीएसआरएलएम	जीविका, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	
उपलब्ध क्षमताएं	पारंपरिक कारीगरों का कौशल, रिकॉर्ड रखना	रिकॉर्ड रखना, डिजाइन विकास, नई मांग-आधारित और बाजार-उन्मुख आधुनिक जीवन शैली उपयोगिता और सजावटी उत्पादों की शुरूआत और नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी का समावेश	डिज़ाइन एवं विकास	एसएचजी गठन और सुदृढ़ीकरण की मूल बातें	कौशल - कृषि आधारित उत्पाद	एसएचजी गठन और सुदृढ़ीकरण की मूल बातें
विपणन	कियोस्क, प्रदर्शनियाँ, मेला और अमेज़ॅन में नामांकित	मेघालय में खासी एम्पोरियम, असम में पूर्बश्री और कलाक्षेत्र, गुवाहाटी, मुंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बेंत और बांस उत्पादों के निजी वाणिज्यिक आउटलेट, शिल्परामम क्राफ्ट विलेज, हैदराबाद और दिल्ली स्थित एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से वैश्विक बाजार	कोई सीधा संबंध नहीं	सामुदायिक सहभागिता (स्कूली छात्र, पुलिस कार्मिक और सरकारी अधिकारी)	किसान चाची खाद्य उत्पाद, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, खादी मॉल, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन	कोई सीधा संबंध नहीं
दीर्घकालिक स्थिरता ताकत	जिले में अधिक उत्पादक समूह और पारंपरिक कारीगर हैं	भालुकी में प्रत्येक परिवार द्वारा की जाने वाली गतिविधि		सामूहिक कार्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत संचालन	उत्पादों की मांग में वृद्धि	सामूहिक कार्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत संचालन
	उत्पादों का अनुकूलन और विविधीकरण	वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाना, बांस आवास, सजावट और निर्माण, और बांस फर्नीचर जैसे नए नवीन क्षेत्रों में विविधता लाना	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	नए डिज़ाइन और विविधीकरण	खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	हल्दी एवं मिर्च प्रसंस्करण इकाई

जैसा कि हॉफ और तलवार ने पाया, जब महिलाएं उद्यमशीलता गतिविधियों में शामिल होती हैं तो महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है, परिवारों और समुदायों के लिए अधिक समृद्धि होती है और समाज को समग्र लाभ होता है। इससे एसएचजी सदस्यों को एक स्थिर आय उत्पन्न करने में मदद मिलती है, जिसका उपयोग उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एक एसएचजी सूक्ष्म-उद्यम द्वारा उत्पन्न लाभ की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उद्यम का आकार, उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रकार और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल सामग्री और श्रम की लागत शामिल है। इसके अतिरिक्त, बिक्री की मात्रा और प्रतिस्पर्धा की डिग्री एक एसएचजी सूक्ष्म उद्यम के लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकती है। अंततः, एक एसएचजी सूक्ष्म उद्यम की लाभप्रदता काफी हद तक उसके सदस्यों के कौशल, संसाधनशीलता के स्तर और समर्पण पर निर्भर करती है।

हालाँकि एसएचजी समूहों के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया, लेकिन समूह के सदस्यों के रूप में भी उन्हें अलग-अलग हद तक लाभ हुआ। वे अपने संसाधनों को एकत्रित करने, जोखिम साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने में सक्षम थे, जिससे आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। इस सामूहिकता ने एसएचजी महिलाओं को अपने हितों और मांगों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बन गईं। इस तरह की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने, स्थानीय निकायों में प्रतिनिधि बनने और सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार दिया है। तालिका 4 में, मन की बात के बाद एसएचजी को हुए ये लाभ और फायदे सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4:

आय लाभ और फायदे: एसएचजी का क्रॉस-केस विश्लेषण

क्रॉस-केस संकलन	**तमिलनाडु - तंजावुर**	**असम - भालूकी**	**ओडिशा - गुलनगर**	**उत्तर प्रदेश - कादीपुर**	**बिहार - किसान चाची**	**मध्य प्रदेश - चिचगांव**
व्यक्ति की वित्तीय स्थिति	नियमित मासिक आय (रु.12000-रु.15000)	नियमित मासिक आय (रु.12000-रु.15000)	इतना आकर्षक तो नहीं लेकिन समुदाय की सेवा कर रहा हूँ	औसत मासिक आय रु.7000	नियमित मासिक आय (रु. 6000 - 8000)	दैनिक आय 250 रुपये तक बढ़ गयी है
समूह की वित्तीय स्थिति	उत्पादों में निवेश	मशीनरी में निवेश	मशीनरी में निवेश	मशीनरी में निवेश	उत्पादों में निवेश	मशीनरी में निवेश
सामाजिक लाभ और सशक्तिकरण	सामाजिक सशक्तिकरण	सामाजिक सशक्तिकरण	सामाजिक सशक्तिकरण	सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण	सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण	राजनीतिक सशक्तिकरण

तालिका 5:

मन की बात से लाभ उल्लेख: एसएचजी का क्रॉस-केस विश्लेषण

क्रॉस केस संकलन	**तमिलनाडु - तंजावुर**	**असम - भालूकी**	**ओडिशा - गुलनगर**	**उत्तर प्रदेश - कादीपुर**	**बिहार - किसान चाची**	**मध्य प्रदेश - चिचगांव**
सामाजिक मान्यता	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
वित्तीय सुद्दढ़ीकरण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
प्रेरणा में वृद्धि	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
उन्नत समर्थन आधार	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
गुणक प्रभाव	अधिक समूह शामिल हुए अन्य जिलों में भी इसी तरह की पहल शुरू हुई	अधिक समूह शामिल हुए	उनकी पहल में एक और एसएचजी शामिल हो गया	तीन पड़ोसी ग्राम पंचायतों के एसएचजी को दोहराया गया	अधिक समूह शामिल हुए	-
अविश्वसनीय पहुँच	उत्कृष्ट पहुँच	उत्कृष्ट	मध्यम	मध्यम	उत्कृष्ट	मध्यम

हालाँकि इस अध्ययन की रिपोर्ट में एसएचजी महिला उद्यमियों को उन्हें, उनके परिवार और बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए अलग-अलग तरीकों से लाभ हुआ है, लेकिन एसएचजी एमई द्वारा उत्पन्न प्रभाव को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1:

स्वयं सहायता समूह का प्रभाव पथ

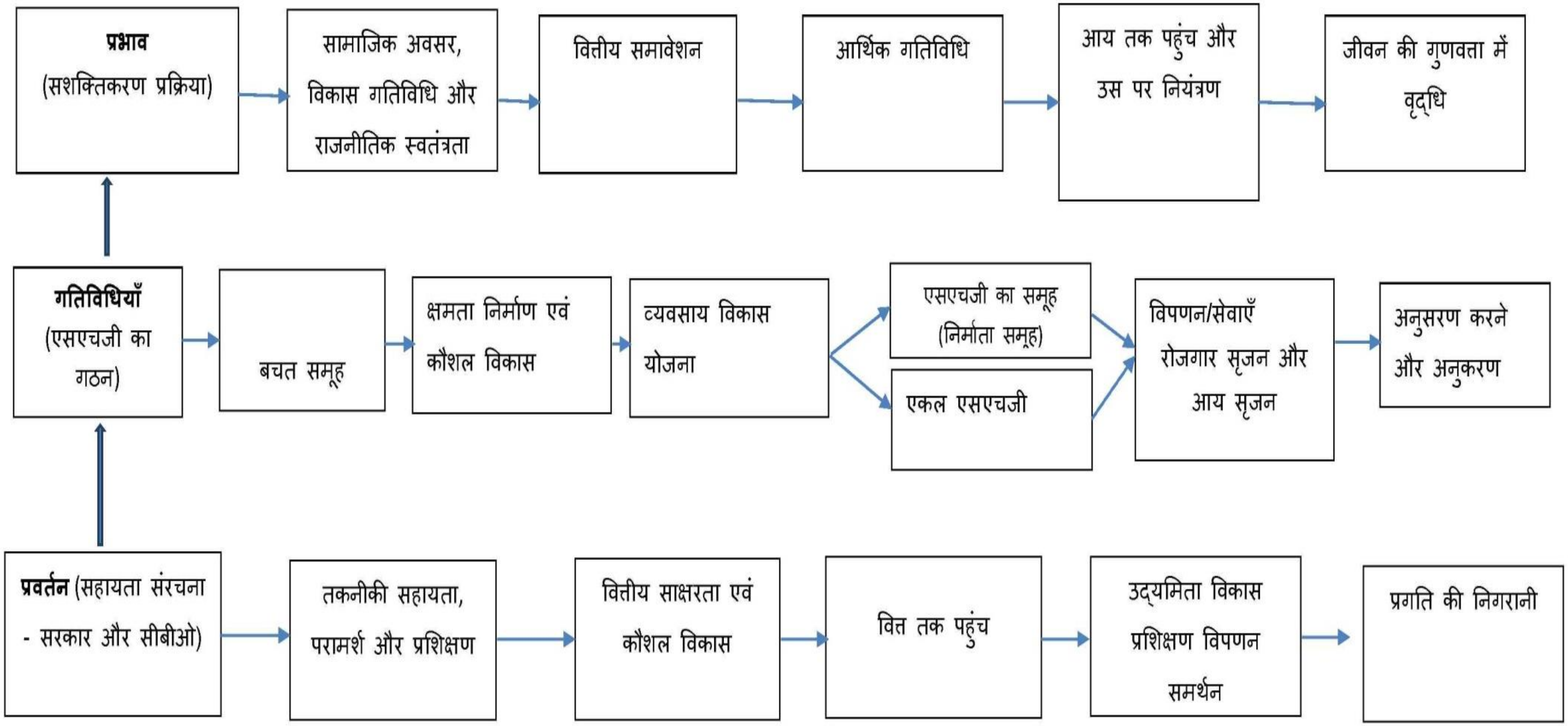

संचार के माध्यम के रूप में रेडियो का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग तरीके से किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा, राजनीतिक संचार, सूचना साझाकरण आदि के लिए किया जाता है। मन की बात संबोधन में रेडियो का उपयोग आम नागरिकों और उनसे संबंधित चीजों से जुड़ने के लिए किया जाता है। प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न विषयों पर नागरिकों तक पहुंचना है जो उन्हें मन की बात संबोधन में उल्लिखित पहलों को आगे बढ़ाने और उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सके। इस प्रपत्र के मामला अध्ययन में मन की बात संबोधन के बाद एसएचजी सदस्यों के बीच प्रेरणा के स्तर में वृद्धि देखी गई। एसएचजी सदस्यों की सामाजिक मान्यता और समर्थन आधार में काफी वृद्धि हुई, जैसा कि मामले के अध्ययन में दर्ज किया गया था। एमकेबी के संबोधन के बाद एसएचजी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से और समूह में वित्तीय मजबूती का अनुभव हुआ। मन की बात संबोधन से कुछ स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों में कई गुना प्रभाव पड़ा, विशेषकर उनकी गतिविधियों में जो एक क्लस्टर में काम कर रहे थे, इस प्रकार उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिली, जिनकी पहुंच नहीं थी। मन की बात संबोधन ने कुछ नवीन एसएचजी गतिविधियों को प्रकाश में लाया जो करीब एक दशक से चल रही थीं, जैसे श्रीमती कमला मोहना की अपशिष्ट से संपत्ति बनाने की पहल जो अब अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच रही है। तालिका 5 मन की बात संबोधनों से एसएचजी सदस्यों के लिए लाभ को सामने लाती है, जिसमें सामाजिक मान्यता, वित्तीय मजबूती, प्रेरणा में वृद्धि, समर्थन आधार में वृद्धि, गुणक प्रभाव और वंचितों तक पहुंचना शामिल है।

तालिका 5:

मन की बात से लाभ उल्लेख: एसएचजी का क्रॉस-केस विश्लेषण

क्रॉस केस संकलन	तमिलनाडु - तंजावुर	असम - भालूकी	ओडिशा - गुलनगर	उत्तर प्रदेश - कादीपुर	बिहार - किसान चाची	मध्य प्रदेश - चिचगांव
सामाजिक मान्यता	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
वित्तीय सुदृढ़ीकरण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
प्रेरणा में वृद्धि	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
उन्नत समर्थन आधार	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
गुणक प्रभाव	अधिक समूह शामिल हुए अन्य जिलों में भी इसी तरह की पहल शुरू हुई	अधिक समूह शामिल हुए	उनकी पहल में एक और एसएचजी शामिल हो गया	तीन पड़ोसी ग्राम पंचायतों के एसएचजी को दोहराया गया	अधिक समूह शामिल हुए	-
अविश्वसनीय पहुँच	उत्कृष्ट पहुँच	उत्कृष्ट	मध्यम	मध्यम	उत्कृष्ट	मध्यम

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों की सफलता का श्रेय महिलाओं की मजबूत समुदायों का निर्माण करने और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने की क्षमता को दिया जा सकता है। एसएचजी महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए संसाधन और कौशल प्रदान करके सशक्त बना रहे हैं। इस प्रपत्र में चर्चा किए गए मामलों से एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों ने रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देकर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिला उद्यमियों को अक्सर संसाधनों तक सीमित पहुंच, पहचान की कमी और लैंगिक रूढ़िवादिता जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही समर्थन और मार्गदर्शन के साथ, इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है और महिला उद्यमियों की क्षमता का पूरी तरह से एहसास किया जा सकता है। इस दिशा में, प्रधान मंत्री के मन की बात संबोधनों ने व्यापक सार्वजनिक मान्यता के साथ उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया। इन मामलों का अनुकरण अन्यत्र भी किया जा सकता है। सही नीतियों, व्यवसाय विकास पहलों और निवेश के साथ, महिला उद्यमी समग्र आर्थिक प्रगति और विकास में योगदान दे सकती हैं।

संदर्भ:

Agarwal, S., & Lenka, U. (2016). An exploratory study on the development of women entrepreneurs: Indian cases. *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 18*(2), 232 – 247.

Alrefaei, N., Aquinas, P. ., & Al-Maamari, O. A. (2022). Self help group (SHG) in India: a path toward empowerment and poverty reduction. *Social Work with Groups*, 1–15. https://doi.org/10.1080/01609513.2022.2159612

Chakraborty, A., Kumar, N., Kaur, G., & Kathuria, G. (2022). Vulnerability of Self-Help Groups in Marketing their Products–Identification of the Key Factors for Enhanced Market Reach and Profitability. *Indian Journal of Agricultural Economics, 77*(1), 179–193.

Deininger, K., & Liu, Y. (2013a). Economic and social impacts of an innovative self-help group model in India. *World Development*, *43*, 149–163.

Deininger, K., & Liu, Y. (2013b). Evaluating program impacts on mature self-help groups in India. *The World Bank Economic Review*, *27*(2), 272–296.

Deshpande, A. (2021). *Workshop Proceedings Virtual Webinar on Rural Livelihoods Programs in South Asia : Lessons From the Past As a Guide To the Future Date*. 124.

Díaz-Martin, L., Gopalan, A., Guarnieri, E., & Jayachandran, S. (2023). Greater than the Sum of the Parts? Evidence on Mechanisms Operating in Women's Groups. *The World Bank Research Observer*, *38*(1), 1–35. https://doi.org/10.1093/wbro/lkac001

Haough, H. M., & Talwar, A. (2016). Linking Social Capital. *Journal of Business Ethics*, *133*, 643–658. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2449-4

Jose, S., Chockalingam, S. M., & Velmurugan, R. (2019). Problems of Women Self Help Group Members in Ernakulam District. *Journal of Critical Reviews*, *7*(1), 141–143.

Kapoor, S. (2019). Entrepreneurship for Economic and Social Empowerment of Women: A Case Study of Self Help Credit Program in Nithari Village, Noida, India. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, *13*(2), 123–142.

Kochar, A., Nagabhushana, C., Sarkar, R., Shah, R., & Singh, G. (2022). Financial access and women's role in household decisions: Empirical evidence from India's National Rural Livelihoods project. *Journal of Development Economics*, *155*(January), 102821. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102821

Minimol, M. C. (2020). Women entrepreneurship in Coastal Kerala: Role of self help groups in developing a sustainable community. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, *7*(4), 3426–3437. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(56)

Osberg, S. R., & Martin, R. L. (2015). Two keys to sustainable social enterprise. *Harvard Business Review*, *2015*(May).

Severt, J. B., & Estrada, A. X. (2015). On the function and structure of group cohesion. In *Team Cohesion: Advances in Psychological Theory, Methods and Practice*. https://doi.org/10.1108/S1534-085620150000017002

Sharma, D. M., & Johri, S. M. (2020). Exploring Critical Determinants of Income Generating Activities in Self-Help Groups for Women Empowerment: Field Evidence From India. *Journal of Critical Reviews*, *7*(15), 3560–3571.

Singh, S., Thakur, G., & Gupta, P. C. (2013). A Case Study on Empowerment of Rural Women through Micro Entrepreneurship Development. *IOSR Journal of Business and Management*, *9*(6), 123–126. https://doi.org/10.9790/487x-096123126

Suprabha K. R. (2014). Empowerment of Self Help Groups (SHGs) towards Microenterprise Development. *Procedia Economics and Finance, 11*, 410 – 422.

Were, P. O., & Kimaru-Muchai, S. W. (2021). Evaluation of Self-Help Groups in Promoting Women Socio-Economic Empowerment in Kibra Sub-County, Nairobi County, Kenya. *Journal of Global Awareness*, *2*(1).

Wituk, S. A., Shepherd, M. D., Warren, M., & Meissen, G. (2002). Factors Contributing to the Survival of Self-Help Groups. *American Journal of Community Psychology, 30*, 349–366.

Yoak, M., & Chesler, M. (1985). Alternative professional roles in health care delivery: Leadership patterns in self-help groups. *Journal of Applied Behavioral Science, 21*(4), 427–444.

अमृत सरोवरों के माध्यम से विकास की परिकल्पना: जल भंडारण और संरक्षण के पुनरुद्धार के लिए मन की बात मामलों का एक अध्ययन

सोनल मोबार रॉय*, सी. धीरजा**, दिगंबर ए. चिमनकर**, अनुराधा पल्ला*, राज कुमार पम्मी*, और जी. नरेंद्र कुमार***

सार

भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर की पहल शुरू की गई। मिशन का लक्ष्य आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। इस प्रपत्र में, लेखकों ने चार अमृत सरोवरों के मामलों का अध्ययन किया, जिनका उल्लेख प्रधान मंत्री के 'मन की बात' (एमकेबी) कार्यक्रम, दिनांक 28 अगस्त 2022 (92वां एपिसोड) में किया गया था। चयनित अमृत सरोवर ललितपुर (उत्तर प्रदेश), मंडला (मध्य प्रदेश), वारंगल (तेलंगाना) और बगलकोट (कर्नाटक) में स्थित हैं। इन मामलों का अच्छी तरह से दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण नहीं किया गया है और इसलिए यह पेपर उनके प्रभाव को विस्तार से उजागर करने का प्रयास करता है। साहित्य समीक्षा से संकेत मिलता है कि अमृत सरोवर जैसे तालाब जलवायु-प्रूफिंग में प्रभावी हो सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद कर सकते हैं। एमकेबी कार्यक्रम में उल्लेख के बाद लेखक अमृत सरोवरों के विकास के लिए मुख्य सफलता कारकों, खर्च की गई लागत और धन के स्रोत, भौतिक विशेषताएं, मौजूद सुविधाएं, पानी की उपलब्धता और उपयोग पर प्रभाव की जांच करते हैं। इसके अलावा, वे अमृत सरोवर पहल के विस्तार पर मन की बात के प्रभाव का आकलन करते हैं और इसके परिणामस्वरूप जल भंडारण और संरक्षण, कृषि उत्पादन में बदलाव और अमृत सरोवर के आसपास पारिस्थितिकी और सामाजिक-सांस्कृतिक सामंजस्य पर अमृत सरोवर का प्रभाव पड़ता है। पेपर उस तरीके को दर्शाता है जिसमें मिशन में जल निकायों के विकास और प्रबंधन और उपयोगकर्ता समूहों के गठन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए स्थानीय निवासियों को संगठित करने के रूप में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। अंत में, यह पेपर अमृत सरोवरों के बेहतर उपयोग के लिए आगे बढ़ने के तरीके के साथ-साथ उत्पन्न आय और सिंचित क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित संकेतकों के लिए एक क्रॉस-केस विश्लेषण पर प्रकाश डालता है। यह पाया गया कि एमकेबी संबोधन ने अमृत सरोवर पहल के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुछ राज्य लक्ष्य से परे अमृत सरोवरों की संख्या बढ़ाने के लिए आगे आए। मन की बात संबोधन के बाद, अमृत सरोवर के हितधारकों के बीच न केवल मौजूदा अमृत सरोवर का बेहतर उपयोग करने बल्कि स्थान और समय में अपने कवरेज का विस्तार करने के लिए उत्साह में वृद्धि देखी गई।

प्रमुख शब्द: मन की बात, अमृत सरोवर, जल संरक्षण, सामुदायिक जुटाव, जलवायु संरक्षण।

अध्ययन हेतु मन की बात एपिसोड का संदर्भ: 92वां एपिसोड- 28 अगस्त, 2022

---

*सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्यूईएल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

**एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्यूईएल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

***महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

परिचय :

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किए गए मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों और उसके लोगों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में इतना आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि अपने भीतर भी बनाए रखा है। आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित भारत 2.0 को सक्रिय करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता।

यह पेपर ललितपुर (यूपी), मंडला (एमपी), वारंगल (तेलंगाना) और बगलकोट (कर्नाटक) में स्थित चार अमृत सरोवरों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये चार अनुकरणीय मामले हैं जिनका उल्लेख माननीय प्रधान मंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम (एमकेबी, 92 वें एपिसोड) में किया था। वहीं, पीएम ने जल के महत्व और उसके संरक्षण पर भी जोर दिया था. उन्होंने ऋग्वेद का एक श्लोक उद्धृत किया::

ओमान-मापोमानुषी:
अमृतकमधात्तोकायतनयाश्याम्यो: |

योयं हिसथ भिषजो मातृतम विश्वस्यस्थ
अतु: जगतोजनित्रि: ||

(अर्थ - हे जल, तुम मानवता के सबसे अच्छे मित्र हो। तुम ही जीवन दाता हो। तुमसे ही अन्न उत्पन्न होता है और तुमसे ही हमारे बच्चों का कल्याण होता है। तुम ही हमारे रक्षक हैं और हमें सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। तुम ही सर्वोत्तम औषधि हैं और तुम ही इस जगत के पालनकर्ता हैं।)

उन्होंने कहा कि एमकेबी कार्यक्रम में अमृत सरोवर के उनके प्रारंभिक उल्लेख के बाद, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन एक साथ आए और इस प्रकार भीड़ जुटाने के माध्यम से देश भर में विभिन्न अमृत सरोवर विकसित किए गए।

साहित्य की समीक्षा

भारत की वर्षा-आधारित कृषि योग्य प्रणालियों में, जो कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% है (शंकर, 2011), लाभदायक और लचीली वर्षा-आधारित प्रणालियों के लिए वर्षा का संग्रहण और कुशलतापूर्वक उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण घटक है। वर्षा आधारित फसलों का सफल उत्पादन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी की नमी को कितनी कुशलता से यथास्थान संरक्षित किया जाता है या अधिशेष अपवाह की कटाई करके उसे पूरक सिंचाई के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है। जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं की उच्च आवृत्ति के साथ कृषि के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व अब और अधिक जरूरी हो गया है (राव तथा अन्य, 2009; आईपीसीसी, 2014)। वर्षा जल प्रबंधन वर्षा आधारित खेती के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है और फसलों का सफल उत्पादन काफी हद तक इस

बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी की नमी को कितनी कुशलता से संरक्षित किया जाता है और अधिशेष प्रवाह को काटा जाता है, संग्रहीत किया जाता है और अतिरिक्त सिंचाई के लिए और पुनर्भरण के लिए पुन: उपयोग किया जाता है (राव, 2010; श्रीनिवासराव, 2013)।

खेत के तालाब घरेलू उपयोग के साथ-साथ जानवरों के लिए भी पानी उपलब्ध कराकर खेती की गतिविधियों को महत्व देते हैं। यह फसलों को उगाने के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान करता है और मछली पालन में मदद करता है। क्यूएन्स के अनुसार, ये तालाब और "तालाबों का नेटवर्क" जैव विविधता के लिए और मनुष्यों को कई लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं, जिसे "लोगों के लिए प्रकृति का योगदान", भी कह सकते हैं जैसे कि जलवायु शमन और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, जैव विविधता, जल शुद्धिकरण, खाद्य शमन और सांस्कृतिक लाभ के लिए आवास का निर्माण और रखरखाव (मनोरंजक संभावनाएँ) । लोगों तक प्रकृति योगदान की एक विस्तृत श्रृंखला के वितरण के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों के रूप में तालाबों के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक, आर्थिक और नीति ज्ञान को उत्पन्न और एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, तालाबों के व्यापक उपयोग का समर्थन करने के लिए साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मणिकंदन और भुवनेश्वरी (2022) के अध्ययन से पता चलता है कि खेत तालाब भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहीत करने के सर्वोत्तम वैकल्पिक तरीकों में से एक हैं। खेत के तालाब आम तौर पर चौकोर या आयताकार आकार में छोटे खोदे हुए स्थान होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, खेत तालाबों का उपयोग सिंचाई उद्देश्यों, सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है, और मवेशियों के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह अध्ययन मुख्य रूप से भारत में ग्रामीण आजीविका पर खेत तालाबों के प्रभाव पर केंद्रित है।

राव तथा अन्य (2017) का लेख, जलवायु परिवर्तन सहित कई कारणों से पानी की कमी को दूर करने के लिए एक अनुकूलन रणनीति के रूप में खेत तालाब प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का सारांश प्रस्तुत करता है। इस तकनीक में पूरक सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने और फसल क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि करने की क्षमता है, जिससे फसलों से निवल प्रतिफल में वृद्धि होगी। कृषि तालाब सूखे की बढ़ती आवृत्तियों, विशेष रूप से मध्य-मौसम और जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के तहत अंतिम सूखे को दूर करने के लिए एक समाधान प्रदान करता है। लेख व्यक्तिगत खेत स्तर पर या सामुदायिक-साझाकरण के आधार पर 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र वाले प्रत्येक खेत के लिए एक तालाब को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की सिफारिश करता है। पिछले दशकों में, पानी की कमी के मुद्दे गंभीर हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों के बीच मीठे पानी के लिए गहन प्रतिस्पर्धा हुई है और जल संसाधनों के इष्टतम आवंटन को पूरा करने की आवश्यकता है (फ़्राइसन तथा अन्य, 2017; शाओ तथा अन्य, 2015)। भौगोलिक स्थिति (अर्थात्, धरा के प्रतिकूल बनाम प्रवाह के साथ), वर्ग, जाति और लिंग में असमानताएं और प्रौद्योगिकी की पसंद सहित कई कारक, वाटरशेड कार्यक्रमों में असमानताओं में योगदान करते हैं (राजोरा, 1998; ओइकोस और आईआईआरआर, 2000; जॉय और परांजपे, 2004)। भूमि और जल संसाधनों के विकास और आगामी बायोमास उत्पादन के लाभों का एक समान वितरण करने के लिए, ग्रामीण समुदायों को भागीदारी योजना और कार्यान्वयन में शामिल करने के लिए, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवस्था बनाने के लिए, संपत्तियों को

बनाए रखने के लिए और अधिक समावेशी सामाजिक वातावरण में काम करने के लिए, जल संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

खेत तालाबों की तर्ज पर, 24 अप्रैल 2022 से अमृत सरोवर मिशन के तहत अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। देश भर में, 100311 स्थलों की पहचान की गई और अंततः 44,613 स्थलों पर अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो गया। अमृत सरोवरों के विकास के लिए किए गए अधिकांश कार्य महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से पूरे किए गए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को महात्मा गांधी नरेगा के तहत अभिसरण वर्ष घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के पास उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संसाधनों के साथ महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के अभिसरण के माध्यम से स्थायी और उत्पादक संपत्ति बनाने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निवेश को अनुकूलित करना है। विकास कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से प्रयासों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिसरण महात्मा गांधी नरेगा और जिला स्तर पर नवीन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने वाले अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के बीच तालमेल को अनुकूलित करता है। अभिसरण के संचालन के तीन स्तर हैं:

- कृषि के साथ व्यापक अभिसरण,
- एकीकृत सहभागी योजना अभ्यास (आईपीपीई) के तहत सूक्ष्म-स्तरीय योजना के स्तर पर अभिसरण और,
- संसाधनों के स्तर पर अभिसरण

कृषि के लिए जल संरक्षण और भंडारण के साधन के रूप में खेत तालाब भारत में तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। भारत में खेत तालाबों के लागत-लाभ विश्लेषण में तालाब के निर्माण और रखरखाव से जुड़ी लागतों के साथ-साथ फसलों के लिए पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लाभों की जांच शामिल होगी। आकार और स्थान जैसे संकेतक निर्माण लागत निर्धारित करेंगे। चूँकि ऐसे तालाबों को ठीक से काम करने के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है, रखरखाव की लागत तालाब के आकार, रखरखाव की आवृत्ति और श्रम लागत पर निर्भर करेगी। तालाबों के निर्माण से प्राप्त लाभों में पानी की उपलब्धता में वृद्धि, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार और बढ़े हुए उत्पादन से आय में वृद्धि शामिल है। खेत के तालाब पानी को रोककर और पानी के बहाव को रोककर मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

उद्देश्य

लेख का उद्देश्य अमृत सरोवरों के विकास के लिए मुख्य सफलता कारकों के साथ-साथ मन की बात के बाद की स्थिति की जांच करना है।

क्रियाविधि

अमृत सरोवरों पर इस विशेष अध्ययन के लिए एनआईआरडीपीआर अध्ययन दल चार राज्यों में गए। अध्ययन टीमों द्वारा मामले के अध्ययन के लिए साक्ष्य तैयार करने के लिए एक समान पद्धति से युक्त एक व्यापक अनुसंधान प्रोटोकॉल अपनाया गया था। डेटा संग्रह उपकरणों में अर्ध-संरचित प्रश्नावली, फोकस समूह चर्चा आयोजित करने के लिए जांच-सूची शामिल थी और अध्ययन टीमों द्वारा क्षेत्र अवलोकन किए गए थे। दैनिक क्षेत्र टिप्पणियाँ एकत्रित और संकलित की गई। लाभार्थियों, पीआरआई सदस्यों और संबंधित ग्रामीणों जैसे हितधारकों का साक्षात्कार लिया गया। डेटा संग्रह में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र अवलोकन से पहले टीम के विचार-मंथन और विवरण के साथ-साथ साहित्य की समीक्षा की गई। डेटा संग्रह चरण के बाद, टीमों को एक साथ जानकारी दी गई और कारण-प्रभाव संबंधों के आधार पर एक गुणात्मक मामला विश्लेषण ढांचा विकसित किया गया। अमृत सरोवर हस्तक्षेप पर जोर देने के साथ, व्यक्तिगत मामले की रिपोर्टों का क्रॉस-केस तुलना परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया गया।

मन की बात कार्यक्रम

मन की बात कार्यक्रम एक रेडियो कार्यक्रम है जो हर महीने प्रसारित किया जाता है जहां प्रधान मंत्री देश के नागरिकों के साथ उन विषयों और मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो देशवासियों के लिए प्रमुख चिंता का विषय हैं। मन की बात शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद "वर्ड्स फ्रॉम द हार्ट" होता है। कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी ऐप पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के विषय सामाजिक मुद्दों से लेकर शासन और विकास पहल तक हैं। यह कार्यक्रम ध्यान और सराहना आकर्षित करता है क्योंकि इसमें देश के आम लोगों के जीवन से जुड़ी कहानियां, मामले और घटनाएं शामिल हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह से समाज और देश में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य मोदी जी द्वारा सिद्ध किये गये 'परिवर्तनकारी प्रधान मंत्री' और नागरिकों के बीच संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना भी है। कार्यक्रम ने जनता के बीच विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा की है।

इसकी एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एक रेडियो कार्यक्रम है। रेडियो को संचार के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है जो लंबी दूरी के लोगों को जोड़ता है, सूचना प्रसारित करता है और मनोरंजन भी प्रदान करता है। जैसा कि गर्ग (2020) ने कहा, इस कार्यक्रम ने भारतीय लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। शर्मा और दुबे (2021) का सुझाव है कि मन की बात कार्यक्रम में वक्तृत्व कौशल और सावधानीपूर्वक चुने गए शब्दों का उपयोग नागरिकों को प्रेरित करने में सफल है। 1.3 अरब लोगों के देश में, मन की बात कार्यक्रम के लिए एक माध्यम के रूप में रेडियो का उपयोग प्रभावी पाया गया है (गिरि और त्रिपाठी, 2018; सक्सेना, 2016)। गांधी और बालामुरुगन (2017) को लगता है कि इस कार्यक्रम में देश के भविष्य को ढालने और बेहतर आकार देने की क्षमता है। मन की बात एक पहल के रूप में नेता को देश के नागरिकों से जोड़ने का एक सफल विचार साबित हुआ। लेकिन संस्कृति, भाषा, धर्म आदि के मामले

में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए इस पहल को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।

मिशन अमृत सरोवर

भारतीय संस्कृति और धर्म में 'अमृत' शब्द के कई अर्थ और तात्पर्य हैं। इसलिए, इसका उपयोग पवित्रता और कायाकल्प के विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 'सरोवर' शब्द का हिंदी में अर्थ झील या तालाब होता है। 'अमृत सरोवर' शब्द का उद्देश्य पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए शुद्ध और पुनर्जीवित जल निकाय का विचार व्यक्त करना है। 'अमृत' शब्द जिसका अर्थ रस या पारस मणि है, यहां भारतीय समाज में पानी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है और जल संकट को दूर करने के लिए सरकार की पहल को रेखांकित करता है। मिशन अमृत सरोवर का प्रमुख लक्ष्य "देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाब) का निर्माण/विकास करना है।" प्रत्येक अमृत सरोवर में न्यूनतम तालाब का आकार 1 एकड़ (0.4 हेक्टेयर) होगा, जिसकी जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर होगी। सभी ग्रामीण जिले विकसित होंगे और उनमें कम से कम 75 अमृत सरोवर होंगे, पूरे देश में कुल मिलाकर लगभग 50,000 अमृत सरोवर होंगे।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन दल ने मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित चार अमृत सरोवरों की जांच की। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि देश भर में अमृत सरोवरों की स्थिति पर राज्यों की स्थिति कैसी है।

तालिका 1

भारत में अमृत सरोवरों की स्थिति का परिदृश्य

भारत में अमृत सरोवरों की स्थिति का परिदृश्य				
क्र.सं.	राज्य	पहचाने गए स्थलों की कुल संख्या	कुल चिन्हित स्थलों में से शुरू किये गये कार्यों की कुल संख्या	प्रारंभ किये गये कार्यों में से पूर्ण किये गये कार्यों की कुल संख्या
1.	अण्डमान और निकोबार	353	204	156
2.	आंध्र प्रदेश	4643	3355	1320
3.	अरुणाचल प्रदेश	2611	1562	1274
4.	असम	3338	2784	2135
5.	बिहार	3692	2374	1083
6.	छत्तीसगढ	3808	2859	1957
7.	गोवा	165	165	164
8.	गुजरात	2693	2667	2145

9.	हरियाणा	7454	3115	1137
10.	हिमाचल प्रदेश	2189	1398	822
11.	जम्मू और कश्मीर	4066	2682	2438
12.	झारखंड	4103	2098	1277
13.	कर्नाटक	6460	4998	2451
14.	केरल	911	644	212
15.	लद्दाख	174	134	131
16.	मध्य प्रदेश	7234	5949	3246
17.	महाराष्ट्र	3115	2517	1776
18.	मणिपुर	1349	868	767
19.	मेघालय	1100	481	318
20.	मिजोरम	1155	813	753
21.	नागालैंड	270	181	53
22.	ओडिशा	4277	2909	1377
23.	पुदुचेरी	170	153	142
24.	पंजाब	2046	1307	803
25.	राजस्थान	4035	3335	1885
26.	सिक्किम	279	221	156
27.	तमिलनाडु	3172	2261	1546
28.	तेलंगाना	3358	2085	935
29.	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	95	81	81
30.	त्रिपुरा	998	988	772
31.	उत्तराखंड	1943	1251	1116
32.	उत्तर प्रदेश	18775	12102	10178
33.	पश्चिम बंगाल	280	16	7
34.	कुल	100311	68557	44613

स्रोत: https://amritsarovar.gov.in/Master 23 अप्रैल, 2023 तक की रिपोर्ट।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पूरे भारत में 100311 स्थलों की पहचान की गई है और 68557 स्थलों पर काम चल रहा है और 23 अप्रैल 2023 तक 44613 स्थलों पर काम पूरा हो चुका है। इस अध्ययन में चार मामलों का संदर्भ देते हुए, ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि चार में से दो मामले उत्तर भारत से हैं और दो दक्षिण भारत से हैं। उत्तर प्रदेश (18775) और मध्य प्रदेश (7234) ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक संख्या में स्थलों की पहचान की गई है, और ये वही राज्य हैं जहां शुरू किए गए कार्यों में से सबसे अधिक कुल कार्य पूरे किए गए हैं। तेलंगाना के लिए, पहचान की गई स्थलों की कुल संख्या 3358 थी, जिनमें से शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या 2085 थी। हालाँकि, शुरू किए गए कार्यों

में से कुल मिलाकर केवल 935 कार्य ही पूरे किए गए। जबकि कर्नाटक में कुल 6460 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 4998 स्थलों पर काम शुरू हुआ और 2451 स्थलों पर काम पूरा हो गया।

जैसा कि दिशानिर्देशों से ज्ञात होता है, मिशन अमृत सरोवर को ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अभिसरण के साथ मिशन मोड में लिया गया है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) को मिशन के लिए एक तकनीकी भागीदार के रूप में शामिल किया गया है और तालाबों के निर्माण के लिए स्थलों की पहचान करने और सिफारिश करने के लिए संबंधित प्राधिकारी था। अमृत सरोवर के निर्माण के बाद, यह परिकल्पना की गई है कि भूजल स्तर में वृद्धि होगी; सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे फसल और पशुधन उत्पादकता बेहतर होगी और इससे जनता को लाभ होगा। हस्तक्षेप ने तालाबों के निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी अनिवार्य कर दिया।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन चार अमृत सरोवरों का चयन किया गया है जिनका उल्लेख माननीय प्रधान मंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। निम्नलिखित चार गांवों/तांडा का संक्षिप्त विवरण है।

1. **ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**: यह अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के महरौनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली निवाड़ी ग्राम पंचायत में है। इसका नाम शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर रखा गया है। पंचायत में 312 परिवारों की आबादी 2175 है। यह ग्राम पंचायत जिले से 44 किमी और ब्लॉक मुख्यालय से 5 किमी दूर स्थित है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र 1221 हेक्टेयर है, जिसमें औसत वर्षा 939.30 मिमी है। भूवैज्ञानिक अवलोकनों के अनुसार, गाँव में मुख्य रूप से कठोर चट्टानी भूभाग है क्योंकि यह बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित है।
2. **मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**: यह अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के सुरम्य घने जंगल (बफर जोन) मोचा गांव में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी दूर दक्षिण पूर्व की ओर है। मोचा ग्राम पंचायत में छह गांव हैं जिनके नाम मोचा, मानेगांव, लमना, सेतिया, पटपारा और बोदा चपरी हैं।
3. **वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**: वारंगल में अमृत सरोवर का निर्माण मंगत्या वाल्या तांडा में किया गया है। यह तेलंगाना राज्य में वारंगल जिले के पर्वतगिरि मंडल में मंडल परिषद कार्यालय से लगभग 10 किमी दूर स्थित है। मंगत्या वाल्या तांडा, पूर्ववर्ती गांव बुरुगुमाडला पंचायत से एक नवगठित ग्राम पंचायत है, जो थांडा को ग्राम पंचायतों में अपग्रेड करने की राज्य सरकार की पहल का हिस्सा है। तीन अन्य छोटे गाँव जैसे तांडा हैं जिन्हें रंजू तांडा, एड्डुबुगड्डा तांडा और हरिसिंह तांडा के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत पर्वतगिरि मंडल मुख्यालय से 10 किमी दूर और जिला मुख्यालय वारंगल से 50 किमी दूर है। 515 की आबादी वाले कुल मिलाकर 123 घर हैं। ग्राम पंचायत 235 एकड़ के कुल खेती योग्य क्षेत्र के साथ 300 एकड़ भूमि के क्षेत्र को कवर करती है। औसत वर्षा 900 मिमी है।
4. **बागलकोट, कर्नाटक में अमृत सरोवर**: बागलकोट में अमृत सरोवर उत्तरी कर्नाटक पठार पर स्थित है जो बड़े दक्कन पठार का एक हिस्सा है। उत्तर मध्य कर्नाटक में स्थित, बागलकोट पश्चिम में बेलगावी जिले, उत्तर और उत्तर-पूर्व में विजयपुर और कलबुर्गी और पूर्व में रायचूर, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और

दक्षिण-पश्चिम में क्रमशः कोप्पल, गडग और धारवाड़ से घिरा हुआ है। बिलकेरूर ग्राम पंचायत में तीन गाँव शामिल हैं, अर्थात् संगपुर, अचनौर और बिल्केरूर, जिनकी कुल भूमि लगभग 3380 हेक्टेयर है।

क्रॉस-केस विश्लेषण

लेख के इस खंड में, संकेतकों में भिन्नता की विस्तार से जांच करके और चार मामलों में उनका विश्लेषण करके चार अमृत सरोवरों का एक क्रॉस-केस विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2

अमृत सरोवरों की स्थिति

तालिका 2: अमृत सरोवरों की स्थिति					
क्र.सं.	**संकेतक**	**ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**	**मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**	**वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**	**कर्नाटक के बागलकोट में अमृत सरोवर**
1.	प्रारंभ और समापन की तिथि	17 जून 2022 को शुरू हुआ और 18 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ।	30 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और अभी तक पूरा नहीं हुआ है।	12 मई, 2022 को शुरू हुआ और 31 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ	18 जून 2022 को शुरू हुआ 13 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ
2.	पूर्ण होने की स्थिति	सरोवर निर्माण पूरा हुआ। सहायक/संलग्न कार्य प्रगति पर है।	अमृत सरोवर का कार्य प्रगति पर है	निर्माण पूरा हुआ	निर्माण पूरा हुआ
3.	नये/पुराने तालाब का पुनरोद्धार	नया निर्माण	नया निर्माण	नया निर्माण	पुराने तालाब का पुनरुद्धार
4.	क्षेत्र/तालाब	1.5 एकड़	लगभग 2.5 एकड़	लगभग 1 एकड़	0.5 एकड़
5.	लंबाई और गहराई	लंबाई - 90 मीटर चौड़ाई- 45 मी गहराई - 2 मी	लंबाई- 110 मीटर चौड़ाई-80 मी गहराई- 6.77 मी	लंबाई - 80 मीटर चौड़ाई- 120 मी गहराई - 1.5 मी.	लंबाई - 45 मीटर चौड़ाई- 44.5 मी गहराई - 2.5 मी
6.	बांध की गुणवत्ता: स्टोन की पिचिंग के लिए सुदृढ़ीकरण/फिट की आवश्यकता है	सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है	स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है	सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है	स्टोन पिचिंग हो गई है
7.	वृक्षारोपण की गुणवत्ता: पर्याप्त/बढाने की आवश्यकता	बढ़ाने की जरूरत है	पर्याप्त	बढ़ाने की जरूरत है	पर्याप्त

भले ही सभी चार अमृत सरोवरों में 2022 की पहली तिमाही में काम शुरू हो गया, लेकिन उनके पूरा होने के समय में काफी अंतर है। जबकि मंडला, एमपी में काम अभी भी प्रगति पर है, ललितपुर में काम पूरा करने में लगभग पांच महीने लगे, वारंगल में 3 महीने और बागलकोट में पुराने तालाब का कायाकल्प 9 महीने में किया गया। तालाबों के आकार में 0.5 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक काफी भिन्नता देखी गई और आयामों में भी भिन्नताएं थीं। दो मामलों में, यह देखा गया कि मेड़बंदी को मजबूत करने की आवश्यकता है, जबकि दो अन्य मामलों में, पत्थर की पिचिंग या तो पूरी हो चुकी है या प्रगति पर है। जहां तक वृक्षारोपण का सवाल है, दो तालाबों पर तालाब के चारों ओर पर्याप्त वृक्षारोपण किया गया था, जबकि अन्य दो तालाबों पर वृक्षारोपण में वृद्धि का सुझाव दिया गया था।

तालिका 3

अमृत सरोवरों का वित्तीय विवरण

तालिका 3: अमृत सरोवर का वित्तीय विवरण					
क्र.सं.	**संकेतक**	**ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**	**मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**	**वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**	**कर्नाटक के बागलकोट में अमृत सरोवर**
1.	निधि/अभिसरण का स्रोत (क) महात्मा गांधी नरेगा (ख) XV एफसी (ग) कोई अन्य	(क) महात्मा गांधी नरेगा (रु. 25.82 लाख) (ख) एसएफसी - रु. 1.6 लाख (ग) वन विभाग द्वारा 150 पौधे वितरित किये गये	(क) महात्मा गांधी नरेगा (24.95 लाख रुपये) (ख) नहीं (ग) होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन द्वारा 1.20 लाख	(क) महात्मा गांधी नरेगा (9.93 लाख रुपये)	(क) महात्मा गांधी नरेगा (19.9 लाख रुपये) (ख) वन विभाग ने पौधे वितरित किए और एसएचजी महिलाओं ने पौधे लगाए।
2.	यदि महात्मा गांधी नरेगा, तो: (क) अनुमानित लागत (ख) वास्तविक व्यय (ग) सामग्री (घ) मजदूरी	31/03/2023 तक: (क) रु. 25.82 लाख (ख) रु. 12.64 लाख (ग) रु. 3.99 लाख (घ) रु. 8.56 लाख	(क) रु. 24.95 लाख (ख) रु. 21.22 लाख (ग) रु. 11.25 लाख (घ) रु. 9.9 लाख	(क) रु. 9.93 लाख (ख) रु. 6.74 लाख (ग) रु. 5300 (घ) रु. 6.69 लाख	(क) रु. 19.9 लाख (ख) रु. 18.7 लाख (ग) रु. 16.1 लाख (घ) रु. 3.87 लाख
3.	सृजित व्यक्ति-दिन	31 मार्च 2023 तक 4,826	5227	4171	1254
4.	वास्तविक पर प्रति एकड़ लागत (कुल लागत/तालाब क्षेत्र)	रु. 8.42 लाख	रु. 8.49 लाख	रु. 6.74 लाख	रु. 37.40 लाख
5.	प्रति एकड़ तालाब के लिए व्यक्ति-दिवस (सृजित कुल व्यक्ति दिवस/तालाब क्षेत्र)	3217	2091	4171	2508

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अमृत सरोवरों ने मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) से निधियां प्राप्त की। जहां एक पंचायत ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान से धनराशि जोड़ी, वहीं मंडला के मामले में, होटल और रेस्तरां एसोसिएशन से धनराशि जुटाई गई। वन विभाग ने भी दो अमृत सरोवरों के मामले में वृक्षारोपण में योगदान दिया।

मजदूरी और सामग्री लागत भी परिवर्तनशील पाई गई। ललितपुर के मामले में, मजदूरी लागत में सामग्री का प्रतिशत 32:68 है, मंडला के लिए यह 53:47 है, वारंगल के लिए यह 1:99 है और बागलकोट के लिए यह 81:19 है। परिवर्तनशीलता को स्थलाकृति, महात्मा गांधी एनआरईजीएस कार्यों, मिट्टी के प्रकार, तालाब के आकार और बांधों के सौंदर्यीकरण और मजबूती के संबंध में लंबित कार्यों में अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वास्तविक लागत के आधार पर गणना की गई प्रति एकड़ लागत में भिन्नता देखी जाती है, हालांकि, दोनों उत्तरी राज्यों में, प्रति एकड़ लागत लगभग समान है। बागलकोट में जल-जमाव वाले क्षेत्र में किए गए सीमेंट कार्य, पत्थर की पिचिंग और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के कारण यह काफी ऊंचा है। इस अंतर का कारण सभी चार साइटों में स्थलाकृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं। जहां तक प्रति एकड़ तालाब के लिए व्यक्ति दिवस (सृजित कुल व्यक्ति दिवस/तालाब क्षेत्र) का सवाल है, 2091 से 4171 व्यक्ति दिवस तक का अंतर देखा गया है, जिसे फिर से सभी चार मामलों में भौगोलिक, स्थलीय, मिट्टी के प्रकार, भूजल तालिका स्तर में अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालाँकि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले, खासकर मंडला और वारंगल में, जहाँ आदिवासी आबादी (लाम्बाडी और गोंड) निवास करती है।

तालिका 4

अमृत सरोवरों के जल की उपलब्धता एवं जल का उपयोग

तालिका 4: अमृत सरोवरों की जल उपलब्धता एवं जल का उपयोग					
क्र.सं.	**संकेतक**	**ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**	**मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**	**वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**	**कर्नाटक के बागलकोट में अमृत सरोवर**
1.	क्या अमृत सरोवर कभी एक बार भर गया या नहीं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	जल-संकटग्रस्त क्षेत्र या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र	जल-संकटग्रस्त क्षेत्र	जल-संकटग्रस्त क्षेत्र	जल-संकटग्रस्त क्षेत्र	बाढ़ग्रस्त क्षेत्र
3.	मिट्टी के कटाव में कमी	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4.	क्या अमृत सरोवर से भूजल स्तर में वृद्धि हुई?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	पशुधन एवं वन्य पशु-पक्षियों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	कुओं का पुनर्भरण	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
7.	जिन महीनों के लिए अमृत सरोवर का पानी उपलब्ध था।	6 महीने	कार्य प्रगति पर है	7 महीने	दस महीने
8.	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	50+ एकड़	कार्य प्रगति पर है	30+ एकड़	22+ एकड़

जैसा कि तालिका 4 से देखा जा सकता है, यूपी के ललितपुर, एमपी के मंडला और तेलंगाना के वारंगल में अमृत सरोवरों में पानी लबालब भर गया और वर्ष के दौरान कम से कम एक बार भरा हुआ था जैसा कि प्रमुख सूचनादाताओं द्वारा बताया गया था और जैसा कि एफजीडी प्रतिक्रियाओं से निष्कर्ष निकाला गया है। हालाँकि, बागलकोट में अमृत सरोवर एक पुनर्जीवित तालाब था और इसमें पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता थी। तालाब में पानी की उपलब्धता में अंतर 6 महीने से 10 महीने तक था। यह भी नोट किया गया कि जहां चार अमृत सरोवरों में से तीन जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में थे, वहीं एक बाढ़-प्रवण क्षेत्र में स्थित था।

यह देखा गया कि सभी अमृत सरोवरों में, मिट्टी का कटाव काफी हद तक कम हो गया था और हितधारकों द्वारा सभी चार स्थानों पर जल स्तर में वृद्धि भी दर्ज की गई थी। हालाँकि तालाब के पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता था, इसका उपयोग पशुओं और सिंचाई के लिए किया जाता था। जंगली जानवर और पक्षी भी तालाब का उपयोग करते थे। जबकि कुओं का पुनर्भरण ललितपुर, वारंगल और बागलकोट में देखा गया था, यह मंडला में लागू नहीं था। मंडला में, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि स्पष्ट नहीं थी, हालांकि ललितपुर, वारंगल और बागलकोट में क्रमशः 50, 30 और 22 एकड़ से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई थी।

तालिका 5

अमृत सरोवर के आसपास सुविधाएं

तालिका 5: अमृत सरोवर के आसपास सुविधाएं					
क्र.सं.	**संकेतक**	**ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**	**मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**	**वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**	**कर्नाटक के बागलकोट में अमृत सरोवर**
1.	मनोरंजन सुविधाओं की उपलब्धता	पूर्ण विकसित	अभी भी विकसित किया जाना है	आंशिक सुविधाएं उपलब्ध हैं	अभी भी विकसित किया जाना है
2.	उपयोगकर्ता समूह गठन की स्थिति	अभी बनना बाकी है	अभी बनना बाकी है	बनाया	बनाया
3.	पर्यटन का संवर्धन	अभी तक नहीं	हाँ	अभी तक नहीं	अभी तक नहीं

अमृत सरोवर दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अमृत सरोवरों में तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण होना चाहिए और साइट को बनाए रखने के लिए एक उपयोगकर्ता समूह होना चाहिए। अध्ययन दल ने देखा कि ललितपुर में अमृत सरोवर में बैठने की व्यवस्था की गई थी, साथ ही इंटरलॉकिंग ईंटों का मार्ग, प्रवेश द्वार पर एक मेहराब और वृक्षारोपण किया गया था, जबकि मंडला में काम अभी भी प्रगति पर था, केवल वृक्षारोपण किया गया था। वारंगल में अमृत सरोवर में एक श्मशान, खेल का मैदान, नर्सरी, एक पार्क और डंपिंग और पृथक्करण यार्ड था। बागलकोट में अमृत सरोवर कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ था और इसके चारों ओर पौधे थे। वारंगल और बागलकोट में अमृत सरोवर में क्रमशः बालुचुलाबोड्ड और बिल्वाश्री संजीवनी नाम से उपयोगकर्ता समूह बनाए गए हैं, जबकि अन्य दो तालाबों में, उपयोगकर्ता समूह अभी तक नहीं बनाए गए हैं। चूंकि यह एक नया हस्तक्षेप है, पर्यटन ने अभी तक तालाब स्थलों को नहीं उठाया है, हालांकि मंडला में यह बताया गया था कि मन की बात के बाद, इस स्थल ने उन पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया था जो निकटवर्ती कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी कर रहे थे।

आकृति 1

मन की बात द्वारा त्वरित अमृत सरोवर के प्रभाव का कारण और प्रभाव संबंध

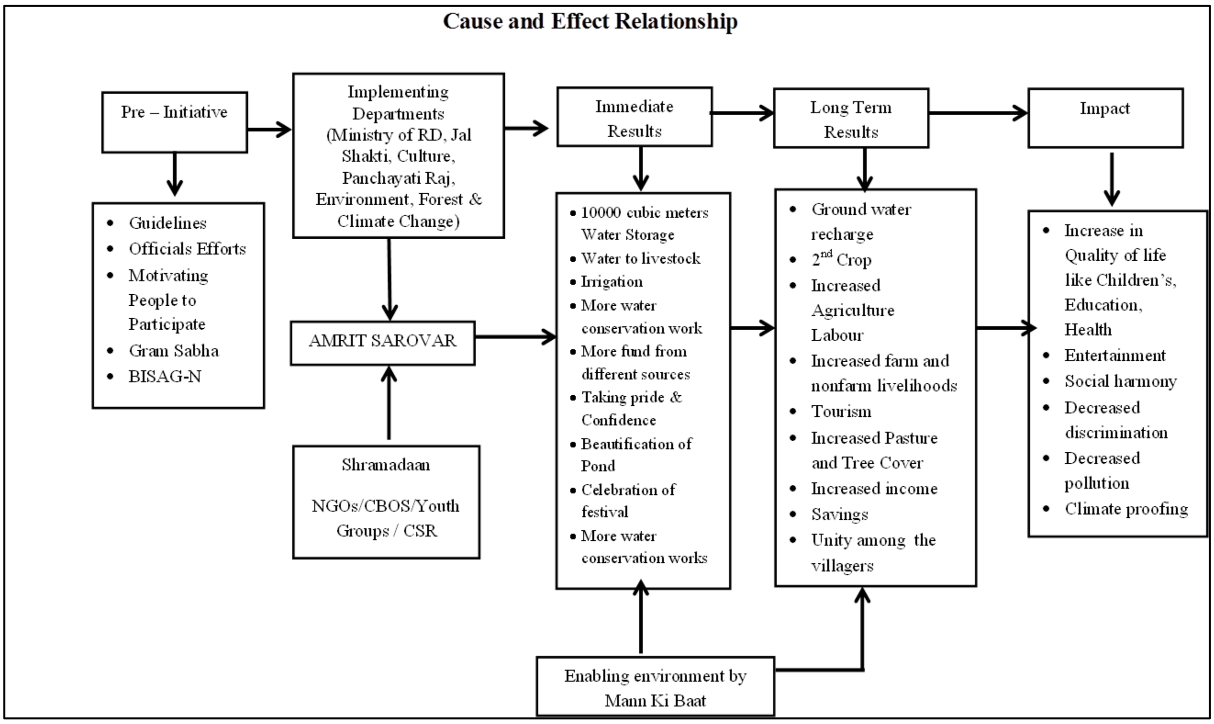

यह आंकड़ा जल संरक्षण तालाब के विकास के तात्कालिक परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे दीर्घकालिक परिणाम मिलते हैं। यह चित्र मन की बात कार्यक्रम के बाद के प्रभाव को दर्शाता है और कैसे अमृत सरोवर के विकास से लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक सद्भाव, प्रदूषण में कमी और जलवायु-सुरक्षा हुई।

तालिका 6

अमृत सरोवरों का प्रभाव

तालिका 6: अमृत सरोवरों का प्रभाव					
क्र.सं.	**संकेतक**	**ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**	**मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**	**वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**	**कर्नाटक के बागलकोट में अमृत सरोवर**
1.	**कृषि पर प्रभाव**				
	क्या अमृत सरोवर से औसत आय बढ़ी?	हाँ	अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है	हाँ	हाँ
	क्या पशुधन पशुओं की संख्या बढ़ी?	हाँ	अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है	हाँ	हाँ
	क्या कृषि	हाँ	अतिरिक्त कार्य	हाँ	हाँ

	योग्य भूमि के विस्तार में वृद्धि हुई है?		प्रगति पर है		
	क्या सिंचाई के कारण खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई है?	हाँ	अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है	हाँ	हाँ

उपरोक्त तालिका अमृत सरोवर के निर्माण के बाद आय, पशुधन, उपलब्ध कृषि योग्य भूमि और परती भूमि पर, जो कि अमृत सरोवर के निर्माण के बाद खेती योग्य थी, प्रभाव को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से अनुमान लगाया जा सकता है, अमृत सरोवर के कारण चार मामलों में आय में 10,000 रुपये से 80,000 रुपये तक की वृद्धि देखी गई। उपलब्ध कृषि योग्य भूमि 150 एकड़ थी और ललितपुर में परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया। मण्डला में कार्य प्रगति पर होने के कारण आय आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी फसल (मक्का) उगाने की संभावना से वारंगल में आय के स्तर में वृद्धि हुई है। 235 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध थी जिसमें तीस एकड़ वर्षा आधारित थी और अमृतसरोवर के निर्माण के बाद चौबीस एकड़ भूमि कृषि योग्य हो गई। बागलकोट में, आय में वृद्धि हुई थी क्योंकि यह बाढ़-प्रवण क्षेत्र था, और अमृत सरोवर के निर्माण से 22.78 एकड़ में फसलों को जल-जमाव से बचाया गया था।

तालिका 7

अमृत सरोवरों के कारण सामाजिक पूंजी संवर्धन

तालिका 7: अमृत सरोवरों के कारण सामाजिक पूंजी संवर्धन					
क्र.सं.	**संकेतक**	**ललितपुर, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर**	**मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत सरोवर**	**वारंगल, तेलंगाना में अमृत सरोवर**	**कर्नाटक के बागलकोट में अमृत सरोवर**
1.	सामाजिक पूंजी का निर्माण (सभाएं, झंडा फहराना, बुजुर्गों/स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों का सम्मान करना/त्योहारों का जश्न मनाना)	ध्वजारोहण किया गया; महिलाओं द्वारा सरोवर पर कार्तिक मास मनाया गया।	जी हाँ, स्वर्गीय मंगलू बैगा के परिवार को इस अवसर पर सम्मानित किया गया है	तीज जैसे त्यौहार मनाये जा रहे हैं; ध्वजारोहण किया गया; वरिष्ठतम नागरिकों का सम्मान किया गया।	ध्वजारोहण किया गया; बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बुजुर्गों का सम्मान और पूर्व सैनिकों ने ध्वजारोहण किया।
2.	क्या इक्विटी संबंधी कोई समस्या है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

सभी चार स्थानों पर अमृत सरोवरों से समुदाय के बीच मजबूत सामाजिक पूंजी का निर्माण हुआ। अध्ययन टीमों द्वारा अमृत सरोवरों से लाभ प्राप्त करने में कोई समानता का मुद्दा नहीं देखा गया। हालाँकि बागलकोट के दस किसानों के मामले में, जो पहले जलभराव की समस्या से पीड़ित थे, मंडला और वारंगल में अमृत सरोवर के विकास से काफी लाभान्वित हुए, संभवतः आबादी में एकरूपता इस सामंजस्य को देखने का एक मजबूत कारण था। वारंगल में, निकटवर्ती तांडाओं के लोग बिना किसी प्रतिबंध के अमृत सरोवर से लाभ उठा रहे थे। अन्य दो स्थानों, यानी ललितपुर और बागलकोट में, हितधारकों ने पशुधन पालन और घरेलू कामों के लिए बिना किसी विवाद के तालाब का उपयोग किया।

विचार-विमर्श

इस लेख में चार अमृत सरोवरों की चर्चा की गई है, जिनका उल्लेख माननीय प्रधान मंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था, और जिन्हें उत्तर प्रदेश के ललितपुर, मध्य प्रदेश के मंडला, तेलंगाना के वारंगल और कर्नाटक के बागलकोट में विकसित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद की अध्ययन टीमों ने इन स्थलों का दौरा किया और खेत तालाबों के निर्माण में सफलता की सीमा और सफलता में योगदान देने वाले कारकों का आकलन किया। अमृत सरोवरों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ उन क्षेत्रों के गांवों को भी काफी फायदा हुआ है जहां जलभराव की समस्या रहती थी। ये तालाब प्रभावी जल संरक्षण संरचनाएं पाए गए, हालांकि कुछ कार्य प्रगति पर हैं और कुछ मामलों में बांधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अमृत सरोवर के हितधारकों ने महसूस किया कि केवल बरसात के मौसम के दौरान ही नहीं, बल्कि पानी की बारहमासी उपलब्धता के लिए चैनलों या जल निकायों के साथ कनेक्शन की आवश्यकता है। अमृत सरोवरों की सफलता और उपयोगिता को देखते हुए, हितधारकों ने जल संसाधनों तक साल भर पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने सामुदायिक खेत तालाबों को गहरा और चौड़ा करने की मांग की। अध्ययन के लिए लिए गए अमृत सरोवरों से भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की नमी बनाए रखने में वृद्धि हुई है, जिससे यह उपजाऊ और खेती योग्य हो गई है और साथ ही आसपास के कुएं भी पानी से भर रहे हैं। अध्ययन में अधिकांश अमृत सरोवरों से पता चला कि पैदावार बढ़ने से किसानों को अमृत सरोवरों से काफी लाभ हुआ है और वे पानी की उपलब्धता बढ़ने के कारण अधिक फसलें उगाने में भी सक्षम हैं। औसत वार्षिक आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सभी चार मामलों में अमृत सरोवर पशुधन, जंगली जानवरों और प्रवासी पक्षियों और ग्रामीणों के घरेलू कामों के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में भी उभरे हैं। अमृत सरोवरों के विकास के लिए धनराशि मुख्य रूप से महात्मा गांधी नरेगा से ली गई है, हालांकि 4 में से 2 मामलों में अतिरिक्त धनराशि अन्य स्रोतों से जुटाई गई थी।

यह देखा गया कि चार अमृत सरोवरों में से तीन नए हैं जबकि चौथा मौजूदा तालाब का कायाकल्प था। सामुदायिक खेत तालाबों के निर्माण की लागत में नए तालाबों के औसत मूल्य के आसपास उचित स्तर की स्थिरता देखी गई। दूसरी ओर प्रति एकड़ व्यक्ति दिवसों में भिन्नता पाई गई और इसे चार मामलों में भौगोलिक और स्थलाकृतिक अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह देखा गया कि अमृत सरोवरों के पूरा होने की अवधि एक महीने से लेकर लगभग एक वर्ष तक थी और उनका आकार 0.5 से

2.5 एकड़ तक भिन्न था। अमृत सरोवरों के विकास के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नीम, पीपल आदि का वृक्षारोपण किया गया, लेकिन 4 में से 2 मामलों में पाया गया कि वृक्षारोपण बढ़ाने की आवश्यकता है। दो स्थानों पर उपयोगकर्ता समूह बन चुके थे और दो स्थानों पर अभी बनना बाकी था। यह देखा गया कि अमृत सरोवरों ने स्थानीय और राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने, झंडा फहराने, बुजुर्गों और सम्मानित लोगों का सम्मान करने के लिए साइट पर इकट्ठा होने वाले लोगों के साथ सामाजिक पूंजी का मजबूत निर्माण किया है। उन्होंने लोगों को साइट पर बेंच वाले पार्क, खुले व्यायामशाला, नर्सरी, ध्वज स्तंभ, श्मशान इत्यादि जैसी सामान्य उपयोगिताओं का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है, और अध्ययन किए गए चार अमृत सरोवरों में से दो का उपयोग मनोरंजन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

अध्ययन से पता चला कि मन की बात के जिक्र से अमृत सरोवर स्थलों के विकास में तेजी आई। हितधारकों में नया उत्साह भरने के अलावा, मन की बात के उल्लेखों ने हितधारकों को विकास पहल में स्वेच्छा से आगे आने के लिए प्रेरित किया है। जबकि अधिकारियों और अन्य हितधारकों के अधिक ध्यान के माध्यम से मन की बात के उल्लेखों से व्यक्तिगत अमृत सरोवरों को लाभ हुआ, इन उल्लेखों ने अमृत सरोवरों के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाकर समुदाय को प्रेरित किया। मन की बात के उल्लेख के चार में से कम से कम दो मामला अध्ययन राज्यों में पहल को मजबूत करने वाले अन्य लाभकारी प्रभाव भी थे, जो अमृत सरोवर के लक्ष्य को दोगुना करने के लिए आगे आए।

निष्कर्ष

अमृत सरोवर जैसे सामुदायिक जल-संरक्षण तालाब जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करके जलवायु-संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिक बार और गंभीर सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसम की घटनाएं होने की आशंका है, जिसका पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ये तालाब महत्वपूर्ण लाभकारी प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी एक प्रमुख मुद्दा है। वे वर्षा जल को संरक्षित और संग्रहीत करने में मदद कर सकते हैं, जिसका उपयोग सिंचाई, घरेलू उपयोग और पशुधन पालन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वे आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जहां अत्यधिक उपयोग या सूखे के कारण भूजल स्तर कम हो गया है। वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहीत करके, ये तालाब भूजल को फिर से भरने और इसे स्थानीय समुदायों के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकते हैं। इन तालाबों के पानी का उपयोग करके, छोटे पैमाने के किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं। अमृत सरोवर निचले क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को भी कम करते हैं। बारिश के पानी को जमा करके और उसे धीरे-धीरे जमीन में रिसने देकर, ये तालाब सतही बहाव की मात्रा को कम करने में मदद कर सकते हैं जो भारी बारिश के दौरान बाढ़ में बदल सकता है।

इन सामुदायिक कृषि तालाबों की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें उचित रखरखाव, प्रभावी सामुदायिक भागीदारी और उचित डिजाइन और प्लेसमेंट शामिल हैं। मन की बात के उल्लेख के बाद, सभी

चार मामलों ने स्थानीय प्रशासन, प्रिंट और प्रेस मीडिया कवरेज, कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है। अध्ययन दल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से मिली मान्यता के कारण लोगों में जल संरक्षण गतिविधियों के लिए आगे आने के लिए नया उत्साह पैदा हुआ है। यह पाया गया कि मन की बात संबोधन ने अमृत सरोवर पहल के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुछ राज्य अमृत सरोवरों की संख्या को लक्ष्य से अधिक बढ़ाने के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, अमृत सरोवर के हितधारकों के बीच न केवल मौजूदा अमृत सरोवर का बेहतर उपयोग करने बल्कि स्थान और समय में अपने कवरेज का विस्तार करने के लिए उत्साह में वृद्धि देखी गई।

लेखकों का योगदान:

जी नरेंद्र कुमार: संकल्पना, विश्लेषण, आलोचनात्मक पुनरीक्षण और अंतिम रूप देना

सोनल मोबार रॉय: डेटा संग्रह, समीक्षा, डेटा विश्लेषण और पेपर का प्रारूपण

दिगंबर ए. चिमनकर, राज कुमार पम्मी, पी. अनुराधा: डेटा संग्रह और समीक्षा

सी. धीरजा: डेटा संग्रह और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन

संदर्भ:

1. Cuenca-Cambronero, M., M. Blicharska, J. A. Perrin, T. A. Davidson , B. Oertli, M. Lago, M. Beklioglu, M. Meerhof, M. Arim, J. Teixeira, L. De Meester, J. Biggs · J. Robin, B. Martin, H. M. Greaves, C. D. Sayer, P. Lemmens, D. Boix, T. Mehner, M. Bartrons, S. Bruc (2023). *Challenges and opportunities in the use of ponds and pondscapes as Nature-based Solutions*. Springer Nature Switzerland, AG.
2. Friesen, J., Rodriguez Sinobas, L., Foglia, L., Ludwig, R. (2017). *Environmental and socio-economic methodologies and solutions towards integrated water resources management*, Science of the Total Environment, 581, 906-908.
3. Gandhi, A. P., &Balamurugan, J. (2017). Mann Ki Baat-Present and Future. *J. MassCommunication*, *4*(1&2), 1-4.
4. Garg, K. (2020). Sentiment analysis of Indian PM’s “Mann Ki Baat”. *InternationalJournal of Information Technology*, *12*(1), 37-48.
5. Giri, N. A., &Tripathi, S. D. (2018). Listenership study of Mann Ki Baat acrossdifferent media. *Mass Communicator: International Journal of Communication Studies*, *12*(3), 4-10.
6. IPCCClimate Change (2014). Impacts, Adaptation and Vulnerability. TechnicalSummary, Inter-governmental Panel on Climate Change.

7. Joy, K. J. and SuhasParanjape. (2004). *Watershed Development Review: Issues and Prospects*, Technical Report, Centre for Interdisciplinary Studies in Environment and Development, ISEC, Bangalore.

8. Manikandan, R. and S. Bhuvanesvari. (2022). *Positive impact of farm ponds in rural livelihood of India.* International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), Volume 10, Issue 2, ISSN: 2320-2882.

9. OIKOS and IIRR. (2000): Social and Institutional Issues in Watershed Management in India, OIKOS, OS, India and International Institute of Rural Reconstruction, Philippines.

10. Rajora, Rajesh. (1998). Integrated Watershed Development: A Field Manual for Equitable, Productive and Sustainable Development, Rawat Publications, Jaipur.

11. Rao, C. S., Rejani, R., Rao, C. R., Rao, K. V., Osman, M., Reddy, K. S., & Kumar, P. (2017). Farm ponds for climate-resilient rain-fed agriculture. Current Science, 471-477.

12. Rao, K. V. et al. (eds). (2010). In Proceedings of National Workshop cum-Brain Storming on Rainwater Harvesting and Reuse through Farm Ponds: Experiences, Issues and Strategies, ICAR-CRIDA and ICRISAT, Hyderabad, 2010.

13. Rao, K.V., Venkateswarlu, B., Sahrawat, K.L., Wani, S.P., Mishra, P.K., Dixit, S., Reddy,K. S., Kumar, M., Saikia, U.S. (Eds.), (2009). *Proceedings of NationalWorkshop-cum-Brain Storming*, 21–22 April, CRIDA, Hyderabad, India.

14. Saxena, S. (2016). Mann kibaat: Radio as a medium of communication by the Indian premier, Narendra Modi. *Asian Politics & Policy*, *8*(3), 520-524.

15. Shankar, P.S.V. (2011). *Towards a paradigm shift in India's rainfed agriculture*. Innovation Development, 1 (2), 321–322.

16. Shao, D., Li, X., Gu, W. (2015). *A method for temporary water scarcity analysis in humid region under droughts condition*. Water Resources Management 29, 3823-3839.

17. Sharma, D., & Dubey, A. D. (2021). The political leader's motivating language use and his perceived effectiveness: The case of Narendra Modi's Mann Ki Baat. *Asian Politics & Policy*, *13*(4), 534-553.

18. Srinivasarao, Ch., Ravindra Chary, G., Mishra, P. K., Nagarjuna Kumar, R., MaruthiSankar, G. R., Venkateswarlu, B. and Sikka, A. K. (2013). Real time contingency planning: initial experiences from AICRPDA. All India Coordinated Research Project for Dryland Agriculture, ICAR-CRIDA, Hyderabad.

***

उत्तराखंड में मनरेगा कार्यान्वयन - एक बहुआयामी स्थानिक विश्लेषण

स्तुति गुप्ता*, शिखा आनंद**, पी. लक्ष्मी थनमई**, के.एम. रेड्डी*** और टी. रविशंकर****

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) दुनिया का सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसका देश में गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक आधार को मजबूत करने में योगदान के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। हालाँकि, कार्यक्रम कार्यान्वयन को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों से जोड़ने वाले अनुसंधान में एक अंतर है, जो सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार इस अध्ययन का उद्देश्य स्थानिक विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके उत्तराखंड राज्य को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, मनरेगा कार्यान्वयन में जिला-स्तरीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। गेटिस-ऑर्ड सांख्यिकी का उपयोग 2017 तक कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित कार्यों की स्थानिक क्लस्टरिंग प्राप्त करने के लिए किया गया था। ओवरले विश्लेषण को सैटेलाइट छवियों-आधारित विषयगत एन्वेलप्स, जैसे भूमि उपयोग भूमि कवर (एलयूएलसी) और इलाके पर सहक्रियात्मक रूप से लागू किया गया था, जो स्थानीय विकास और योजना प्रयासों को आकार देने के अलावा समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन पर एक गुप्त नियंत्रण रखता है। एलयूएलसी और स्थलाकृति ने राज्य में कार्यों के वितरण पर गहरा प्रभाव दिखाया। प्राप्त परिणाम विभिन्न जिलों में कार्य प्राथमिकता और उनके स्थानिक क्लस्टरिंग में उल्लेखनीय भिन्नता दिखाते हैं, इस प्रकार, एक ओर, कार्यक्रम की मांग-संचालित प्रकृति और दूसरी ओर, राज्य की स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ इसके संरेखण का संकेत मिलता है। निष्कर्ष दूरगामी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लाभांश प्राप्त करने की दिशा में राज्य के लिए सुव्यवस्थित योजनाएं तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

मुख्य शब्द: जियोटैग, स्थानिक विश्लेषण, हॉटस्पॉट विश्लेषण, जीआईएस, मनरेगा, उत्तराखंड

प्रस्तावना

दुनिया भर में ग्रामीण आबादी आजीविका संबंधी झटकों और परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील है (डेवेरेक्स, 2001)। व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रम दुनिया भर में लागू किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी कमजोरियों को दूर करने के वैश्विक प्रयासों को बल मिल रहा है (बनर्जी एवं अन्य, 2013)। विकासशील देश आय हस्तांतरण, आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और प्रभावशाली नौकरी बाजारों और टिकाऊ संपत्तियों पर काफी निर्भर हैं (बैरिएंटोस और हुल्मे, 2009)। एक दशक से भी अधिक समय पहले शुरू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) दुनिया के सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक कानूनी तंत्र है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। यह पर्याप्त और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करके प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प का भी समर्थन करता है। ये संपत्तियां समुदाय द्वारा स्वामित्व वाली और बनाई गई किसी वस्तु या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका मूल्य है और स्थानीय क्षेत्र और उसके प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं (बाबू एवं अन्य, 2013)। योजना के तहत प्रतिवर्ष 260 विभिन्न गतिविधियों (एमओआरडी, 2018) के तहत 30,000 से अधिक संपत्तियां बनाई जाती हैं। इन्हें चार मास्टरवर्क श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् श्रेणी क: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से संबंधित सार्वजनिक कार्य, श्रेणी ख: कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति, श्रेणी ग: एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के अनुरूप महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा, और श्रेणी घ: योजना और निगरानी में आसानी के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा (मैककॉर्ड और पॉल, 2019) ।

गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण भारत में प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करने में इसके पैमाने और महत्व को देखते हुए, मनरेगा में निवेश ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं के व्यापक हितों को आकर्षित किया है (बिस्वास, 2015) । इस योजना का इसके सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के बारे में व्यापक अध्ययन किया गया है (बनिंग एंड डी पॉल, 2017, सर्वदे एवं अन्य, 2019) । अहूजा एवं अन्य (2011) ने हरियाणा राज्य में आय और रोजगार सुरक्षा, प्रवासन, ऋण चुकौती और भागीदारी की सीमा पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन किया। बेहतर अवसर और भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तीकरण में योजना का योगदान अच्छी तरह से प्रलेखित है (पेलिसेरी एवं अन्य, 2011; राजलक्ष्मी एवं सेल्वम, 2017)। एस्टेवेसेट अल. (2013) ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कृषि और आजीविका भेद्यता सूचकांकों के ब्लॉक-स्तरीय माप का उपयोग करके योजना के पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभों का अध्ययन किया। रवींद्रनाथ और मूर्ति (2021) ने मनरेगा की कार्बन सिंक क्षमता का अध्ययन किया और भारत में 18 कृषि-पारिस्थितिक सेटिंग्स में मनरेगा के जलवायु शमन सह-लाभों पर प्रकाश डाला। हमारा तर्क है कि जहां मास्टर श्रेणियों क, ख और ग को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण शोध किए गए हैं, वहीं मास्टर श्रेणी घ, यानी ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित लोगों पर स्थानीय और क्षेत्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण घटक

होने के बावजूद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार, मनरेगा कार्यान्वयन को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने वाले शोध में अंतर है, जो सतत विकास के अधिक महत्वपूर्ण वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक और कमी यह है कि अधिकांश उपलब्ध अध्ययन सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) को लागू करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख सूचनादाता सर्वेक्षण, फोकस समूह चर्चा और माध्यमिक डेटा शामिल होते हैं। हालांकि ऐसे तरीकों के संभावित फायदे हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनके गुणात्मक आधार के कारण उन्हें कई पद्धति संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ता है (कैंपबेल, 2001)। उनमें स्थानिक रूप से स्पष्ट प्रतिनिधित्व का भी अभाव है; इसलिए, छोटे नमूने के आकार के कारण इन निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर सामान्यीकृत करना अक्सर सीमित होता है। इस प्रकार, यह माना जाता है कि भूमि उपयोग योजना प्रक्रिया को नीचे से ऊपर की ओर प्रेरित करने के लिए स्थानीय भागीदारी और क्षेत्रीय योजना के बीच सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की अनुमति देने के लिए नए तरीकों की आवश्यकता है (सेडोगो, 2002)।

यह सर्वविदित है कि पृथ्वी पर सभी मानवीय गतिविधियों के अपने स्थानिक पदचिह्न होते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग करके खींची गई छवियां इन पृथ्वी प्रणाली-मानव संबंधों को समझने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार, सैटेलाइट छवियां पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं, इसके पर्यावरण और अंतर्निहित प्रक्रियाओं (टेटम एट अल., 2008) पर महत्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके संसाधन योजना के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट का निर्माण करती हैं (टेटम एवं अन्य, 2008)। भूमि उपयोग भूमि कवर (एलयूएलसी) जानकारी और रिमोट सेंसिंग छवियों से प्राप्त डिजिटल उन्नयन मॉडल लगभग हर पैमाने पर अर्थात् वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर योजना और विकास में सबसे बुनियादी और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इनपुट हैं। जीआईएस उच्च-मूल्य वाली स्थानिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उपग्रह डेटा सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विकास के दृश्य प्रभावों को चित्रित करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है। स्थानिक विश्लेषण का संग्रह सभी प्रकार के डेटा के सुपरइम्पोज़िशन को सुविधाजनक बनाकर छिपी हुई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक विशाल अवसर प्रदान करता है। ये विश्लेषण सरल ओवरले ऑपरेशन से लेकर अधिक सांख्यिकीय उपकरण तक होते हैं जो अधिक पुष्टिकरण या खोजपूर्ण हो सकते हैं (एंसेलिन और गेटिस, 1992) । मनरेगा कार्यान्वयन की स्थानिक जानकारी प्राप्त करने में जीआईएस विश्लेषण लागू करना हाल ही में शुरू किया गया है, जैसा कि कार्यों के स्थानिक क्लस्टरिंग (दिव्या एवं अन्य, 2019) और उनके स्थानिक-लौकिक दृश्य (गुप्ता एवं अन्य, 2020) पर अध्ययन से स्पष्ट है। गुप्ता एवं अन्य (2021) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के साथ योजना के संबंधों की स्थानिक रूप से स्पष्ट मैपिंग का भी अध्ययन किया गया है, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन के उप-राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन और सतत विकास को प्राप्त करने में इसकी भूमिका में इस तरह के विश्लेषण की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मंडला एवं अन्य (2020) ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के गुरला मंडल में मनरेगा के तहत बनाए गए सिंचाई टैंकों के आसपास सुधार की पहचान करने के लिए स्थानिक विश्लेषण का उपयोग किया। हालाँकि, हमारा तर्क है कि मनरेगा और विभिन्न अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और स्थानीय और राष्ट्रीय विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ उनके संरेखण का अध्ययन करने में स्थानिक विश्लेषण दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार यह अध्ययन योजना के स्थानिक पदचिह्नों का आगे विश्लेषण करने, कल्पना करने, तर्क करने और विचार-विमर्श करने के लिए स्थानिक विश्लेषण उपकरणों और मानवीय क्षमताओं को सहक्रियात्मक रूप से लागू करके मनरेगा कार्यान्वयन से जिला-स्तरीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक नया प्रयास है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड को लेते हुए, हमारे अध्ययन का उद्देश्य एमजीएनआरईए के तहत सबसे पसंदीदा कार्यों, ग्रामीण स्तर पर उनके स्थानिक क्लस्टरिंग और भूमि उपयोग और इलाके से संबंधित उनके वितरण को ढूंढना है, जो परियोजना कार्यान्वयन पर एक गुप्त नियंत्रण रखते हैं।

अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन भारत में उत्तराखंड में किया गया है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,484 किमी है। अक्षांश 28º45′ से 31º30′ उत्तर और रेखांश 77º30′ से 81º5′ पूर्व के बीच विस्तारित, यह उत्तर में चीन, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसमें 13 जिले, 31 कस्बे, 95 ब्लॉक और 16,826 गांव शामिल हैं। राज्य का परिदृश्य बेहद विविध है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 103 मीटर से लेकर 7184 मीटर तक है। इसे मोटे तौर पर ऊपरी पहाड़ियों-उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में वर्गीकृत किया गया है; मध्य पहाड़ियाँ -टिहरी-गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोडा और चंपावत, नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र और देहरादून की चकराता तहसील। तलहटी में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले का शेष क्षेत्र शामिल है। औसत वर्षा 1000-2500 मिमी प्रति वर्ष है (काला, 2014), जिनमें से अधिकांश दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान होती है (प्रताप एवं अन्य, 2020)। इसके कुल क्षेत्रफल का 63.42 प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत है, और केवल 12.65 प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है (आईएसएफआर, 2017)। जबकि कृषि लोगों की प्राथमिक आजीविका है, कृषि के अंतर्गत आधे से अधिक क्षेत्र वर्षा आधारित है। कृषि क्षेत्र राज्य में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है, जो कुल पानी की मांग का 75 प्रतिशत है। कई जल स्रोतों के बावजूद, उत्तराखंड के कई जिले ऊर्जा, पर्यटन और शहरी उपयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके असमान वितरण और नियमित विचलन के कारण पानी की कमी का सामना करते हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व क्रमशः 1.01 करोड़ और 189 प्रति वर्ग किमी है। राज्य की साक्षरता दर 79.63 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 88.33 प्रतिशत और 70.70 प्रतिशत है (भारत की जनगणना, 2011)। हालाँकि, राज्य को पहाड़ियों और मैदानों के बीच भारी अंतर के साथ समावेशी विकास की कमी, पुरस्कृत रोजगार की कमी और स्वास्थ्य और शिक्षा तक सीमित या कोई पहुंच नहीं, पीने योग्य पानी तक खराब पहुंच, ठोस अपशिष्ट निपटान, आदि के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षरण जैसी गंभीर समस्याओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में प्राकृतिक आपदाएँ और भूकंप, भूस्खलन और बादल फटने जैसी चरम घटनाएँ आम हैं और इनका सीधा असर पर्यटन पर पड़ता है। फिर भी, अपने शानदार प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए, राज्य में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं।

डाटा और पद्धतियाँ

अध्ययन में प्रयुक्त पद्धति का अवलोकन चित्र 1 में प्रस्तुत किया गया है। राज्य प्रशासनिक सीमा एसआईएस-डीपी परियोजना से प्राप्त की गई थी। 2017 तक कार्यान्वित कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 4,44,369 मनरेगा परिसंपत्तियों का जियोटैग किया गया डेटा भुवन जियो-मनरेगा पोर्टल से प्राप्त किया गया था। हमने शुद्धता, पूर्णता और स्थिरता के लिए डेटा की गुणवत्ता जांच की क्योंकि यह बड़े डेटा का एक आवश्यक पैरामीटर है (ताई और बल्लू, 1998)। जिन अभिलेखों में कार्य श्रेणी के नाम नहीं हैं और जो व्यक्तिगत भूमि श्रेणियों पर काम कर रहे हैं, उन्हें विशेषता तालिका में उपलब्ध उप-श्रेणी के नाम के आधार पर संबंधित कार्य श्रेणियों में मैप किया गया था। तटीय क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत अस्पष्ट रिकॉर्ड सामने आए, जिनमें मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा (एफसीपी) उपायों में शामिल घेरा वृक्षारोपण शामिल थे। अन्य कार्य जैसे कि खाद और तरल जैव खाद के लिए बुनियादी ढाँचा और विविध कार्य (500 से कम परिसंपत्ति गणना वाले), मुख्य रूप से समुदायों को प्रेरित करने के लिए किए गए अर्थात् प्रवेश बिंदु गतिविधि (ईपीए) को एक नई श्रेणी में समूहीकृत किया गया। इस प्रकार, अंतिम विश्लेषण में 11 कार्य श्रेणियों पर विचार किया गया (तालिका 1)।

तालिका 1: उत्तराखंड में मनरेगा परिसंपत्तियों की श्रेणी-वार संख्या

क्र.सं.	**कार्य श्रेणी का नाम**	**परिसंपत्तियों की संख्या**
1.	आंगनवाड़ी/अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा (एओआरआई)	7,059
2.	सूखा निवारण (डीपी)	14,730
3.	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा (एफसीपी)	86,952
4.	भूमि विकास (एलडी)	51,073
5.	सूक्ष्म सिंचाई कार्य (एमआईडब्ल्यू)	14,922
6.	प्रवेश बिंदु गतिविधियाँ (ईपीए)	55,411
7.	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण (आरटीडब्ल्यूबी)	9,582
8.	ग्रामीण संयोजकता	67,762
9.	ग्रामीण पेयजल (आरडीडब्ल्यू)	995
10	ग्रामीण स्वच्छता (आरएस)	89,471
11.	जल संरक्षण और जल संचयन (डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच)	46,412

तालिकाबद्ध डेटा में उपलब्ध भौगोलिक समन्वय जानकारी के आधार पर जीआईएस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके एक बिंदु वेक्टर परत तैयार की गई थी। गाँव की प्रशासनिक सीमा के साथ स्थानिक जुड़ाव करके प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत संपत्तियों की गाँव-वार गणना प्राप्त की गई थी। प्रत्येक जिले में योजना के तहत कार्य प्राथमिकता को दर्शाने के लिए कार्यों की जिलेवार गणना की गई। कार्यान्वित कार्यों (संयुक्त गणना/गांव) के समान स्थानिक घनत्व वाले गांव समूहों को प्राप्त करने के लिए स्थानिक क्लस्टरिंग विश्लेषण किया गया था। मोरन की I तकनीक का उपयोग किसी भी वैश्विक स्तर के क्लस्टरिंग पैटर्न की

उपस्थिति पर प्रारंभिक जांच करने के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण स्थानिक समूहों वाले या उनके बिना वाले क्षेत्रों को गेटिस-ऑर्ड (जीआई*) आंकड़ों का उपयोग करके आगे मैप किया गया था, जो विभिन्न आत्मविश्वास स्तरों पर उच्च (हॉटस्पॉट) और निम्न मान (कोल्डस्पॉट) के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्लस्टर देता है अर्थात् 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत और 99 प्रतिशत (ऑर्ड और गेटिस, 1995) । मॉडल पर अध्ययन क्षेत्र में वन श्रेणियों और बारहमासी बर्फ का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े बहुभुजों के प्रभाव को दूर करने के लिए निश्चित दूरी बैंड विधि लागू की गई है। यह एक निर्दिष्ट महत्वपूर्ण दूरी मान को सुनिश्चित करता है जो कम से कम एक पड़ोसी वाले सभी गांवों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है (सांचेज़-कुएर्वो और एडे, 2013)। ओवरले विश्लेषण का उपयोग करके प्रत्येक स्थानिक क्लस्टर श्रेणी के अंतर्गत गांवों की संख्या की भी गणना की गई थी।

ओवरले विश्लेषण किया गया था, और इलाके (अर्थात ऊंचाई और ढलान) और कार्यान्वित कार्यों के एलयूएलसी-आधारित वितरण प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय आंकड़े प्राप्त किए गए थे। डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) अध्ययन क्षेत्र को कवर करने वाले 14 कार्टोसैट-1 उपग्रह दृश्यों का उपयोग करके तैयार किया गया था, जिन्हें भुवन ओपन डेटा संग्रह से डाउनलोड किया गया था। व्यापक स्तर के विश्लेषण के लिए उन्नयन मानचित्र को चार वर्गों (चित्र 2) में वर्गीकृत किया गया था। ढलान (चित्र 3) को मानक संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वर्गीकरण प्रणाली (पामेला और अन्य, 2018) के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 2016-17 के लिए आईआरएस लिस-III डेटा का उपयोग करके 1:50k के पैमाने पर तैयार किए गए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के राष्ट्रीय संसाधन जनगणना कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए मानचित्र का उपयोग करके भूमि उपयोग भूमि कवर (एलयूएलसी) विश्लेषण किया गया है (चित्र 4)।

चित्र 1:

पद्धति अनुक्रम चार्ट

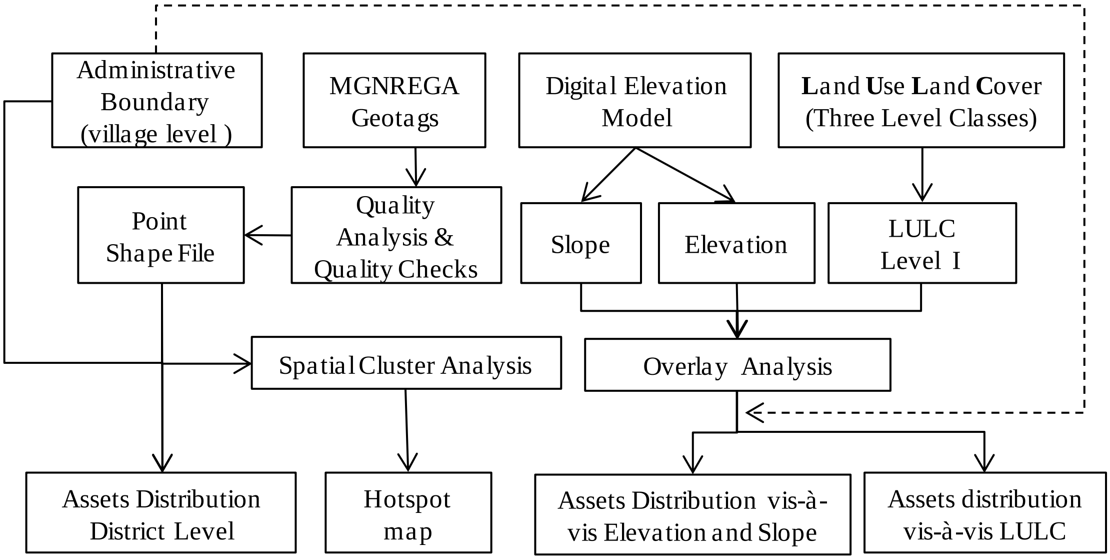

चित्र 2:

उत्तराखंड का डिजिटल एलिवेशन मॉडल (स्रोत: कार्टोडेम)

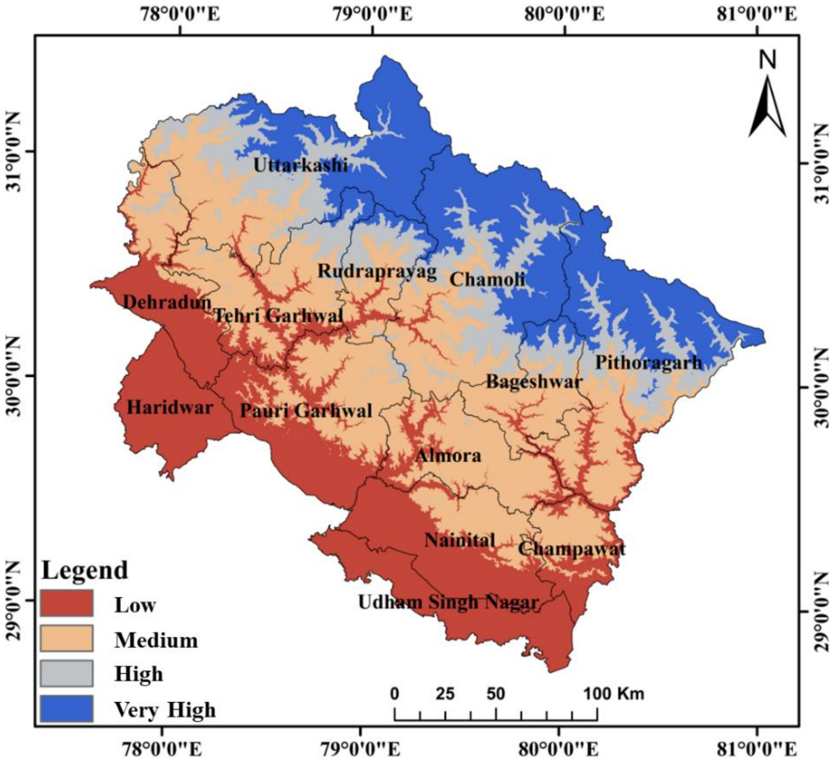

चित्र 3:

उत्तराखंड का ढलान मानचित्र (स्रोत: कार्टोडेम)

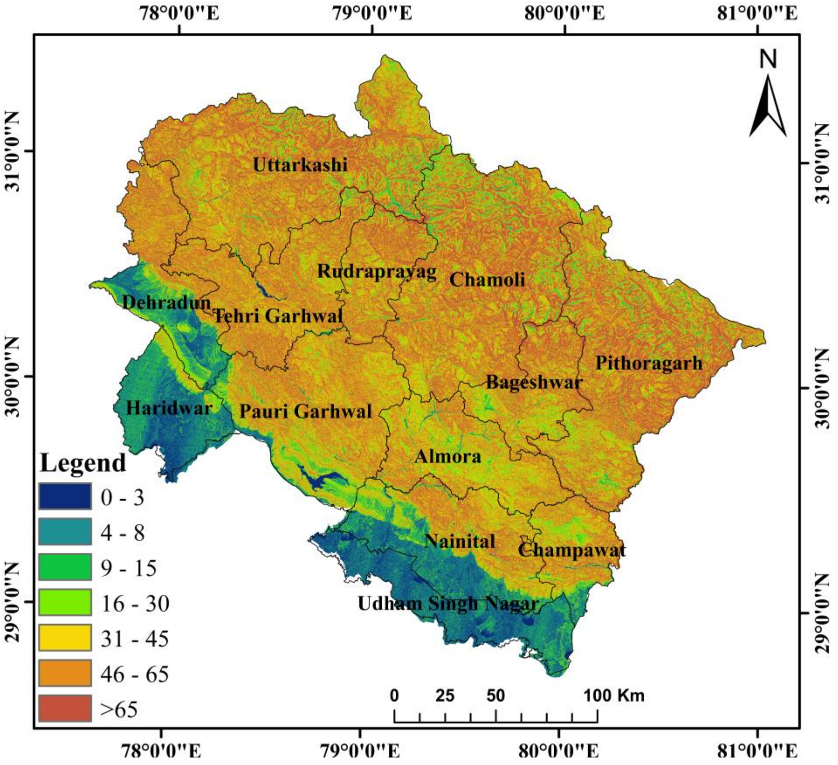

चित्र 4:

उत्तराखंड का भूमि उपयोग एवं समाविष्ट भूमि का मानचित्र (स्रोत: एनएनआरएमएस, एनआरएससी)

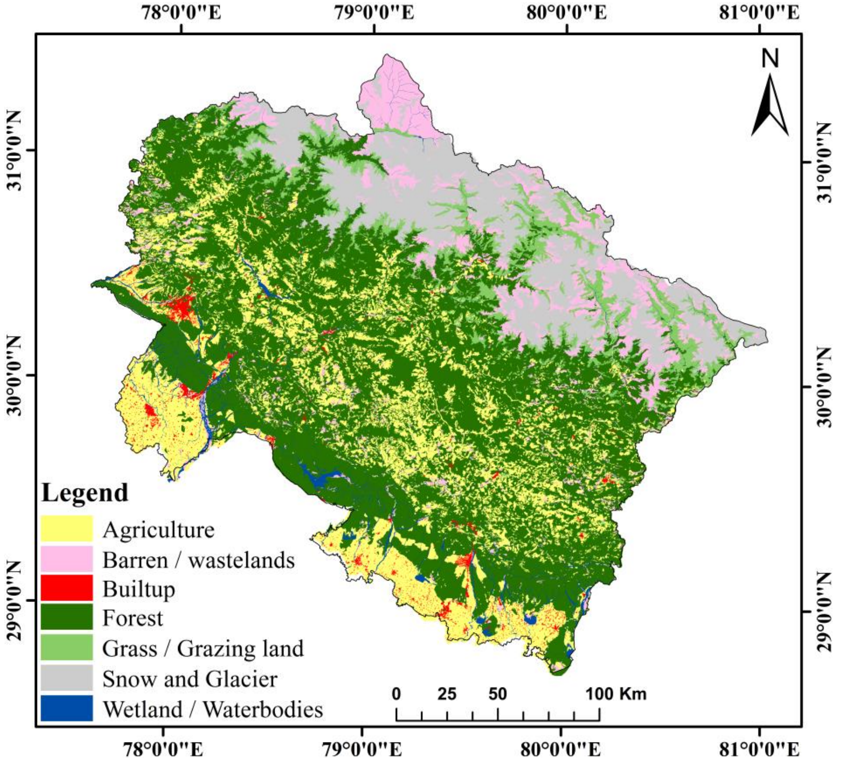

परिणाम

परिसंपत्तियों का विभाजन

उत्तराखंड में मनरेगा कार्यों के समग्र वितरण से पता चलता है कि आरएस सबसे पसंदीदा कार्य श्रेणी है, इसके बाद एफसीपी, आरसी और एलडी हैं। हालाँकि, जिला-स्तरीय प्रदर्शन के मामले में, चमोली अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक कार्यों के साथ पहले स्थान पर है, मुख्य रूप से उत्तरकाशी, जिसमें समान भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद, कार्यों की संख्या लगभग आधी है। योजनाओं को लागू करने में पौडी गढ़वाल और पिथौरागढ दूसरे अग्रणी जिले हैं (चित्र 5)। बारीकी से आकलन करने पर पता चलता है कि ये काम दूर-दराज के गांवों जैसे कि चमोली में माणा और पिथोरागढ़ में कुटी, मुखवा और उत्तरकाशी में लिवाड़ी में भी किए गए हैं (चित्र 6)। एफसीपी चमोली, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में सबसे पसंदीदा काम है। पौडीगढ़वाल और पिथोरागढ़ में एलडी और आरएस को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हमने पाया कि आरएस के बाद आरसी को प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि, नैनीताल और देहरादून में, आरएस मनरेगा के तहत कार्यान्वित सबसे पसंदीदा कार्य प्रकार बना हुआ है। अल्मोडा और चंपावत जिलों में किए गए अधिकांश कार्य डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच श्रेणी में हैं, इसके बाद आरसी और एफसीपी हैं। रुद्रप्रयाग में ईपीए और आरएस प्रमुख कार्य हैं, जबकि बागेश्वर में आरएस और एफसीपी सबसे पसंदीदा हैं। एओआरआई से संबंधित कार्यों को टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में अधिक पसंद किया जाता है। आरडीडब्ल्यू को मुख्य रूप से टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, पिथोरागढ़ और चमोली में पसंद किया गया है।

चित्र 5:

उत्तराखंड में मनरेगा परिसंपत्तियों की जिला स्तरीय गणना

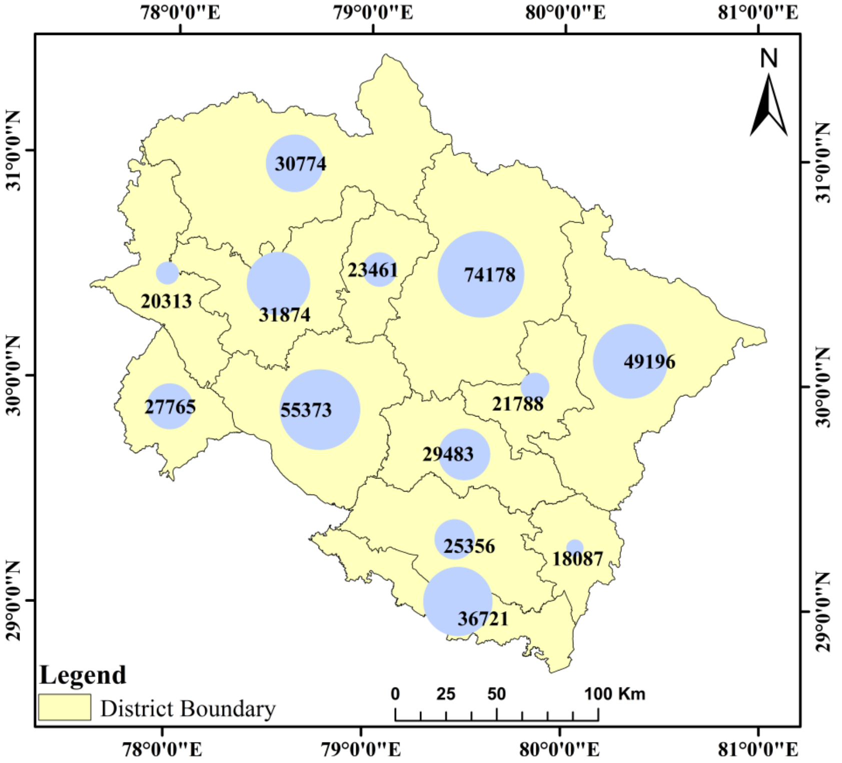

तालिका 2:

जिलेवार क्षेत्र, संपत्ति गणना (घटते क्रम में), और सर्वाधिक पसंदीदा कार्य श्रेणी

क्र.सं.	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	संपत्ति	सर्वाधिक पसंदीदा कार्य श्रेणी
1.	चमोली	8030	74092	एफसीपी (30.8%)
2.	पौडी गढ़वाल	5329	55335	एलडी (21.2%) एवं आरएस (19.5%)
3.	पिथोरागढ़	7090	49127	आरएस (20.9%)
4.	उधम सिंह नगर	2542	36152	आरएस (23.1%) एवं आरसी (21.6%)
5.	टिहरीगढ़वाल	3642	32002	एफसीपी (22.7%)
6.	उत्तरकाशी	8016	30680	एफसीपी (38.9%)
7.	अल्मोडा	3144	29615	डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच (21.4%) एवं आरसी (21.0%)
8.	हरिद्वार	2360	27646	आरएस (31.8%) एवं आरसी (28.3%)
9.	नैनीताल	4251	25820	आरएस (25.9%)
10	रुद्रप्रयाग	1984	23434	ईपीए (23.2%) एवं एफसीपी (19.9%)
11.	बागेश्वर	2241	21780	आरएस (20.3%) & एफसीपी (19.9%)
12.	देहरादून	3088	20440	आरएस (25.9%)
13.	चम्पावत	1766	18045	डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच (20.3%) एवं एफसीपी (19.9%)

चित्र 6:

मानचित्र दृश्य में भुवन से उत्तराखंड का उत्तरी भाग (माणा गांव, चमोली; 2. मुखवा गांव; 3. लिवाड़ी गांव, उत्तरकाशी; 4. कुटी गांव, पिथौरागढ)

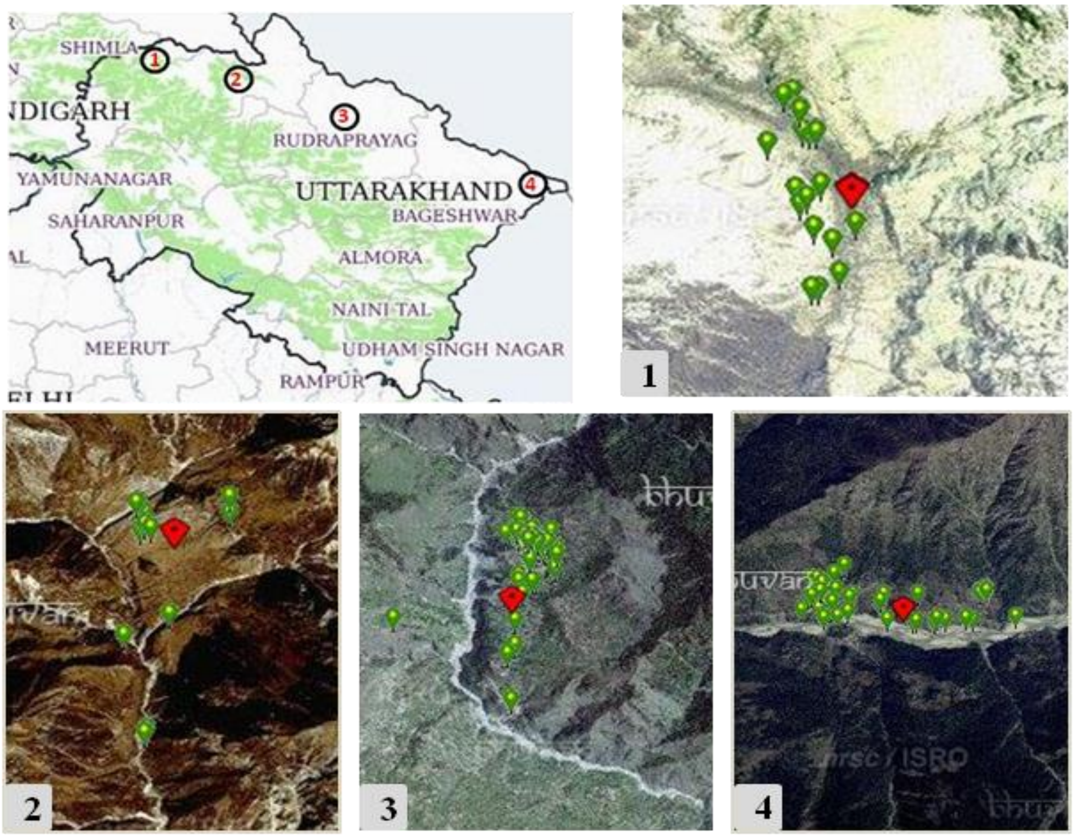

परिसंपत्तियों का स्थानिक समूहन

परिसंपत्तियों के स्थानिक समूहन से सभी जिलों में एक अलग पैटर्न का पता चला। पिथौरागढ, चमोली और बागेश्वर जिलों में बड़े आकार के हॉटस्पॉट देखे गए, जबकि देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, अल्मोडा और टेहरी गढ़वाल में कई अलग-अलग वितरित छोटे आकार के स्थानिक समूह देखे गए (चित्र 7)। देहरादून-उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग-चमोली और बागेश्वर-पिथौरागढ़ की जिला सीमाओं पर काफी बड़े कोल्डस्पॉट देखे गए। टेहरी गढ़वाल, पौडी गढ़वाल और चंपावत जिलों में अलग-थलग और छोटे आकार के कोल्डस्पॉट शामिल हैं। विभिन्न प्रतीति स्तरों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानिक क्लस्टर में गांवों की संख्या (तालिका 3)। 99 प्रतिशत प्रतीति के साथ हॉटस्पॉट के तहत सबसे अधिक गांव पिथौरागढ़ जिले में हैं, इसके बाद टेहरी गढ़वाल और पौडी गढ़वाल हैं। 99 प्रतिशत प्रतीति के साथ कोल्डस्पॉट वर्ग में सबसे अधिक गाँव पिथौरागढ, चमोली और टेहरी गढ़वाल में आते हैं।

चित्र 7:

उत्तराखंड में मनरेगा परिसंपत्तियों का स्थानिक क्लस्टर मानचित्र

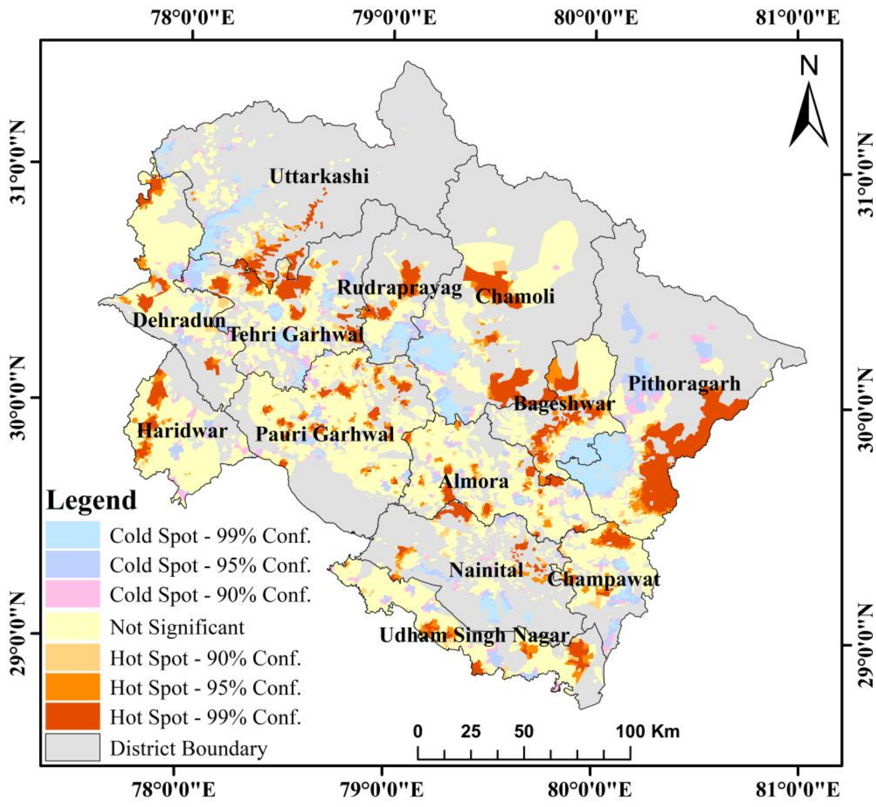

*Conf. stands for Confidence Level

तालिका 3:

विभिन्न प्रतीति स्तरों वाले समूहों के अंतर्गत गांवों की जिलेवार गणना

महत्व के स्तर के साथ स्थानिक क्लस्टर	जिला													
	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	चमोली	देहरादून	हरिद्वार	नैनीताल	पौड़ी गढ़वाल	पिथौरागढ़	रुद्रप्रयाग	टेहरी गढ़वाल	उधम सिंह नगर	उत्तरकाशी	कुल
हॉट स्पॉट 99% आत्मविश्वास	120	123	73	151	44	43	120	163	307	148	260	50	128	**1730**
हॉट स्पॉट 99% आत्मविश्वास	103	76	44	29	19	11	50	162	88	26	52	33	45	**738**
हॉट स्पॉट 99% आत्मविश्वास	58	30	25	38	14	24	34	103	50	10	52	29	18	**485**
महत्वपूर्ण नहीं है	1680	400	410	537	537	482	499	2607	407	263	898	513	299	**9532**

कोल्डस्पॉट 90% आत्मविश्वास	149	8	42	40	43	31	86	194	56	21	163	31	18	**882**
कोल्डस्पॉट 90% आत्मविश्वास	108	32	69	97	48	39	145	160	129	77	240	26	52	**1222**
कोल्डस्पॉट 90% आत्मविश्वास	37	165	26	336	41	0	145	61	593	128	173	4	120	**1829**
कुल	**2255**	**834**	**689**	**1228**	**746**	**630**	**1079**	**3450**	**1630**	**673**	**1838**	**686**	**680**	**16418**

भू-भाग की तुलना में परिसंपत्तियों का विभाजन

उत्तराखंड में भू-भाग में व्यापक भिन्नता इसके जनसांख्यिकीय वितरण, सामाजिक-आर्थिक संरचना और प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण नियंत्रण दर्शाती है। इस समझ के साथ, ऊंचाई और ढलान का उपयोग करके इलाके के संबंध में मनरेगा के तहत कार्यान्वित पसंदीदा कार्यों के वितरण का विश्लेषण किया गया (तालिका 4)। संपत्ति का वितरण तलहटी/कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों (एमएसएल से 100-1100 मीटर ऊपर) में सबसे अधिक है, इसके बाद मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों (एमएसएल से 1101-2400 मीटर ऊपर) का स्थान है, जो राज्य का अधिकतम क्षेत्र है। इसके अलावा, कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिसके लिए इन क्षेत्रों में लगातार बर्फ के आवरण के कारण निर्जन भूभाग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा वितरण स्पष्ट है क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच और कम जनसंख्या घनत्व के मुद्दे हैं। हालाँकि, कार्य श्रेणी से संबंधित इस वितरण को देखने से राज्य के विकास में योजना के योगदान के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। तलहटी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एफसीपी, आरएस और आरसी सबसे पसंदीदा कार्य पाए जाते हैं, इसके बाद मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। हालाँकि, मध्यम उन्नयन में, एलडी और डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच में अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों के माध्यम से राज्य में लचीलापन विकसित करने की दिशा में योजना के संरेखण पर प्रकाश डालते हैं।

इसी तरह, हालांकि उच्चतम ऊंचाई वाले क्षेत्र में बहुत कम कार्य निष्पादित किए गए हैं, वे एफसीपी के लिए स्थानीय प्राथमिकता को उचित रूप से दर्शाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अचानक बाढ़ आना आम बात है। आरसी और आरएस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क संयोजन और स्वच्छता की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने में मनरेगा के योगदान पर प्रकाश डालती है। हालाँकि, आरडीडब्ल्यू के तहत कार्यों पर राज्य के अन्य जिलों में, विशेषकर अधिक ऊंचाई वाले जिलों में काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं।

ढलान वर्गों से संबंधित परिसंपत्तियों का वितरण प्राथमिकता की अलग-अलग डिग्री दर्शाता है। सबसे अधिक संख्या में कार्य मध्यम खड़ी श्रेणी में वितरित पाए गए, उसके बाद पहाड़ी और खड़ी ढलान वाली श्रेणियों में वितरित किए गए (सारणी 5)। ये मुख्य रूप से एफसीपी के अंतर्गत हैं, इसके बाद एलडी और आरसी आते हैं। समतल और लहरदार ढलानों को छोड़कर सभी ढलान वर्गों में एफसीपी सबसे पसंदीदा काम है, जो स्पष्ट

रूप से भूस्खलन को कम करने के लिए ऐसे उपायों के महत्व को दर्शाता है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के नाज़ुक वातावरण में एक आम विशेषता है। आरसी राज्य में तीसरा सबसे पसंदीदा काम, खासकर उतार-चढ़ाव वाले इलाकों में आवागमन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

भूमि उपयोग एवं समाविष्ट भूमि की तुलना में परिसंपत्तियों का विभाजन

उत्तराखंड में, जंगल प्राथमिक भूमि आवरण वर्ग है, इसके बाद कृषि, बर्फ और ग्लेशियर हैं। प्रमुख एलयूएलसी वर्गों के मुकाबले कार्यों की प्राथमिकता को समझने के लिए एलयूएलसी के साथ मनरेगा कार्यों का ओवरले किया गया है अर्थात् कृषि, बंजर/बंजर भूमि, निर्मित, वन, घास/चारागाह भूमि, बर्फ और ग्लेशियर, और आर्द्रभूमि/जल निकाय (तालिका 6)। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकांश कार्य, यानी, 63.48 प्रतिशत, कृषि क्षेत्रों में किया गया क्योंकि वे सामुदायिक स्तर पर निकटता से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण सेट-अप और कृषि आधार के आसपास ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, वन क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण मात्रा में काम (21.74 प्रतिशत) किया जाता है, जो मुख्य रूप से एफसीपी और डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच से संबंधित है। निर्मित क्षेत्रों में आरएस, ईपीए और आरसी सबसे पसंदीदा कार्य हैं।

तालिका 4:

विभिन्न ऊंचाई पर कुल और श्रेणी-वार मनरेगा परिसंपत्तियों का प्रतिशत विभाजन

Elevation (Range in m)	% Area	Assets Count & %	AORI	DP	FCP	LD	MIW	EPA	RTWB	RC	RDW	RS	WCWH
Low (100-1100)	40.26	262003 (59%)	↓	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↑	→
Medium (1101-2400)	29.36	181523 (41%)	↓	↘	↑	↗	↓	↗	↘	↗	↓	↗	↗
High (2401-4100)	10.32	840 (0.2%)	↓	→	↑	→	→	→	↘	↗	↓	↗	↘
Very High (4101-7200)	20.06	0 (0%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Grand Total	100.00	444366 (100%)	↓	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↑	↗

तालिका 5:

विभिन्न ढलान वर्गों में कुल और श्रेणी-वार एमजीएनईआरजीए परिसंपत्तियों का प्रतिशत विभाजन

Slope Classes (Range in %)	% Area	Assets Count & %	AORI	DP	FCP	LD	MIW	EPA	RTWB	RC	RDW	RS	WCWH
Flat (0-3%)	7.47	49668 (11.18%)	↓	↘	↗	↘	→	↑	↓	↗	↓	↑	↘
Undulating (4-8%)	6.39	34403 (7.74%)	↓	↘	↗	→	→	↗	↓	↗	↓	↑	↘
Moderately Sloping (9-15%)	5.02	26855 (6.04%)	↘	↘	↑	↗	→	↗	↓	↗	↓	↗	→
Hilly (16-30%)	12.90	96379 (21.69%)	↓	↘	↑	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↑	↗
Moderately Steep (31-45%)	18.84	125510 (28.24%)	↓	↘	↑	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↗	↗
Steep (46-65%)	26.48	91481 (20.59%)	↓	↘	↑	↗	↘	→	↘	↗	↓	↗	↗
Very Steep (> 65%)	22.88	20073 (4.52%)	↓	→	↑	↗	↘	→	↘	↗	↓	↗	↗
Grand Total	100.00	444369 (100%)	↓	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↑	↗

तालिका 6:

भूमि उपयोग एवं समाविष्ट भूमि की तुलना में कुल और श्रेणी-वार मनरेगा परिसंपत्तियों का प्रतिशत विभाजन

LULC Classes	% Area	Assets Count & %	AORI	DP	FCP	LD	MIW	EPA	RTWB	RC	RDW	RS	WCWH
Settlements	1.23	41323 (9.30%)	↓	↓	↗	→	↘	↑	↓	↗	↓	↑	↘
Wetland / Waterbodies	2.31	6603 (1.49%)	↓	↘	↑	↗	↘	→	↓	→	↓	→	→
Grass / Grazing land	6.97	7697 (1.73%)	↓	↘	↑	→	↓	↗	↘	↗	↓	↗	→
Barren / Unculturable wastelands	8.35	10059 (2.26%)	↓	↘	↗	↗	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↗
Snow and Glacier	13.30	9 (0%)	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↗	↓	↗	↓
Agriculture	20.49	282086 (63.48%)	↓	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↗	→
Forest	47.35	96592 (21.74%)	↓	↘	↗	↗	↘	→	↘	↗	↓	↗	↗
Grand Total	100.00	444369	↓	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↓	↑	↗

↑ : Assets% >= 20; ↗ : Assets% < 20 & >= 10; → : Assets%<10 & > =5; ↘ : Assets% <5 & >= 2; ↓ : Assets %< 2

AORI- Anganwadi/ Other Rural Infrastructure; DP- Drought Proofing; FCP- Flood Control and Protection; LD- Land Development; MIW- Micro Irrigation Works; EPA- Entry Point Activities; RTWB- Renovation of traditional water bodies; RC- Rural Connectivity; RDW-Rural Drinking Water; RS-Rural Sanitation; WCWH-Water Conservation and Water Harvesting

परिचर्चा

जैसा कि हमारे अध्ययन में पाया गया है, उत्तराखंड में मनरेगा कार्यान्वयन एक उल्लेखनीय स्थानिक परिवर्तनशीलता दर्शाता है। यहां तक कि दुर्गम व्यवस्था वाले सबसे दूरदराज के गांव में भी, जियोटैग की उपस्थिति एक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। सबसे पसंदीदा कार्यों के संदर्भ में, हालांकि आरएस, एफसीपी, आरसी और डब्ल्यूसीडब्ल्यूएच सूची में शीर्ष पर हैं, ईपीए और एलडी के तहत काफी काम किए जाते हैं, जो योजना की मांग-संचालित प्रकृति को दर्शाता है। उत्तराखंड बड़ी संख्या में घरेलू और बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करता है (कुमार एवं अन्य, 2015)। इसका लक्ष्य क्रमशः 2024 और 2030 तक भारत के शीर्ष पांच और आगे शीर्ष तीन पर्यटन गंतव्य राज्यों में स्थान सुरक्षित करना है (यूवीडी, 2018)। चूंकि स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के अलावा अच्छी पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने में स्वच्छता और सड़क कनेक्टिविटी सर्वोपरि है, इसलिए आरएस और आरसी कार्यों के लिए उच्च प्राथमिकता समग्र पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में सबसे अधिक संख्या में कार्य किए गए हैं, इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वे व्यस्ततम अवधि के दौरान पर्यटकों की भरमार को आकर्षित करते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में आरएस कार्यों को होमस्टे को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जा सकता है, जो पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण मांग को पूरा करने और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका रणनीति के रूप में उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक संभावित खंड है (मैसेक, 2012)।

अध्ययन में किया गया हॉटस्पॉट विश्लेषण राज्य भर में परिसंपत्तियों के स्थानिक क्लस्टरिंग में एक उल्लेखनीय भिन्नता को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से अकेले परिसंपत्ति गणना के आधार पर अपनाई गई मौजूदा पद्धति की तुलना में मनरेगा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अधिक विश्वसनीय उपाय प्रदान करता है। ऐसे पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों को निर्धारित करने के लिए चयनित समूहों में गहन विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई यह मूल्यांकन कर सकता है कि क्या यह कार्यक्रम की वास्तविक मांग-संचालित प्रकृति के कारण है या विभिन्न स्थानीय अभिनेताओं और निहित स्वार्थों द्वारा समर्थित इसके असंतुलित कार्यान्वयन के कारण है। इसी प्रकार, कार्यक्रम की सफलता से उत्पन्न मांग में कमी, कार्य की आपूर्ति में कमी, या वाल्वों के क्रमिक 'बंद होने' के आधार पर कोल्डस्पॉट का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह का विश्लेषण परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए स्थानिक संदर्भ भी प्रदान करता है। हालाँकि, हम डेटा की प्रकृति और मैपिंग के उद्देश्य पर विचार करते हुए परिणामों को अनुकूलित करने के लिए डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्थानिक विश्लेषण का सावधानीपूर्वक चयन सुनिश्चित करने का सुझाव देते हैं (खालिडियन और मिलर, 2020)। स्थानिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त पैमाने का चयन करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अवलोकन या विश्लेषण के पैमाने में कोई भी बदलाव इकाई के आकार, आकार, रिक्ति आदि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, साथ ही देखी जा रही घटना के सांख्यिकीय संबंधों और परिणामों को भी प्रभावित करता है (डुंगन एवं अन्य, 2002)।

प्राकृतिक और मानवजनित गतिविधियों का संयुक्त प्रभाव उत्तराखंड को देश के सबसे गंभीर आपदा-प्रवण राज्यों में से एक बनाता है (यूएसडीएमए, 2015)। बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जंगलों को काटना राज्य में गंभीर मुद्दों में से एक है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, जंगल के बाहर पेड़ों की वृद्धि के कारण 23 किमी वर्ग की वृद्धि देखी गई है। फिर भी, 2015 से 2017 तक राज्य में चक्रीय कटाई और विकासात्मक गतिविधियों के कारण 49 किमी वर्ग की कमी आई है (आईएसएफआर, 2017)। अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के तहत किए गए एलडी और एफसीपी कार्य राज्य के नाजुक ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं (महापात्रा एवं अन्य, 2018; समरा, 2019; डोभाल एवं अन्य, 2020)। वन क्षेत्रों और ऊपरी इलाकों में ये कार्य तराई क्षेत्रों में विकसित होने वाली कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के तत्वावधान में किए जा रहे प्रयासों को भी उजागर करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की बढ़ती संवेदनशीलता के मद्देनजर, हम अनुशंसा करते हैं कि भविष्य में ऐसे कार्यों और प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

समापन

उत्तराखंड में मनरेगा के कार्यान्वयन से भूमि उपयोग, कवर और इलाके में कार्यों की प्राथमिकता और वितरण में महत्वपूर्ण स्थानिक भिन्नता दिखाई देती है। अध्ययन के निष्कर्ष राज्य के लिए दूरगामी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लाभांश उत्पन्न करने के लिए योजनाओं को आगे तैयार करने और बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। पारंपरिक पीआरए अभ्यासों में आने वाले पूर्वाग्रह को दूर करने के

लिए ऐसे अध्ययनों के लिए स्थानिक उपकरणों के उपयोग की सिफारिश की जाती है। इससे यह जानकारी देने में भी मदद मिलेगी कि क्षेत्र दौरे के दौरान डेटा संग्रह प्रयासों को कहां केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे विशेष रूप से कठिन इलाके में लागत और प्रयासों को कम किया जा सकेगा।

स्वीकृति

हम एमओआरडी के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आभारी हैं। हम इस कार्य को करने के लिए डॉ. पी.वी.एन राव (उप निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन एरिया, एनआरएससी) की निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन को भी स्वीकार करते हैं। हम अज्ञात समीक्षकों को उनके सुझावों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, जिनसे हमें पांडुलिपि को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली।

संदर्भ:

Ahuja, U.R., Tyagi, D., Chauhan, S. & Chaudhary, K.R. (2011). Impact of MGNREGA on Rural Employment and Migration: A Study in Agriculturally-Backward and Agriculturally-Advanced Districts of Haryana. *Agricultural Economics Research Review*, 24(347-2016-16987495-502.

Anselin, L. &Getis, A., 1992. Spatial Statistical Analysis and Geographic Information Systems.*The Annals of Regional Science*, 26(1), 19-33.

Babu, S.V., Dheeraja, C., Kanth, G.R.&Rangacharyulu, S.V. (2013).Frequently Asked Questions on MGNREGA Operational guidelines. New Delhi: Ministry of Rural Development, Centre for Wage Employment and PovertyAlleviation (CWEPA)

Banerji, A. &Gentilini, U. (2013), September. Social Safety Nets: Lessons from Global Evidence and Practice. In Bank of Namibia’s Annual Symposium on Social Safety Nets in Namibia, Windhoek, September (Vol. 26).

Barrientos, A. and Hulme, D., 2009. Social protection for the poor and poorest in developing countries: reflections on a quiet revolution: commentary. Oxford Development Studies, 37(4), pp.439-456.

Biswas, S., 2015. Impact of MGNREGA on Employment Generation and Asset Creation in Rural India-A Critical Review.*International Journal in Management & Social Science, 3*(5), 350-357.

Bunning, S. & De Pauw, E. (2017).Land Resource Planning for Sustainable Land Management.*Land and Water Division Working Paper (FAO) eng no. 14*.

Campbell, J.R. (2001). Participatory Rural Appraisal as Qualitative Research: Distinguishing Methodological Issues from Participatory Claims. *Human Organization, 60*(4), 380-389.

Census of India (2011). New Delhi: Office of the Registrar General and Census Commissioner, India. https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables.

Devereux, S., 2001. Livelihood insecurity and social protection: a re-emerging issue in rural development. Development policy review, 19(4), pp.507-519.

Divya, K., Reddy, K.M., Pujar, G.S. and Rao, P.J., 2019.Assessing the Spatial Patterns of Geotagged MGNREGA Assets on Bhuvan Using GIS-Based Analysis.In Proceedings of International Conference on Remote Sensing for Disaster Management (pp. 227-241).Springer, Cham.

Dobhal, S., Kumar, R., Chauhan, K. and Rawat, P., 2020.Soil and Water Conservation Measures for Sustainable Agroecosystem Development of Uttarakhand. Tropical Forest Research Institute.

Dungan, J.L., Perry, J.N., Dale, M.R.T., Legendre, P., CitronPousty, S., Fortin, M.J., Jakomulska, A., Miriti, M. & Rosenberg, M. (2002).A Balanced View of Scale in Spatial Statistical Analysis. *Ecography, 25*(5),626-640.

Esteves, T., Rao, K.V., Sinha, B., Roy, S.S., Rao, B., Jha, S., Singh, A.B., Vishal, P., Nitasha, S., Rao, S., & IK, M. (2013).Agricultural and Livelihood Vulnerability Reduction through the MGNREGA.*Economic and Political Weekly, 48*(52), 94-103.

Gupta, S., Dharmaraj, T., Reddy, K.M., and Ravisankar, T., 2020. Spatial-Temporal Analysis and Visualisation of Rural Development Works Implemented under the World's Largest Social Safety Program in India—A Case Study. *Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 4*(2), 1-14.

Gupta, S., Anand, S., Thanmai, P.L., Reddy, K.M., &Ravisankar, T. (2021). Spatial Distribution of SDGs Accomplished under MGNREGA beyond SDG1. *International Journal of Rural Management*, p.09730052211037108.

ISFR (2017).India State of Forest Report.Dehradun: Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

Kala, C.P. (2014). Deluge, Disaster and Development in Uttarakhand Himalayan Region of India: Challenges and Lessons for Disaster Management. *International Journal Of Disaster Risk Reduction, 8*, 143-152.

Khaledian, Y. and Miller, B.A. (2020).Selecting Appropriate Machine Learning Methods for Digital Soil Mapping.*Applied Mathematical Modelling, 81*, 401-418.

Kumar, D.S., Rana, G. &Mairaj, H. (2015).Status and Scenario of Tourism Industry in India–ACase Study of Uttarakhand. (Bansal, S.P., Kulshreshtha, S., Gautam PK). Tourism: Inclusive Growth & Sustainable Development. (pp.585-575: Bharti Publications)

Macek, I.C. (2012). Home-stays as Livelihood Strategies in Rural Economies: The Case of Johar Valley, Uttarakhand, India. (Doctoral Dissertation). USA: University of Washington.

Mahapatra, S.K., Reddy, G.O., Nagdev, R., Yadav, R.P., Singh, S.K. & Sharda, V.N. (2018).Assessment of Soil Erosion in the Fragile Himalayan Ecosystem of Uttarakhand, India, Using USLE and GIS for Sustainable Productivity.*Current Science, 115*(1), 108-121.

Mandla, V.R., Nerella, S.P., Choudhary, M. &Peddinti, V.S.S. (2020). Impact Study on De-siltation of Water Tanks in Rural Areas Using Spatial Technology: A Case Study Work under MGNREGA. In Advances in Geotechnical and Transportation Engineering (pp. 85-99).Springer, Singapore.

McCord, A. & Paul, M.H., 2019.An Introduction to MGNREGA Innovations and their Potential for India-Africa Linkages on Public Employment Programming. A Working Paper in GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ).

MoRD, 2018. Mahatma Gandhi NREGS Permissible Works List (Schedule 1 of MGNREG Act 2005). http://nwm.gov.in/sites/default/files/MGNREGS-Work_List.pdf

Ord, J.K., &Getis, A. (1995). Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application. *Geographical Analysis, 27*(4), 286-306.

Pamela, Yukni, A., Imam, S.A. &Kartiko, R.D. (2018, July). The selective causative factors on landslide susceptibility assessment: Case study Takengon, Aceh, Indonesia. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1987, No. 1, p. 020089).AIP Publishing LLC.

Pellissery, S. &Jalan, S.K. (2011). Towards Transformative Social Protection: A Gendered Analysis of the Employment Guarantee Act of India (MGNREGA). *Gender &Development, 19*(2), 283-294.

Pratap, S., Srivastava, P.K., Routray, A., Islam, T. & Mall, R.K. (2020). Appraisal of Hydro-Meteorological Factors during Extreme Precipitation Event: Case Study of KedarnathCloudburst, Uttarakhand, India. *Natural Hazards, 100*(2), 635-654.

Rajalakshmi, V. &Selvam, V. (2017). Impact of MGNREGA on Women Empowerment and Their Issues and Challenges: A Review of Literature from 2005 to 2015. *The Journal of Internet Banking and Commerce, 22*(57),1-13.

Ravindranath, N.H. and Murthy, I.K., 2021. Mitigation co-benefits of carbon sequestration from MGNREGS in India. *PlosOne, 16*(5), p.e0251825.

Samra, J.S., 2019. Rainwater Harvesting and Its Impact on Farming Systems.

Sanchez-Cuervo, A.M. and Aide, T.M., 2013.Identifying hotspots of deforestation and reforestation in Colombia (2001–2010): implications for protected areas.Ecosphere, 4(11), pp.1-21.

Sarvade, S., Upadhyay, V.B., Kumar, M., and Imran Khan, M., 2019.Soil and water conservation techniques for sustainable agriculture.In Sustainable Agriculture, Forest and Environmental Management (pp. 133-188). Springer, Singapore

Sedogo, L.G. &Groten, S.M. (2002). Integration of Local Participatory and Regional Planning: A GIS Data Aggregation Procedure. *GeoJournal, 56*(2), pp.69-82.

Tatem, A.J., Goetz, S.J. and Hay, S.I., 2008. Fifty Years of Earth Observation Satellites: Views from above have Led to Countless Advances on the Ground in Both Scientific Knowledge and Daily Life, *American Scientist, 96*(5), p.390.

Tayi, G.K., & Ballou, D.P. (1998).Examining Data Quality.Communications of the ACM, 41(2), pp.54-57.

USDMA (2015). State Disaster Management Action Plan, Uttarakhand, Disaster Mitigation & Management Centre, Uttarakhand Secretariat. Dehradun

UVD.2018. Uttarakhand Vision Document 2030.Uttarakhand: Institute for Human Development, Department of Planning, Government of Uttarakhand.

क्या भारत में महिलाएं सशक्त हैं? भारत के राजस्थान के लाडनू ब्लॉक से मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का एक परिप्रेक्ष्य

हेमन्त कुमार मिश्रा* और बिजयलक्ष्मी पांडा**

सार

महिला सशक्तिकरण का अर्थ उनके आत्म-मूल्य की भावना और विकल्प चुनने की क्षमता को बढ़ावा देना है जो समाज में सामाजिक प्रभाव पैदा कर सके। इसके अलावा, यह बिना किसी बाधा के अपनी पसंद तक पहुंचने, परिवार और समाज में आर्थिक योगदान देने और विकास की प्रक्रिया में हर जगह समान रूप से प्रतिनिधित्व करने के मामले में परिवार के साथ-साथ समाज में समान जिम्मेदारी साझा करने पर जोर देता है। दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने आजीविका सुरक्षा और संपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने के लिए देश की एक तिहाई महिलाओं को 100 दिनों का काम प्रदान करने का प्रावधान किया है। यह लेख गुणात्मक अनुसंधान के संदर्भ में उनकी बेहतर जीवनशैली के बारे में राजस्थान के लाडनू ब्लॉक के लाभार्थियों के अनुभवों को उजागर करने का प्रयास करता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा अंतराल को पाटने के तरीके सुझाता है। दूसरे शब्दों में, यह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या महिलाएँ, मनरेगा के लाभार्थी के रूप में, कार्यक्रम में योगदान दे रही हैं या नहीं, और बेहतर जीवन शैली बनाए रखने के लिए संपत्ति बना रही हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, राजस्थान के लाडनू ब्लॉक के दो गांवों में 97 उत्तरदाताओं के साथ एक मिश्रित पद्धति लागू की गई। संख्याओं से परिणाम सकारात्मक हैं; हालाँकि, अधिनियम के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार को ग्राम पंचायत (जीपी) के माध्यम से समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने, पारदर्शिता के साथ अधिनियम को कार्यान्वित करने, समय पर भुगतान, मुद्रास्फीति के अनुसार मजदूरी बढ़ाने और मनरेगा के साथ विभिन्न योजनाओं का अभिसरण करने कि दिशा में जीपी सदस्यों को उन्मुख करने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए।

मुख्य शब्द: मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, संपत्ति निर्माण, 100 दिन का कार्य, आजीविका सुरक्षा।

प्रस्तावना:

वर्ष 2005 में संकल्पित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), गरीबी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कल्याण कार्यक्रम है, जिसने विविध अनुभवों के साथ देश के कई गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। यह अधिनियम वर्ष 2006 में 200 जिलों के साथ शुरू हुआ, वर्ष 2007-08 में 130 और जिले जोड़े गए, और बाद में इसे देश भर के अधिकांश जिलों में लागू किया गया। राजस्थान में, इसे अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू किया गया है और इस योजना का नाम बदलकर "मनरेगा-2005" कर दिया गया है। एक तरफ, अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर की आजीविका सुरक्षा और संपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य करता है। इसने न केवल अनगिनत सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है बल्कि व्यवस्था में आगे की उम्मीदों और पारदर्शिता के संदर्भ में चुनौतियां को भी सामने लाया हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन एक सामान्य घटना है, जिसका अध्ययन कई शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। इस तरह के अध्ययनों से पता चला है कि यह कैसे परिवार की आय और खराब स्वास्थ्य, शारीरिक शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और विवाहेतर संबंधों जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। भारतीय प्रवासन हमेशा विकास गतिविधियों और सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचना से आकार लेता है। प्रवासन की यह प्रक्रिया विशेष रूप से गैर-कृषि मौसम के दौरान देखी जाती है जब लोग अपनी आजीविका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे कमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। गरीब परिवारों की आजीविका कमाने के अवसरों को संबोधित करने और संपत्ति बनाने के लिए, मनरेगा में सीमित भौगोलिक क्षेत्र में श्रमिकों को शामिल करके जेंडर-संवेदनशील आय का प्रावधान किया गया है। अध्ययन कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 47 प्रतिशत थी (शाह, 2012; शाह एवं अन्य, 2015), जबकि महिलाएँ अन्य सभी प्रकार के कार्यों की तुलना में योजना में अधिक सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करती हैं (घोष, 2009)। इसके कारण, देश के कई जिलों से आजीविका की तलाश में स्थानीय समुदाय के पलायन की सूचना मिली। साहित्य में दर्ज किया गया है कि मनरेगा में भागीदारी ने अल्पकालिक प्रवासन को काफी कम कर दिया है (इम्बर्ट और पैप, 2014)। कॉफ़ी (2013) ने पाया कि महिलाओं के मनरेगा में शामिल होने की अधिक संभावना है, जिससे उनका अल्पकालिक संकटपूर्ण प्रवासन कम हो जाता है, जिससे उनके बच्चों की भलाई में वृद्धि होती है।

एक अन्य प्रतिष्ठित शोधकर्ता द्वारा किया गया अध्ययन गरीबों के लिए मनरेगा से होने वाली आय की प्रासंगिकता को सामने लाता है (झा एवं अन्य, 2012)। मनरेगा समीक्षा में संकलित शोध अध्ययनों की मुख्य विशेषताएं दर्शाती हैं कि इससे प्रति व्यक्ति मासिक खपत और ग्रामीण परिवारों के व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसने पारंपरिक जेंडर मजदूरी भेदभाव को कम करने में भी योगदान दिया है, विशेष रूप से सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में, और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चला है कि 33 प्रतिशत भागीदारी की वैधानिक आवश्यकता हरियाणा (8 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (13.0 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (9 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (25.0 प्रतिशत), बिहार (13.0 प्रतिशत) और झारखंड (18.0 प्रतिशत) में हासिल नहीं की गई थी (देव, 2012)। नकारात्मक पहलुओं में से

एक यह था कि महिलाएं अपनी 14-16 साल की बेटियों को उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कार्यस्थल पर छोड़ देती थीं और घरेलू काम करने के लिए अपने-अपने घर चली जाती थीं।

एनआरईजीएस भारत में सबसे महत्वपूर्ण "अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम" था। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यह काफी बेहतर काम कर रहा था। राजस्थान में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 68 प्रतिशत है, जो नवंबर 2007 (पूनिया, 2012) के राष्ट्रीय औसत (41.0 प्रतिशत) से 27 प्रतिशत अधिक है। मनरेगा महिलाओं की भागीदारी की व्यावहारिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है क्योंकि वे आर्थिक रूप से अपने परिवारों में योगदान दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता बेहतर हो गई है (कार. एस., 2013)। इन तथ्यों के आलोक में, भारत के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा निर्मित संपत्ति की स्थिति जानने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, लेकिन उनमें से अब तक राजस्थान के लाडनू ब्लॉक को कवर नहीं किया गया है। इसलिए, प्रस्तुत लेख यह समझने में मदद करेगा कि क्या मनरेगा ने महिला प्रधान परिवारों में संपत्ति निर्माण और उनकी जीवनशैली में सुधार करने में मदद की है या नहीं।

क्रियाविधि

2012-13 तक राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी 68.9 प्रतिशत थी; वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए यह क्रमशः 67.7 और 68.2 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 51.3 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए 52.8 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए 54.8 प्रतिशत है। चूंकि अधिनियम मुख्य रूप से जेंडर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करता है कि एक तिहाई महिलाओं को काम मिले, कार्यक्रम में नामांकन के बाद इन महिलाओं को मिलने वाले लाभों को समझने की आवश्यकता है। शोधकर्ता को राजस्थान के लाडनू ब्लॉक के गांवों में महिलाओं की भागीदारी, उनकी समस्याओं और मनरेगा से उनकी अपेक्षाओं से संबंधित कोई अध्ययन नहीं मिला है। उपलब्ध समीक्षा महिला लाभार्थियों के साथ गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके गहन विश्लेषण की कमी को दर्शाती है। इस प्रकार, अध्ययन ने ब्लॉक के दो चयनित गांवों में मनरेगा के परिणामों को समझने की कोशिश की और धर्म, परिवार, पारिवारिक आय, जाति, लिंग, शिक्षा, बचत पर आय का स्रोत और काम की अवधि जैसे स्वतंत्र चर कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। शोधकर्ता ने लाडनू ब्लॉक के गांवों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के कारणों का आकलन और परीक्षण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह अधिनियम के उचित कार्यान्वयन, उच्च मजदूरी, महिलाओं की बढ़ती स्थिति या गांव में सुरक्षित वातावरण के कारण था।

यह अध्ययन मिश्रित पद्धति अपनाकर वर्ष 2013 में आयोजित किया गया था। प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए मामला अध्ययन और फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) के लिए दिशानिर्देश, जांचसूची और संकेतक के साथ एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया था। बीपीएल परिवारों की उच्च सांद्रता और मनरेगा के कार्यान्वयन के कारण दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों से उत्तरदाताओं और गांवों के चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण

नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया गया था। दोनों गांवों में संबंधित ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले 121 बीपीएल परिवारों में से 97 परिवारों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। मनरेगा के लाभार्थियों, सरकारी अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए गए; हालाँकि, यह लेख मुख्य रूप से मनरेगा लाभार्थियों के अनुभवों की जाँच करता है। तुलना और चर्चा के लिए योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग आदि की रिपोर्टों से डेटा के द्वितीयक स्रोतों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, मुद्दों को अधिक पारदर्शी ढंग से समझने के लिए, दोनों गांवों में मनरेगा की महिला लाभार्थियों के साथ चार एफजीडी आयोजित की गईं। एक परिकल्पना के लिए स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध की जांच करने के लिए ची-स्क्वायर और एनोवा का भी उपयोग किया गया था - क्या दिनों की संख्या लाभार्थियों के परिवारों में अधिक आय में योगदान करती है या नहीं। विश्लेषण एसपीएसएस 22.0 संस्करण में किया गया और व्याख्या के बाद तालिकाएँ प्रस्तुत की गईं। कुल मिलाकर, वर्तमान अध्ययन से ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, सामाजिक कार्य पेशेवरों/व्यवसायियों और शिक्षकों को मनरेगा कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान मौजूदा कमियों को समझने और ग्राम पंचायत को योजना को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।

परिणाम और मुख्य निष्कर्ष

मनरेगा जेंडर संतुलन बनाकर समानता लाने वाला सबसे बड़ा कल्याण कार्यक्रम है। पिछले डेढ़ दशक से इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। हालाँकि, कई चुनौतियाँ जस की तस बनी हुई हैं और इसे सफल बनाने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे के परिशुद्ध अनुसंधान से पहुंच और मापनीयता के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन को कारगर बनाने में मदद मिल सकती है। अध्ययन में प्राथमिक उत्तरदाता मनरेगा की 97 महिला प्रतिभागी थीं।

लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा:

तालिका 1 उत्तरदाताओं की सामान्य प्रोफ़ाइल का वर्णन करती है और यह दर्शाती है कि 97 उत्तरदाताओं में से 44 प्रतिशत 30-40 वर्ष की आयु के थे, इसके बाद 32.9 प्रतिशत 40-50 वर्ष की आयु के थे और 11.0 प्रतिशत 20-30 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाता थे। यह पाया गया कि आठ व्यक्ति, जो मनरेगा के तहत काम की मांग कर रहे थे, 50-60 वर्ष की आयु के थे और तीन व्यक्ति 60-70 वर्ष की आयु के थे, जिन्हें कमजोर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद अपने गांवों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। अधिकांश महिलाएँ गृहिणी थीं और अपनी कृषि भूमि पर काम करती थीं। कभी-कभी वे आसपास के गांवों में मजदूरी भी करते थे। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 54.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) से थे और नामांकन के बाद, 91.8 प्रतिशत ने कार्यक्रम में भाग लिया। भागीदारी का यह उच्च प्रतिशत इस कार्य में महिलाओं की अधिक भागीदारी को दर्शाता है। अध्ययन किए गए गांवों के आंकड़ों की तुलना में, यह पाया गया कि बाकलिया गांव में महिलाओं की भागीदारी 82.8 प्रतिशत थी, इसके बाद दुजार गांव में 65.6 प्रतिशत थी, जो लाडनूं शहर के नजदीक है। पुरुष सदस्यों के गाँव से बाहर व्यस्त रहने के कारण पुरुषों की भागीदारी कम थी। आंकड़ों से पता चलता है कि बाकलिया में कम मजदूरी के कारण 17 प्रतिशत पुरुष

सदस्य मनरेगा कार्यों में शामिल थे। अधिनियम के तहत ये कम मजदूरी पुरुष श्रमिकों को काम करने के लिए आकर्षित नहीं करते थी और एक से दो महीने पूरा होने के बाद उन्हें काम से हटा दिया जाता था या उनकी पत्नी कार्य में शामिल हो जाती थी। एफजीडी में, पुरुष उत्तरदाताओं द्वारा यह खुलासा किया गया कि उन्हें मनरेगा कार्यों की तुलना में बाहर बेहतर मजदूरी मिली है (पटनायक, 2020)। हालाँकि, सुरक्षा, गोपनीयता, मजदूरी सुरक्षा और कम जोखिम के कारण महिलाएँ इस कार्य को पसंद करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पास में स्थित कार्यस्थलों ने उनका समय बचाया है और वे संतुष्ट हैं क्योंकि उनके गांवों के परिचित व्यक्ति मनरेगा कार्यों में शामिल हैं।

97 लाभार्थियों में से 54.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थे, उसके बाद 42.3 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से थे। बाकलिया में अनुसूचित जाति (62 प्रतिशत) का वर्चस्व है, उसके बाद ओबीसी (34.5 प्रतिशत) का वर्चस्व है, लेकिन दुजार में, ओबीसी प्रभुत्व वाली जाति (45.6 प्रतिशत) है और उसके बाद अनुसूचित जाति (41.0 प्रतिशत) का स्थान है। सभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को उनकी संबंधित पंचायतों से बीपीएल राशन कार्ड प्राप्त हुए थे। यह पाया गया कि 16.5 प्रतिशत परिवार एकल/महिला प्रधान परिवार थे। आंकड़ों से पता चलता है कि दुजार में 61.8 प्रतिशत परिवार एकल परिवार थे, जबकि बाकलिया में यह 51.7 प्रतिशत था। दोनों गांवों में निवासियों की शैक्षिक स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि अधिकांश महिलाओं को हस्ताक्षर करने का भी ज्ञान नहीं था। इसके चलते गांव तो दूर आसपास के गांवों में भी पूरे साल काम नहीं मिल पाता था। इसके अलावा, यह दर्शाया जा सकता है कि लाभार्थियों की अधिकांश पारिवारिक आय 4000 से 6000 रुपये प्रति माह तक थी। कुल मिलाकर, अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी और मनरेगा की अनियमितताओं ने इन मजदूरी चाहने वालों को काम की तलाश में धकेल दिया, जिससे आजीविका के लिए पलायन हुआ।

तालिका 2 योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य अवधि और समय पर राय को उजागर करती है। इससे पता चलता है कि अधिकांश महिला श्रमिकों ने 30 से 90 दिनों का काम पूरा कर लिया है। केवल 11.0 प्रतिशत ने ही मनरेगा के तहत 100 दिन पूरे किये। बाकलिया गाँव की महिलाओं को दुजार गाँव की तुलना में अधिक दिनों का काम मिलता है। उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि कड़ी मेहनत और कम भुगतान के कारण वे 100 दिनों तक अपना काम जारी नहीं रख सके। महिलाओं के साथ चर्चा से पता चला कि जिनके छोटे बच्चे हैं वे डे-केयर/चाइल्ड-केयर सुविधाओं और शौचालयों की अनुपस्थिति के कारण काम जारी रखने में असमर्थ हैं। अन्य कारणों में स्वास्थ्य समस्याएं, बुढ़ापा, काम शुरू करने के बारे में पूर्व जानकारी का अभाव आदि थे। छियानवे प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें समय पर भुगतान मिला और वे संतुष्ट हैं। हालांकि, बाकलिया गांव के 10 फीसदी लोगों ने समय पर भुगतान नहीं होने के कारण असंतोष जताया है।

विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति की 86.8 प्रतिशत महिलाओं को 0-6000 रुपये की आय मिल रही थी, जबकि ओबीसी और अन्य जातियों की 54.5 प्रतिशत महिलाएं थीं। समानता, मनरेगा नामांकन के परिणामस्वरूप 13.2 प्रतिशत की आय 6000 रुपये से अधिक थी। इसका यह भी निष्कर्ष है कि एकल परिवारों ने संयुक्त परिवार के लाभार्थियों की तुलना में बेहतर आय अर्जित की है जो 6000 रुपये

तक कमा रहे हैं। ची-स्क्वायर परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि विभिन्न जातियों और परिवार की आय के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। हालाँकि, विभिन्न प्रकार के परिवारों के लिए परीक्षण परिणाम महत्वपूर्ण नहीं था। इसका मतलब यह है कि एकल परिवारों और संयुक्त परिवारों में लाभार्थियों की आय में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है।

तालिका 1:

राजस्थान के लाडनू ब्लॉक के अध्ययन किए गए गांवों में उत्तरदाताओं की प्रोफ़ाइल

पृष्ठभूमि विशेषताएँ		बकलिया (एन= 29)	दुजार (n =68)	कुल (n =97)	ची-स्क्वायर मूल्य	पी मूल्य
आयु	20-30 वर्ष	4 (13.8)	7(10.3)	11(11.3)		
	30-40 वर्ष	13(44.8)	30(44.1)	43(44.3)		
	40-50 वर्ष	8 (27.6)	24(35.3)	32(32.9)		
	50-60 वर्ष	3 (10.3)	5 (7.4)	8(8.2)		
	60-70 वर्ष	1(3.3)	2(2.9)	3(3.1)		
जाति	अनुसूचित जाति	18(62.1)	35(51.5)	53(54.6)		
	अन्य पिछड़ी जातियाँ	10(34.5)	31(45.6)	41(42.3)		
	अन्य	1(3.4)	2(2.9)	3(3.1)		
मनरेगा में भागीदारी	पुरुष	5(17.2)	3(4.4)	8 (8.2)	4.422	.035**
	महिला	24(82.8)	65(65.6)	89 (91.8)		
धर्म	हिंदू	27(93.1)	60(88.2)	87(89.7)	.257	.612
	मुसलमान	2(6.9)	8(11.8)	10(10.3)		
पारिवारिक प्रकार	एकल	15(51.7)	42(61.8)	57(58.8)	.846	.35
	संयुक्त	14(48.3)	26(38.2)	40(41.2)		
शिक्षा	निरक्षर	24(82.8)	65(95.6)	89(91.8)		
	साक्षर	1(3.4)	1(1.5)	2(2.1)		
	प्राथमिक तक	3(10.3)	1(1.5)	4(4.1)		
	वरिष्ठ माध्यमिक तक	1(3.4)	1(1.5)	2(2.1)		
परिवार की आय आय के स्रोत	मज़दूर	20(68.7)	55(80.9)	75(77.3)		
	स्वनियोजित	5(17.2)	3(4.4)	8(8.2)		
	सरकारी पेंशन	4(13.8)	10(14.7)	14(14.4)		
परिवारों की आय	4000 से कम	12(41.4)	19(27.9)	31(31.6)		
	4000-6000	9(31.0)	30(44.1)	39(40.2)		
	6000-8000	7(24.1)	16(25.0)	23(24.7)		
		1(3.4)	3(4.4)	4(4.1)		

पृष्ठभूमि विशेषताएँ		बकलिया (एन= 29)	दुजार (n =68)	कुल (n =97)	ची-स्क्वायर मूल्य	पी मूल्य
	अधिक 8000					
नई आय	1-6000 आईएनआर	21(30.0)	49(70.0)	70(72.2)	.001	.972
	6000 से ऊपर	8(29.6)	19(70.4)	27(27.8)		

स्रोत: लेखकों द्वारा एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा।

तालिका 2

राजस्थान के लाडनू ब्लॉक में कार्य, अवधि एवं समय पर भुगतान पर राय का विभाजन

प्रतिक्रिया वर्ग	बकलिया एन=29	दुजार एन=68	कुल एन=97
कार्य की अवधि			
30 दिन से कम	1 (3.4)	2 (2.9)	3 (3.1)
30 दिन से 90 दिन तक	21 (72.4)	62 (91.2)	83 (85.6)
100 दिन पूरे हुए	7 (24.1)	4 (5.9)	11 (11.3)
समय पर भुगतान			
हाँ	26 (89.7)	67 (98.5)	93 (95.9)
नहीं	3 (10.3)	1(1.5)	4 (4.1)
कुल	**29 (100)**	**68 (100)**	**97(100)**

स्रोत: लेखकों द्वारा एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा।

तालिका 3:

जाति, आय के साथ लाभार्थियों के परिवार के प्रकार के बीच ची-स्क्वायर का परिणाम

संकेतक		0-6000 आईएनआर	>6000 आईएनआर	कुल	x2 मूल्य	पी मूल्य
जाति	अनुसूचित जाति	46 (86.8)	7 (13.2)	53 (100.0)	12.446	.000***
	ओबीसी एवं अन्य	24(54.5)	20(45.5)	44 (100.0)		
परिवार का	एकल	41 (71.9)	16 (28.1)	57 (100.0)		

संकेतक		0-6000 आईएनआर	>6000 आईएनआर	कुल	x2 मूल्य	पी मूल्य
प्रकार	संयुक्त	29 (72.5)	11 (27.5)	40 (100.0)	.004	.951

पियर्सन ची-स्क्वायर मूल्य है 12.446 (p=.000), $P < 0.05$

****p<0.001, **p<0.05, *p<0.10*

इसके अलावा, अध्ययन में काम की अवधि (30 दिन से कम, 30-90 दिन और पूरे 100 दिन) और आश्रित चर के रूप में लाभार्थियों की आय नामक दो चर के साधनों के बीच अंतर की तुलना करने की कोशिश की गई। एक-तरफ़ा एनोवा का प्रदर्शन किया गया और परिणाम $F(1, 95) = 5.505$, $p<.05$ दर्शाता है कि दो चयनित चर, अर्थात् कार्य की अवधि और पारिवारिक आय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसका मतलब है कि मनरेगा के तहत अधिक कार्य दिवस उन लाभार्थियों के लिए अधिक आय की सुविधा प्रदान करते हैं जिनके पास अन्य दो श्रेणियों की तुलना में 100 दिनों का काम था। इसलिए, कार्यान्वयनकर्ताओं को अध्ययन क्षेत्र में सभी को 100 दिन का काम प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए (तालिका 4 और 5)।

तालिका 4

कार्य की अवधि और लाभार्थियों की कुल घरेलू आय के बीच वर्णनात्मक आँकड़े

कार्य की अवधि								
					माध्य के लिए 95% विश्वास अंतराल			
पारिवारिक आय	एन	माध्य	मानक व्यतिक्रम	मानक त्रुटि	निचली सीमा	ऊपरी सीमा	न्यूनतम	अधिकतम
0-6000	70	2.03	.339	.041	1.95	2.11	1	3
6000 से ऊपर	27	2.22	.424	.082	2.05	2.39	2	3
कुल	97	2.08	.373	.038	2.01	2.16	1	3

स्रोत: लेखकों द्वारा एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा।

तालिका 5

कुल पारिवारिक आय के साथ कार्य की अवधि के लिए एनोवा परिणाम

कार्य की अवधि	वर्गों का योग	डीएफ	माध्य वर्ग	एफ	Sig.
समूहों के बीच	.731	1	.731	5.505	.021***
समूहों के भीतर	12.610	95	.133		
कुल	13.340	96			

आश्रित चर: परिवार की आय।

स्रोत: लेखकों द्वारा एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा।

तालिका 6 राजस्थान के लाडनू ब्लॉक में मनरेगा से संबंधित जानकारी के स्रोतों को दर्शाती है। लाभार्थियों ने उल्लेख किया कि उन्हें योजना के बारे में पड़ोसियों और दोस्तों (69.0 प्रतिशत) से पता चला और यह जानकारी का प्रमुख स्रोत था। आगे तुलना करने पर पता चला कि बकलिया गांव में 20 फीसदी महिलाओं को इस योजना के बारे में जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली। महिला लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें मनरेगा के तहत काम के बारे में ग्राम पंचायत से कोई सूचना नहीं मिली। इसलिए, मनरेगा जॉब कार्ड धारक काम से अनभिज्ञ थे और इस प्रक्रिया में देर से शामिल हुए। इस संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभाव मूल्यांकन के अध्ययन से भी इसी तरह के निष्कर्ष सामने आए। लाभार्थी मनरेगा के बारे में जानते थे और उन्होंने इस योजना के बारे में सुना था लेकिन अधिनियम के प्रावधानों से अनभिज्ञ थे। यह बताया गया कि अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोई होर्डिंग्स नहीं लगाए गए, पदयात्रा या नुक्कड़ नाटक आयोजित नहीं किए गए। लाभार्थियों ने कहा कि भुगतान न्यूनतम मजदूरी से कम है, जबकि उनमें से आधे ने प्रति दिन 60 रुपये मिलने की बात कही। उन्हें कम भुगतान के कारणों के बारे में बहुत कम जानकारी थी और पंचायत सदस्य उन्हें कभी इसके बारे में सूचित नहीं करते थे।

तालिका 6

राजस्थान के लाडनू ब्लॉक में मनरेगा के बारे में जानकारी के स्रोत

प्रतिक्रिया वर्ग	बकलिया एन=29	दुजार एन=68	कुल एन=97
पंचायत	5(17.2)	8(11.8)	13(13.4)
दोस्त और पड़ोसी	17(59.6)	50(73.5)	67(69.1)
मिडिया	1(3.4)	3(4.4)	4(4.1)
आंगनवाड़ी केंद्र	6(20.7)	7(10.3)	13(13.4)
कुल	**29 (100)**	**68(100)**	**97(100)**

स्रोत: लेखकों द्वारा एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा।

महिला सशक्तिकरण हमेशा घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और संपत्ति निर्माण में निर्णय लेने की बात करता है। अध्ययन में प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त धनराशि के मुकाबले उनकी व्यय पद्धति को समझने की कोशिश की गई और निष्कर्ष को तालिका 4 में संक्षेपित किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि बकलिया गांव में महिलाएं अपनी मजदूरी का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू संपत्ति (89.7 प्रतिशत) खरीदने के लिए कर रही थीं और इससे उन्हें अपने परिवार की दैनिक जरूरतों (86.2 प्रतिशत) को पूरा करने में भी मदद मिली। लेकिन दुजार गांव में 91 फीसदी महिलाएं अपनी मजदूरी का इस्तेमाल अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में करती थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेशनरी के सामान, अपने बच्चों की शिक्षा फीस और दवा पर खर्च

किया। पहले, वे हर चीज़ के लिए अपने पति की आय पर निर्भर थीं; अब, वे अपने आय स्रोत को लेकर उत्साहित महसूस करते हैं।

दुजार गांव में, 66 प्रतिशत महिलाएं गांव से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाडनूं शहर की नियमित यात्रा के लिए परिवहन सुविधा का उपयोग करती हैं, और वे कृत्रिम आभूषणों, कपड़ों और खाद्य पदार्थों पर पैसा खर्च करती हैं। महिलाओं ने दूसरों से बात करने में कोई झिझक नहीं दिखाई और वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए स्वतंत्र रूप से लाडनूं के सरकारी अस्पताल और निजी क्लीनिकों में भी जा रही हैं। अनुभवों को साझा करना महिलाओं में देखा गया बड़ा बदलाव था। देव (2012) ने चर्चा की कि मनरेगा से होने वाली आय ने बच्चों की भलाई जैसे भूखमरी कम करने और स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्पल और भट्टाचार्य ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 17.3 प्रतिशत लाभार्थियों (जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं) ने कहा कि यह योजना उन्हें गांव के भीतर काम करने देती है और साथ ही साथ सुरक्षित रूप से कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी पैदा करती है (डे एवं भट्टाचार्य, 2013)। इसके अतिरिक्त, महिलाओं द्वारा मनरेगा में शामिल होने का मुख्य कारण कम कार्यभार के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का विकल्प था (तालिका 7)। आय से बचत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब हतोत्साहित करने वाले थे। लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा, यानी दोनों गांवों में 93.8 प्रतिशत, अपर्याप्त भुगतान और दैनिक जीवन में किए गए व्यय के कारण मनरेगा से प्राप्त धनराशि को बचत करने में असमर्थ थे। बचत की कमी के कारण वे कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। लेकिन इसके विपरीत, एक अध्ययन के निष्कर्षों में कहा गया है कि मनरेगा महिला श्रमिकों (30 प्रतिशत) के कर्ज के बोझ को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है, लेकिन अर्जित राशि कर्ज चुकाने के लिए अपर्याप्त है (बोरा और बोरदोलोई आर., 2014)। इस पर और अधिक व्यवस्थित तरीके से शोध करने की जरूरत है।

तालिका 7

मनरेगा के तहत अर्जित धन के उपयोग और बचत के संबंध में प्रतिक्रियाएँ

प्रतिक्रिया वर्ग	**बकलिया एन=29**	**दुजार एन=68**	**कुल एन=97**
व्यय के मुख्य क्षेत्र*			
दैनिक आवश्यकताएं	25 (86.2)	62(91.2)	87(89.7)
दवाइयाँ	9(31.0)	10(14.7)	19(19.6)
परिसंपत्तियों का निर्माण	26(89.7)	25(36.8)	51(52.6)
बच्चों की शिक्षा	11(37.9)	23(33.8)	34(35.1)
अन्य (निर्दिष्ट करें)	10(34.5)	45(66.2)	55(56.7)
बचत			
हाँ	4(13.7)	3(4.4)	5(5.2)
कोई बचत नहीं	25(86.2)	65(95.6)	91(93.8)
कुल	**29 (100)**	**68(100)**	**97(100)**

स्रोत: लेखकों द्वारा एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा।

*एकाधिक प्रतिक्रियाओं के कारण, जोड़े जाने पर वितरण 100 प्रतिशत नहीं होगा।

इसके अलावा, प्रवासन की स्थिति को समझने के लिए समुदाय के सदस्यों की राय का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि मनरेगा कार्यों के दौरान महिलाओं के प्रवासन में कमी आई है। महिलाओं ने काम की तलाश में आसपास के शहरी इलाकों में जाना बंद कर दिया था और इससे उनका शारीरिक शोषण भी कम हो गया था। शहरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिलाएं लंबे समय तक काम करने और तनाव के कारण खराब स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित होती हैं। मनरेगा में वे अपने गांव से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर ही काम कर सकते थे। यदि दूरी पांच किमी से अधिक है, तो वे प्रति दिन मजदूरी के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पैसा कमा रहे थे। इस कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में, महिला लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें हमेशा पैसे के लिए पहले की तरह पति से भीख नहीं मांगनी पड़ती है। चार महिलाओं ने बताया कि वर्ष 2012 के दौरान मनरेगा में काम करते हुए उन्होंने 5000-7000 रुपये कमाए थे, जिसका उपयोग उन्होंने आभूषण खरीदने में किया। एफजीडी से प्राप्त ये प्रतिक्रियाएं असम में पांच जिलों में 40 ग्राम पंचायतों में फैले 400 एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों (लक्षित समूह) और 400 गैर-श्रमिकों (नियंत्रण समूह) के साथ किए गए एक हालिया अध्ययन में प्राप्त उत्तरों के समान थीं। 81 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों ने स्वीकार किया कि मनरेगा ने उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में 88 प्रतिशत लोगों की राय थी कि मनरेगा ने उन्हें कुछ हद तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। 73 प्रतिशत सदस्यों ने पुष्टि की कि उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जबकि नियंत्रण समूह के 60 प्रतिशत के बच्चे स्कूलों में जाते हैं (पांडा, 2015)।

दुजार गांव में एफजीडी के दौरान, महिला लाभार्थियों ने कहा कि वे लाडनूं शहर की यात्राओं के अलावा सब्जियां, स्टेशनरी सामान और कपड़े खरीदने के लिए सप्ताह में दो बार बाजार का दौरा कर रही थीं। परिवहन सेवाओं की निरंतर उपलब्धता के कारण उनके लिए परिवहन शुल्क के रूप में 10 रुपये का भुगतान करके शहर का दौरा करना आसान था। बताया गया कि कार्यस्थल पर निर्धारित मात्रा में काम पूरा नहीं होने के कारण महिलाओं को प्रति दिन 60 से 90 रुपये मिल रहे थे। इसके अलावा, धनराशि का उपयोग संपत्ति और कपड़े खरीदने के लिए किया गया था, जिसका अर्थ है कि मनरेगा का अवैतनिक कार्यों को भुगतान किए गए कार्यों में बदलने और घरेलू मामलों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका के दायरे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले वे पंचायत की बैठकों या अन्य योजनाओं से अनभिज्ञ थे। लेकिन अब, वे शंकाओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत का दौरा करते हैं और अक्सर ग्राम पंचायत कार्यालय में मासिक बैठक में भी भाग लेते हैं।

ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार के दौरान, यह पाया गया कि कार्यक्रम ने केवल मनरेगा कार्यों के दौरान प्रवासन को कम करने में योगदान दिया है। इस कार्यक्रम से ग्रामीणों में सहयोग एवं समन्वय की भावना भी आयी। मणिपुर के एक क्षेत्र रिपोर्ट से पता चलता है कि गरीबों की खपत में कुछ सुधार हुआ है, संकटपूर्ण प्रवासन में कमी आई है और महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है (सिंह एवं सिंह के.टी., 2013)।

दुजार स्थित पंचायत कार्यालय में मनरेगा के अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) से भी चर्चा की गयी। उन्होंने कहा कि मनरेगा हर साल 'जुलाई से अक्तूबर' तक स्थगित रहता है क्योंकि महिलाएं कृषि भूमि पर काम

करने में व्यस्त रहती हैं। बारिश के डर के कारण वे नवंबर के दौरान काम करने में रुचि नहीं रखते हैं। इस अवधि के दौरान, ग्रामीण पूरी तरह से अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। जिन व्यक्तियों ने 100 दिन का काम पूरा कर लिया था, वे बिना किसी रुकावट के अपनी निरंतर भागीदारी के लिए सरकार से प्रोत्साहन के रूप में 2100 रुपये की अतिरिक्त राशि पाने के हकदार थे। लाभार्थियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए जॉब कार्ड जारी किए गए। अधिकारी ने यह भी बताया कि दुजार सब्जियां उगाने के लिए प्रसिद्ध था, और इसकी आपूर्ति लाडनूं शहर के निवासियों को की जाती थी। कुछ महिलाएँ अपने उपभोग के लिए सब्जियाँ उगाने के साथ-साथ दूसरों के कृषि क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं। इसलिए, ग्रामीण मनरेगा में काम करने के बजाय दोहरा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने खेतों में काम करना पसंद करते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। बुजुर्ग महिलाओं और शिशुओं वाली विवाहित महिलाओं ने काम की मांग की लेकिन उन्होंने कभी भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया। महिलाएँ कुछ हद तक काम कर सकती थीं; हालाँकि, उन्होंने पूरी मज़दूरी पाने के लिए शिकायतें दर्ज कीं। साथ ही कार्यस्थल पर शिशुगृह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी।

एमजीएनईआरजीएस से प्राप्त लाभ के कारण बीपीएल परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। कभी-कभी, वे बाज़ार से भोजन खरीद लेते थे। इसके विपरीत, पलामू जिले के कुसुमाटांड़ गांव की जग देवी द्वारा रिपोर्ट किए गए झारखंड में रोजगार गारंटी: जमीनी हकीकत पर अध्ययन (भाटिया एंड वीकली, 2006) का कहना है कि यह योजना जीवन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं ला सकी। जो लोग पहले साग और कंदमूल खाकर गुजारा करते थे, वे आजकल भी वही खा रहे हैं।

मामला अध्ययन

लाडनूं ब्लॉक के बकलिया गांव की मुस्लिम समुदाय की 45 वर्षीय अनपढ़ विधवा सुमन अपने एकल परिवार यानी 25 और 18 साल के दो बेटों के साथ रहती थी। वह अपने अर्ध-पक्के घर में रह रही थी, जिसमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। 25 रुपये की दैनिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वह अन्य ग्रामीणों की भूमि पर काम करती थी और अपनी सुरक्षा और उचित परिवहन शुल्क के डर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। बड़ा बेटा शादीशुदा था और मजदूरी करता था, जबकि छोटा बेटा, जो 70 प्रतिशत चलने-फिरने में अक्षम था, अपनी शिक्षा जारी रख रहा था। कुछ साल पहले, उनका बड़ा बेटा जो बेहतर मजदूरी की तलाश में जयपुर शहर चला गया था, परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए गाँव लौट आया।

वर्ष 2010 में, गाँव के एक व्यक्ति, जो सरपंच और ग्राम सेवक के साथ अच्छे संबंध रखता है, ने उसे इस वर्तमान अध्ययन से दो साल पहले बीपीएल सूची में पंजीकृत होने में मदद की। योजना के लिए अपना नाम पंजीकृत करने से पहले, वह मनरेगा के विस्तृत प्रावधानों से अनभिज्ञ थी और ग्राम बैठक के दौरान अपने पुरुष समकक्षों के साथ अपनी समस्याओं को साझा करने में झिझकती थी। पहले उन्हें बाजार से 18 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर गेहूं खरीदना पड़ता था। कभी-कभी, आपात्कालीन स्थिति से निपटने के लिए, उसे गाँव वालों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। उनके सबसे छोटे बेटे को पिछले दो वर्षों से विकलांगता पेंशन

योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, जिसका उपयोग उन्होंने विशेष रूप से उसकी शिक्षा के लिए किया। घर के बाकी काम-काज और जरूरतें विधवा पेंशन योजना से पूरी होती थीं।

बीपीएल सूची में नाम दर्ज होने और 100 दिन रोजगार योजना के तहत काम मिलने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया। योजना के तहत प्रथम वर्ष की आय 10000 रूपये थी; उनके ख़राब स्वास्थ्य के कारण दूसरे वर्ष में यह घटकर 4000 रुपये हो गयी। उसने अपनी बचत का उपयोग संपत्ति बनाने, कपड़े खरीदने आदि के लिए किया। अब उनके छोटे बेटे की सोच बदल गई है और उसने उच्च शिक्षा के माध्यम से घर की स्थिति को सुधारने की ठानी है। मनरेगा आय का एक स्रोत है और अन्य लाभों के साथ-साथ एक सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित करता है। बीपीएल कार्ड के कारण अब उन्हें सरकारी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और विशेष देखभाल मिल रही है। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को आय उत्पन्न करने में मदद करने के लिए वित्तीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। वह चाहती थीं कि मनरेगा को नियमित मजदूरी आधारित कार्य बनाया जाए। यह मामला मनरेगा योजना से जुड़ने के कारण परिवार के सदस्यों विशेषकर महिलाओं में स्थापित हुई सकारात्मकता को उजागर करता है।

चर्चा, निष्कर्ष और नीति निहितार्थ

मनरेगा का महिलाओं के रोजगार पैटर्न पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और यह निष्कर्षों से स्पष्ट भी हुआ; हालाँकि, पहले के अध्ययनों से भिन्नता की उपस्थिति का पता चलता है (बिश्नोई एवं अन्य, 2012) । महिलाओं को विशेष रूप से लाभ हो रहा है और वे अपने मौद्रिक योगदान के कारण परिवारों में बेहतर स्थिति का आनंद लेने लगी हैं (गुप्ता एवं अन्य, 2013; रॉय एवं अन्य, 2014) । सामुदायिक स्तर पर भी उनकी स्थिति की प्रशंसा की गई है। अब महिलाएं सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए चर्चा करने लगी हैं। शिक्षा के महत्व के बारे में महिलाओं की समझ के परिणामस्वरूप उनके बच्चों को इस संबंध में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने या खरीदारी के लिए बाहर जाने से नहीं हिचकिचाते। मनरेगा महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर, परिवार, समूह और सामुदायिक स्तर पर सशक्त बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। हालाँकि वे इस योजना के कामकाज के तरीके से संतुष्ट हैं, लेकिन कार्यस्थल पर उचित सुविधाओं की कमी ने उन्हें 100 दिन का काम पूरा करने से रोक दिया है और इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है (भट्टाचार्जी, 2017; हिमांशु एवं अन्य, 2015; पंकज और तन्खा आर, 2010) । महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मजदूरी बढ़ानी होगी और इसे पूरे देश में एक समान बनाना होगा (बैनिक एन. एवं अन्य, 2021; मोदी और बरुआ, 2021) । स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए शौचालय या बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। विशेषकर लाडनूं ब्लॉक में उत्पादन के विकास के लिए कृषि भूमि पर कार्यों को मनरेगा के तहत शामिल किया जा सकता है।

दूसरे, ग्रामवासियों के बीच मनरेगा प्रावधानों के संबंध में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत को सक्रिय रूप से नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करनी चाहिए और पारदर्शिता बनाए रखते हुए योजनाओं का विवरण लाभार्थियों के साथ साझा करना चाहिए (चौधरी, 2020) । लेकिन, सरकार कुशल

जनशक्ति की कमी, प्रणाली में पारदर्शिता और अभिसरण जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है (नारायण एस, 2016)। महिलाओं को बैठकों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है; हालाँकि, पुरुष प्रधान भारतीय समाज में यह एक बड़ी चिंता का विषय है। सामाजिक लेखापरीक्षा, जो अधिनियम में अनिवार्य है, को मनरेगा के समुचित कार्य के लिए प्रभावी ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी अद्यतन करने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने के अलावा, स्थानीय भाषा में सटीक जानकारी प्रदर्शित करने वाले नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय की दीवार पर लगाए जाने चाहिए। कार्यक्रम के सुचारू कामकाज के लिए सख्त निगरानी आवश्यक है, और यह लाभार्थियों की भागीदारी और विकास कार्यों के संबंध में सकारात्मक परिणाम ला सकता है (बडोदिया एवं अन्य, 2011)। इससे गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा जैसा कि इस अध्ययन से पता चलता है।

स्वीकृति

लेखक साक्षात्कार के लिए सहमत होने और अपनी राय दर्ज करने के लिए भारत के राजस्थान के लाडनू ब्लॉक के दो गांवों के सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हैं।

लेखक का योगदान:

हेमन्त कुमार मिश्रा: अवधारणा बनाना, लेख और कार्यप्रणाली विकसित करना, विश्लेषण करना और पांडुलिपि को संशोधित करना।

बिजयालक्ष्मी पांडा: डेटा संग्रह, प्रारंभिक चरण में विकास करते समय लेख में इनपुट प्रदान करना।

संदर्भ:

Badodiya, S. K., Kushwah, R. S., Garg, S. K., &Shakya, S. K. (2011). Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) on Poverty Alleviation.*Rajasthan Journal of Extention Education*, *19*, 206–209.

Banik N, Ghosh B, & Choudhury R R. (2021).Impact of MGNREGA on Labour Wage Rate Dynamics in India.*Regional Statistics*, *11*(01), 110–134.

Bhattacharjee, G. (2017). MGNREGA as Distribution of Dole.*Economic & Political Weekly*, *24*, 25–26.

Bishnoi, I., Verma, S., & Rai, S. (2012). MNREGA: An Initiative towards Poverty Alleviation through Employment Generation. *Indian Research Journal of Extension Education Special Issue, I*.

Borah, K., &Bordoloi R. (2014). MGNREGA and Its Impact on Daily Waged Women Workers: A Case Study of Sonitpur District of Assam. *IOSR Journal of Economics and Finance*, *4*(4), 40–44.

Choudhary, R. (2020). The Impact of MGNREGA on Employment and Migration: A Case Study of Rajasthan. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, *10*(10), 1–13. https://doi.org/10.5958/2249-7315.2020.00017.9

Coffey, D. (2013).Children's Welfare and Short-term Migration from Rural India.*Journal of Development Studies*, *49*(8), 1101–1117. https://doi.org/10.1080/00220388.2013.794934

De, U. K., & Bhattacharyya, P. (2013). Participation of Women in MGNREGA: How far is it Successful in Morigaon, Assam? *Indian Journal of Economics and Development*, *1*(2), 38–48.

Dev, Mahindra. S. (2012).*NREGS and Child Well-Being: Mumbai*.

Ghosh, J. (2009). Equity and Inclusion through Public Expenditure: The Potential of the NREGS. *New Delhi: Paper for International Conference on NREGA*, 21–22.

Gupta, S., Henry, C., & Sharma, S. K. (2013).Association of Socio-economic Status on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of Rural Women in Alwar District of Rajasthan.*Indian Journal of Extension Education*, *49*(1and2), 54–56.

Himanshu, Mukhopadhyay, A., & Sharan M R. (2015).*NREGS in Rajasthan: Rationed Funds and Their Allocation across Villages*. Economic and Political Weekly.

Imbert, C., & Papp, J. (2014).*Short-term migration and India's Employment Guarantee Scheme*.

Jha, R., Gaiha, R., & Pandey, M. K. (2012). Net transfer benefits under India's rural employment guarantee scheme. *Journal of Policy Modelling*, *34*(2), 296–311.

Kar.S. (2013). Empowerment of Women through MGNREGS: Issues and Challenges. *Magazines.Odisha.Gov.In*.Retrieved from http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2013/Feb-Mar/engpdf/76-80.pdf

Modi, G., & Baruah, P. B. (2021). Impact of MGNREGA on the Participating Households: A Study in Upper Siang District of Arunachal Pradesh. *Journal of Rural Development*, *40*(5), 620–633. https://doi.org/10.25175/JRD/2021/V40/I5/170694

Narayana S. (2016, March 15). *MNREGA and Its Assets*.Retrieved from https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/mnrega-and-its-assets.html

Panda, B. (2015). National Rural Employment Guarantee Scheme: Development Practice at the Crossroads. *Economic and Political Weekly*, *L*(23), 126–131.

Pankaj, A., &Tankha R. (2010). Empowerment Effects of the NREGS on Women Workers: A Study in Four States. In *Economic & Political Weekly*,*45*(30).

Pattnaik, J. (2020). MGNREGA and Its Impact on Livelihood Rural Development: A Sociological Study in Barwadag Village of Ranchi District of the State of Jharkhand. *Man In India*, *27*, 39–45.

Poonia, J. (2012). Critical study of MGNREGA, Impact and women's participation.*International Journal of Human Resources Development and Management*, *1*(1).

Roy, S., Singh, B., Padaria, R. N., & Singh, N. (2014).Activities and Institutional Mechanism of MNREGA and its Effectiveness in West Bengal.*The Indian Society of Extension Education*, *50*(1and2), 18–23.

Shah, M. (2012).*MGNREGA Sameeksha*(S. Mihir, Ed.; First, Vol. 1).Orient Blackswan.

Shah, M., Mann, N., &Pande, V. (2015).*MGNREGA Sameeksha: An Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (2005) Act 2006-2012*. https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id6749.html

Singh, M., & Singh K T. (2013). Rural Poverty Alleviation Programmes: A Study ofMGNREGA in Manipur. *International Journal of Humanities and Social Science*, *2*(9), 39–43.

उद्यमशीलता प्रवृत्ति: असम में आदिवासी उद्यमियों पर एक अध्ययन

बिनीता टोपनो* और आर. ए. जे. सिंगकोन**

सार

कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने उद्यमिता को प्रमुख चर के रूप में विस्तारित किया है जो सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को आर्थिक विकास से जोड़ता है। उद्यमिता विकास को विशेष रूप से ग्रामीण समाज में असंतुलन को हल करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। आर्थिक विकास में उद्यमिता के महत्व को समझते हुए, यदि पिछड़े समुदायों (जनजातियों) के व्यक्तियों द्वारा इसे नहीं अपनाया गया तो यह प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी। आदिवासी कई बदलावों से गुजर रहे हैं जिनके परिणामों और निहितार्थों को गंभीर रूप से गलत समझा गया है। सभी बाधाओं के बावजूद, एक बदलाव देखा जा रहा है जहां आदिवासी समाज एक उद्यम के निर्माण के प्रति अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहा है। इस अवलोकन के साथ, अध्ययन का उद्देश्य असम के आदिवासियों के बीच उद्यमिता (उद्यमी प्रवृत्ति) के प्रति रूचि की डिग्री निर्धारित करना है, और इस प्रक्रिया में सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा की जांच करना है जो उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्ययन असम के डिब्रूगढ़, सोनितपुर, तिनसुकिया और उदलगुरी जिलों के चाय बागानों, गांवों और कस्बों में फैले 120 आदिवासी उद्यमियों के अर्ध-संरचित साक्षात्कार पर आधारित है। नतीजे बताते हैं कि उद्यमियों के पास न्यूनतम योग्यताएं होती हैं जो उनके रोजगार के अवसरों को सीमित करती हैं। कुछ अवसरों के बावजूद, उन्होंने प्रबल प्रेरणा के साथ स्वेच्छा से उद्यमिता अपनाई। इसके अलावा, उद्यमी व्यक्तिगत संसाधनशीलता के लिए प्रबल रूचि के साथ उच्च उद्यमशीलता प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं।

मुख्य शब्द: उद्यमी, उद्यमिता, उद्यमशीलता प्रवृत्ति, आदिवासी

प्रस्तावना

विभिन्न प्रकार के साहित्य ने उद्यमशीलता विकास को न केवल आर्थिक विकास की समस्या को हल करने के साधन के रूप में, बल्कि बेरोजगारी और असंतुलित क्षेत्र विकास को संबोधित करने के एक तरीके के रूप में भी मान्यता दी है। उद्यमशीलता विकास एक व्यवहार्य व्यवसाय बनाने के लिए किसी व्यक्ति के इरादे और पहल पर निर्भर करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई कारक हस्तक्षेप करते हैं। अक्सर, उद्यमिता को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से आकार लेने वाले उद्यमी के व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है।

साहित्य में भारत में लोगों के एक निश्चित समूह को उद्यमशील समुदायों के रूप में दर्शाया गया है, जैसे कि मारवाड़ी, गुजराती और बंगाली, जो अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों के साथ आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़े (कलमिन्स और चुंग, 2006; अय्यर और शॉअर, 2008; गुप्ता, एन.डी.) । असंतुलित क्षेत्र के विकास के आलोक में, आदिवासियों (मुंडा, ओरांव, खरिया और संथाल जनजाति) नामक लोगों के एक समूह का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और चाय बागान श्रमिकों के रूप में असम की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल हैं। उन्हें मूल रूप से 19वीं सदी के मध्य में गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में भारत के अन्य हिस्सों से अंग्रेजों द्वारा असम लाया गया था। वे असम के चाय बागानों में बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। एक सदी से भी अधिक समय के बाद, यह देखा गया है कि वे जागरूक हैं, शिक्षित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करके कुछ उद्यमशीलता गतिविधियाँ दिखा रहे हैं। इसलिए, इस अध्ययन के माध्यम से भारत के पिछड़े समुदाय माने जाने वाले उद्यमिता के साहित्य में योगदान देने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य आदिवासी उद्यमियों की उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को मापना है और इस प्रक्रिया में, सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल की जांच करना है। यह उद्यमिता में उतरने के उनके उद्देश्यों को समझने का भी प्रयास करता है।

असम में आदिवासियों का संक्षिप्त अवलोकन

असम में आदिवासियों का इतिहास अक्सर चाय बागानों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबूत बताते हैं कि आदिवासी असम में चाय उद्योग की स्थापना से पहले ही उत्तर-पूर्व भारत से जुड़े हुए हैं। आदिवासियों का इतिहास भारत के कोलेरियन आदिवासियों से शुरू होता है। भारत के कोलेरियन आदिवासियों में एक दर्जन से अधिक जनजातियाँ शामिल हैं जिनमें मुंडा, संथाल, होस और खासी प्रमुख हैं। मुंडा, उराँव, संथाल, हो, खरिया और कई अन्य आदिवासी भारत की मूल जनजातियाँ हैं। प्राचीन संस्कृत रचनाओं से पता चलता है कि आर्यों के पूर्वजों के देश में प्रवेश करने से पहले मुंडा और अन्य सजातीय जनजातियों ने उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। जब आर्यों ने उत्तर-पश्चिमी दर्रों से भारत में प्रवेश करना शुरू किया, तो मुंडा और खासी जैसी जनजातियाँ आक्रमणकारियों का विरोध नहीं कर सकीं और पूर्व की ओर पलायन कर गईं और असम में बस गईं। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चूँकि खासी और मुंडा पूर्वोत्तर में एक साथ रह रहे थे, इसलिए उनकी संस्कृति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है; उदाहरण के लिए, वे अपने पूर्वजों के नाम

पर एक पत्थर का स्मारक बनवाएंगे। इसके अलावा, साहित्य में मुंडारी और खासी के बीच शब्दावली, व्याकरण और भाषा निर्माण के सिद्धांतों में समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, खासी कृषक नहीं थे, और इसलिए मुंडा उन्हें 'कासी' कहते थे, जिसका मुंडारी में अर्थ है 'जोतना नहीं' (का का अर्थ है नहीं और सी का अर्थ है जुताई करना)। सबूतों के ये टुकड़े इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि आदिवासी असम के सबसे पुराने निवासी हैं (रॉय, 1912)।

24 फरवरी 1826 को यंदाबो की संधि के माध्यम से असम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया, जो जनरल द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। ब्रिटिश पक्ष से आर्चीबाल्ड कैंपबेल और बर्मी पक्ष से लेगिंग के गवर्नर महा मिन हला क्याव हटिन थे। मध्य भारत (छोटानागपुर, संथाल परगना और मध्य प्रदेश) से आदिवासियों को ब्रिटिश शासक द्वारा असम के चाय बागानों में दास के रूप में लाया गया था (चटर्जी और गुप्ता, 1981; भौमिक, 1985; पालट्टी, 2006)। यह तब तक जारी रहा जब तक चाय उत्पादन असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं बन गया। हालाँकि, ब्रिटिश शासन के दौरान असम में आदिवासियों के प्रवास में योगदान देने वाले दो प्रमुख कारकों को निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: सबसे पहले, असम में चाय उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, और इसलिए श्रम की मांग थी। चाय बागान मालिकों ने श्रमिकों की भर्ती के लिए 'अर्कािटिस' (एजेंट) को नियुक्त किया (चटर्जी और गुप्ता, 1981) और परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में आदिवासियों को असम सहित विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। दूसरे, स्थायी बंदोबस्त (1793) की शुरूआत ने आदिवासियों को उनकी जमीन से वंचित कर दिया। भूमि के निरंतर नुकसान के कारण आदिवासी विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश शासन (शुक्ल, 2011) के खिलाफ विद्रोह की एक श्रृंखला शुरू की और इसने असम में आदिवासियों के हित में और योगदान दिया है। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह असम के चाय उद्योग के निर्माण के लिए एक मजबूर प्रवासन था।

आज असम की लगभग 3.12 करोड़ की आबादी में लगभग 20 प्रतिशत आदिवासी हैं, जिनमें से अधिकांश चाय बागानों में रहते हैं। आर्थिक रूप से ये लोग गरीब हैं, फिर भी असम के आर्थिक विकास, विशेषकर चाय उद्योग में उनका योगदान बहुत बड़ा है। असम में बसने की कई पीढ़ियों के बाद भी, आदिवासी अभी भी निर्वाह जीवन जी रहे हैं और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में रहने वाले अपने साथियों के विपरीत, उन्हें निम्न श्रेणी के नागरिकों के रूप में माना जाता है। सामंतवादी रेखा के भीतर चाय बागानों में फंसना, जो आधुनिक समय के साथ बिल्कुल असंगत है जहां मानव विकास की नई चेतना, और मानव और महिला अधिकारों की घोषणाओं में नई अभिव्यक्तियां स्वदेशी और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, हम आदिवासी श्रमिकों द्वारा अधिकतम मजदूरी, बोनस, बेहतर कामकाजी और रहने की स्थिति, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की मांग देखते हैं। इससे हड़तालें, तालाबंदी आदि हो रही हैं, जो असंगति के गंभीर संकेत हैं। इसके अलावा, आधुनिक पीढ़ी उसी बागान में काम करने के लिए स्वतंत्र, बंधनमुक्त और अनिच्छुक महसूस करती है जिसके लिए उनके पूर्वजों ने काम किया था। सामान्य अवलोकन के आधार पर हम निःसंदेह कह सकते हैं कि आदिवासी कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ताल, तालाबंदी, स्वयं को स्वतंत्र मानना आदि की घटनाएं चिंताजनक हैं और उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। शायद, एक व्यवस्थित अध्ययन और दस्तावेज़ीकरण से आम तौर पर असम में आदिवासियों और विशेष रूप से

उनकी उद्यमशीलता प्रवृत्ति की बेहतर तस्वीर सामने आएगी, जिसे उनकी खराब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से छुटकारा पाने और उन्हें मुक्त करने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है।

साहित्य की समीक्षा

उद्यमिता के विभिन्न पहलू दुनिया भर में उद्यमिता के बारे में हमारी समझ को सुधारने और बढ़ाने में विविध भूमिका निभाते हैं। साहित्य की समीक्षा कुछ चरों के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करती है जो एक उद्यमी के उद्भव में योगदान करते हैं।

लिंग एक महत्वपूर्ण निर्धारक है जो उद्यमिता की ओर रुझान को प्रभावित करता है। उद्यमशीलता की प्रवृत्ति लिंग के अनुसार भिन्न होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और अन्य व्यक्तिगत कारकों से आकार लेती है। वाल्डिंगर और गिल्बर्टसन (1994) ने अमेरिका में आप्रवासियों की प्रगति का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि महिलाओं की व्यावसायिक रैंकिंग पुरुषों की तुलना में कम है। फर्नांडीज और किम (1998) द्वारा उद्यमिता में अंतर-समूह अंतर का निर्धारण करते समय, यह पाया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष आप्रवासियों के स्व-रोज़गार वाले छोटे व्यवसायों में संलग्न होने की संभावना आनुपातिक रूप से अधिक है। ली (2001) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। दूसरी ओर, हैमरस्टेड (2004) सांख्यिकीय रूप से अपनी परिकल्पना को साबित करता है कि स्व-रोजगार महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक है क्योंकि महिलाओं पर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी होती है। उपरोक्त निष्कर्षों के विपरीत, उद्यमिता मध्य-अटलांटिक संयुक्त राज्य अमेरिका की अश्वेत महिलाओं के लिए वेतनभोगी श्रमिकों के रूप में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग भेदभाव को कम करने का एक तरीका बन गया है (हार्वे, 2005)। यह लिंग के आधार पर मानसिकता में अंतर्निहित अंतर को इंगित करता है जैसा कि मिन्निटी और नार्डोन (2007) ने सुझाव दिया था कि यदि महिलाओं के पास उद्यमिता में संलग्न होने के लिए कौशल और ज्ञान है और सफल होने के लिए उनके पास दृढ़ विश्वास है, तो वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की अधिक संभावना रखती हैं। इस प्रकार, उद्यमिता पर पुरुषों और महिलाओं के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

कुछ साहित्य उद्यमिता में शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। दुनिया भर में व्यक्ति अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को व्यावसायिक प्रतिष्ठा में बदल देते हैं जो अक्सर उद्यमिता की ओर ले जाती है। कू (1976) ने एक कोरियाई शहर में शोध करते समय पाया कि उद्यमिता समाज में उच्च स्थिति से जुड़ी है, और जिन व्यक्तियों ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है, वे अधिक कमाई को देखते हुए उद्यमिता में प्रवेश करते हैं। वास्तव में, एक शिक्षित उद्यमी किसी अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में परिवेश के अवसरों का आकलन करने और अपना स्वतंत्र निर्णय और मूल्यांकन करने में बेहतर स्थिति में होता है (ओम्मन, 1981)। यह रीस एवं शाह (1986) के अध्ययन से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का कर्मचारियों की कमाई पर अधिक प्रभाव पड़ता है और स्वरोजगार की संभावना भी बढ़ती है। इसी पंक्ति में, बोरजस (1986) इंगित करता है कि शिक्षा का उद्यमिता की दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उद्यमशीलता की प्रवृत्ति के संबंध में, ली (2001) ने माना कि पेशेवर योग्यता (श्रीवास्तव, 2008) के साथ उच्च स्तर की शिक्षा वाले उत्तरदाता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्व-रोज़गार के प्रति अधिक झुकाव प्रदर्शित करते हैं।

हालाँकि, उपरोक्त निष्कर्षों के विरोधाभासी, फर्नांडीज और किम (1998), एशियाई आप्रवासियों (कोरियाई, चीनी, एशियाई भारतीय और वियतनामी) के चार समूहों की उद्यमशीलता दरों में अंतर और अंतर समूह अंतर की खोज में दावा करते हैं कि सामान्य तौर पर, 90 प्रतिशत कॉलेज के बाद के स्नातक सफेदपोश व्यवसाय में हैं और गैर-कॉलेज स्नातक कम कुशल शारीरिक कार्य में कार्यरत हैं। दूसरी ओर, एशियाई भारतीय गैर-कॉलेज स्नातक अप्रवासी, कॉलेज-स्नातकोत्तर अप्रवासियों की तुलना में उद्यमिता अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। यह इंगित करता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा स्व-रोज़गार दर को कम करती है (हैमरस्टेड, 2004; लेवेनबर्ग और श्वार्ज़, 2008) और यह इस तथ्य के कारण उद्यमशीलता की सफलता (पांडा, 2000; पांडा, 2002) में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है चूँकि उच्च शिक्षित लोगों को स्व-रोज़गार के बाहर व्यावसायिक अवसरों में सबसे अधिक लाभ होता है।

उद्यमिता को अधिकतर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा और हावी किया जाता है। हालाँकि, उद्यमिता के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाकर मैक्लेलैंड का योगदान उल्लेखनीय है। मैक्लेलैंड ने तर्क दिया कि किसी समाज की आर्थिक वृद्धि 'उपलब्धि की आवश्यकता' ('एन' उपलब्धि) नामक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य पर निर्भर करती है। लेकिन मैक्लेलैंड के सिद्धांत पर एक अध्ययन यह साबित करता है कि अकेले 'एन' उपलब्धि से समाज का विकास नहीं होता है (मज़ूर और रोज़ा, 1977) । यह इस बात का प्रमाण देता है कि उद्यमी किसी एक उद्देश्य से नहीं बल्कि कई कारणों से प्रेरित होते हैं। पुरुष और महिला दोनों मुख्य रूप से स्वायत्तता, उपलब्धि, नौकरी से संतुष्टि की इच्छा, भौतिक प्रोत्साहन और अन्य गैर-आर्थिक पुरस्कारों की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं (क्रोमी, 1987; मिशेल, 2004)।

भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जहां जाति व्यवस्था प्रचलित है, उच्च जाति और निचली जाति दोनों के उद्यमी उपलब्धि और शक्ति की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। पश्चिम बंगाल में एक समुदाय के भीतर दो उपसंस्कृतियों (जाति समूहों) के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन इस बात का सबूत देता है कि निचली जाति (महिष्य) ने उच्च जाति की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता अपनाई थी और उच्च जाति के वे प्रदर्शन और उच्च संस्कृतियाँ महिष्यों के लिए उद्यमशीलता का शक्तिशाली संकेतक होती हैं (नंदी, 1973)। अनुसूचित जातियों द्वारा उच्च जातियों की विशेषताओं को प्राप्त करना भी पंजाब में नवाचारों के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में देखा गया था (बाल एवं जज, 2010) । इसके अलावा, खुद का मालिक बनना, नवीन विचारों को व्यवहार में लाना, गैर-व्यावसायिक शिक्षा और दृढ़ संकल्प उद्यमशीलता के इरादे को बढ़ावा देने वाले साबित होते हैं (भंडारी, 2006) । खनका (2009) असमिया उद्यमियों के बीच आर्थिक मकसद, स्वतंत्रता की इच्छा और पारिवारिक व्यवसाय को जीवित रखने को प्रेरक कारक मानते हैं। इनसे पता चलता है कि भारत में भी लोगों के पास उद्यमिता अपनाने के कई उद्देश्य हैं।

अनुसंधान क्रियाविधि

एक सर्वेक्षण डिज़ाइन किया गया था जिसके माध्यम से डेटाबेस बनाने के लिए प्राथमिक डेटा तैयार किया गया था। आदिवासी उद्यमियों (ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही एक उद्यम स्थापित करके अपनी उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को प्रकट कर चुके हैं) को उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए जानकारी के स्रोत के रूप में माना जाता था, जो संकल्पनात्मक रूप से उद्यमिता अपनाने के लिए एक रुझान या प्रवृत्ति या तत्परता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन उद्यमियों ने स्वयं अपना उद्यम शुरू किया है और जिनके पास अध्ययन क्षेत्र में एक जीवंत व्यावसायिक प्रतिष्ठान (विनिर्माण, व्यापार या सेवा) है, उन्हें ध्यान में रखा गया। इस प्रकार, विरासत में मिले व्यवसायों को अध्ययन से बाहर रखा गया। अध्ययन में मुंडा, उराँव, खरिया और संथाल जनजातियों के व्यक्तियों को ही आदिवासी माना गया। सर्वेक्षण असम के विभिन्न क्षेत्रों (चाय बागानों, गांवों और कस्बों) को कवर करते हुए डिब्रूगढ़, सोनितपुर, तिनसुकिया और उदलगुरी जिलों में आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

नमूना इकाई: एक उद्यमी जिसका उद्यम निम्नलिखित दो विशेषताओं को पूरा करता है उसे नमूना इकाई माना जाता था।

i. उद्यम का प्रचार और प्रबंधन एक आदिवासी उद्यमी (केवल मुंडा, संथाल, ओरांव और खरिया जनजातियाँ) द्वारा किया जाता है, जो उद्यम जीवन चक्र के सभी चरणों में शामिल होता है।
ii. उद्यम न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए विद्यमान है (किसी प्रकार की सफलता का प्रदर्शन करता हुआ)।

डेटा संग्रह डिज़ाइन: डेटा को एक शेड्यूल (अर्ध-संरचित) की मदद से एकत्र किया गया था जिसमें दो भाग शामिल थे। पहला भाग नमूना उद्यमियों के जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल करता है और दूसरा भाग उद्यमशीलता की प्रवृत्ति के माप से संबंधित है, जो गार्टनर, (1988) और बालाकृष्णन, गोपाकुमार और कानूनगो (1998) द्वारा चर्चा किए गए एकीकृत व्यवहार ढांचे के बाद शोधकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए पांच-बिंदु लिकर्ट पैमाने पर आधारित है। यह ढांचा पांच प्रमुख तत्वों पर आधारित है: व्यक्तिगत संसाधनशीलता (मिश्रा एवं कुमार, 2000), उपलब्धि अभिविन्यास (मैकलेलैंड, 1961; शेवर एंड स्कॉट, 1991; थॉमस एंड मुलर, 2000), रणनीतिक दृष्टि (मिटन, 1989; कुराटको और हॉजेट्स, 1989; फिनले, 1994), अवसर की तलाश (लीबेंस्टीन, 1968) और नवीनता (शुम्पीटर, 1949)। उल्लिखित प्रत्येक आयाम में छह कथन (सकारात्मक और नकारात्मक) शामिल थे, जिन पर उत्तरदाताओं को एक सममित दृढ़ता से सहमत - दृढ़ता से असहमत पैमाने पर अपनी सहमति या असहमति की डिग्री निर्दिष्ट करनी थी।

अध्ययन के लिए, प्रत्येक क्षेत्र (चाय बागानों, गांवों और कस्बों) से 40 नमूने एकत्र किए गए, जिसमें कुल 120 नमूने (प्रत्येक जिले से 30) थे। शोधकर्ता ने सभी नमूना उद्यमियों का साक्षात्कार लिया और अनुसूची के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं। साक्षात्कार एक घंटे से अधिक समय तक चला। नमूना उद्यमियों का चयन स्नोबॉल नमूनाकरण के माध्यम से किया गया था जो उद्देश्यपूर्ण प्रकृति का था।

डेटा का विश्लेषण: सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए, नकारात्मक कथनों के अंकों को उलट दिया गया। इसके अलावा, पांच-बिंदु लिकर्ट-प्रकार के पैमाने की न्यूनतम और अधिकतम लंबाई निर्धारित करने के लिए, पारंपरिक पद्धति का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, 1 से 1.80 (दृढ़ता से असहमत) 'बहुत कम प्रवृत्ति'; 1.81 से 2.60 (असहमत) 'कम प्रवृत्ति'; 2.61 से 3.40 (अनिर्णय) 'मध्यम प्रवृत्ति'; 3.41 से 4.20 (सहमत) 'उच्च प्रवृत्ति' और 4.21 से 5 (दृढ़ता से सहमत) 'बहुत उच्च प्रवृत्ति' का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरदाताओं के औसत अंकों की गणना की गई और परिणाम स्कोर की आवृत्तियों पर आधारित थे।

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग आदिवासी उद्यमियों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है और उन सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करता है जो उन्हें प्रेरित करते हैं जबकि दूसरा भाग उनकी उद्यमशीलता प्रवृत्ति को मापता है।

उद्यमिता को आकार देने में लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुरुष उद्यमियों का दृष्टिकोण महिला उद्यमियों से भिन्न होता है, और वास्तव में लिंग के आधार पर व्यवसाय शुरू करने की प्रवृत्ति में भी अंतर होता है। साहित्य के निष्कर्षों के अनुरूप, इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि पुरुष उद्यमियों का अनुपात (74 प्रतिशत) उनकी महिला समकक्षों (26 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है जैसा कि तालिका 1 में देखा जा सकता है। हालाँकि महिला उद्यमी केवल एक-चौथाई आबादी को कवर करती हैं, लेकिन यह दावा किया जा सकता है कि यह नगण्य नहीं है और वे रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं और नए व्यावसायिक विचारों के साथ आ रही हैं और अपनी स्थिरता के लिए स्व-रोज़गार को अपना रही हैं। महिला उद्यमियों ने उद्यमिता को एक ऐसी गतिविधि के रूप में देखा जहां वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने काम को अच्छी तरह से संतुलित कर सकती हैं और गरीबी से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जबकि पुरुष समकक्षों के लिए, यह उनकी जोखिम लेने की क्षमता और परिवार को वितीय सुरक्षा प्रदान करने के बारे में था।

तालिका 1:

उद्यमियों की रूपरेखा

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	89	74
महिला	31	26
कुल	**120**	**100**

तालिका 2:

उद्यमियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि

योग्यता	**संख्या**	**प्रतिशत**
निरक्षर	7	6
एचएसएलसी से कम	44	37
एचएसएलसी	12	10
एच एस	31	26
स्नातक	22	18
स्नातकोत्तर	4	3
कुल	**120**	**100**
व्यावसायिक प्रशिक्षण/योग्यता		
हाँ	32	27
नहीं	88	73
कुल	**120**	**100**

शिक्षा के संबंध में, इस अध्ययन के निष्कर्ष उन अध्ययनों के अनुरूप हैं जो उद्यमिता पर योग्यता के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। तालिका 2 में प्रस्तुत सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल के विवरण से पता चलता है कि अधिकांश उद्यमी (37 प्रतिशत) अपनी स्कूल छोड़ने की परीक्षा पूरी नहीं कर सके। आबादी के एक बड़े हिस्से - 88 उद्यमियों - के पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं थी और केवल 27 प्रतिशत के पास अपने क्षेत्र में कुछ तकनीकी योग्यता थी। यह, वास्तव में, इस धारणा का समर्थन करता है कि शिक्षा जितनी अधिक होगी, उद्यमिता की दर उतनी ही कम और इसके विपरीत होगी । इन उद्यमियों की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है, खासकर चाय बागानों और गांवों के मामले में जहां शैक्षणिक सुविधाएं बहुत खराब हैं। चाय बागानों के मामले में, शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब है और केवल प्राथमिक स्तर पर सीमित संख्या में स्कूल संचालित होते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के दौरान, उत्तरदाताओं को खराब आर्थिक स्थिति या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों तक उचित पहुंच की कमी के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप, अध्ययन से पता चलता है कि 38 प्रतिशत चाय बागान और 50 प्रतिशत ग्रामीण उद्यमियों के पास केवल प्राथमिक शिक्षा है। इससे उत्तरदाताओं के पास अपने शहरी समकक्षों की तुलना में कमाई के सीमित विकल्प और कम जोखिम बचता है। परिवेशगत स्थितियों के अलावा, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उन आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुत कुछ बताती है जिनके कारण उद्यमी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहे। तालिका 3 इंगित करती है कि उत्तरदाताओं में से 47 प्रतिशत के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो शारीरिक परिश्रम करके जीवन यापन करते थे। कड़वी सच्चाई यह थी कि परिवार में अधिक बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के बजाय उन्हें अतिरिक्त कमाई के साधन के रूप में देखा जाता था।

गौरतलब है कि उद्यमियों की जड़ें असम के चाय बागानों और गांवों में पाई जा सकती हैं। अतः कस्बों में रहने वाले उद्यमियों के बचपन के अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न नहीं हैं।

उत्तरदाताओं को ऐतिहासिक रूप से जिन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे उनकी मानसिकता में काफी बदलाव आया और उनका ध्यान उद्यमिता की ओर स्थानांतरित हो गया। तालिका 3 दर्शाती है कि उद्यमियों के माता-पिता में से 56 (47 प्रतिशत) मजदूर थे, 38 (31 प्रतिशत) कृषक थे और 19 (16 प्रतिशत) सेवाओं में शामिल थे, जो परिवार के मौजूदा व्यवसाय से बदलाव को दर्शाता है। उत्तरदाताओं ने उद्यमशीलता को चुना जो एक नई घटना थी और परिवार के पारंपरिक व्यवसाय से अलग थी। लेकिन पारंपरिक व्यवसाय से बदलाव क्यों हो रहा है? तालिका 4 की सहायता से इसे बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है।

तालिका 3:

उद्यमियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि

माता-पिता का व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
कृषक (किसान)	38	31
व्यापार	7	6
सेवा	19	16
अन्य (दिहाड़ी मजदूर)	56	47
कुल	**120**	**100**

जैसा कि साहित्य में ग्रामीण उद्यमिता का वर्णन किया गया है, यह उम्मीद की जाती है कि उद्यमियों के लिए जीवित रहने या परिवार के लिए कमाई करने के लिए यह उद्यमिता में शिद्दत से आगे बढ़ने का अंतिम उपाय होगा। तालिका 4 पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अधिकांश (36 प्रतिशत) उद्यमी स्वेच्छा से उद्यमिता अपनाते हैं जैसा कि सामान्य रूप से उद्यमिता साहित्य में वर्णित है। हालाँकि उद्यमियों को स्वेच्छा से उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन मुख्य कारण समाज में व्याप्त वर्ग असमानताएँ और उत्पीड़न थे जो आदिवासियों को श्रम कतार में सबसे नीचे धकेल देते थे जिसका पता आदिवासियों के इतिहास में लगाया जा सकता है। इन उत्तरदाताओं को किसानों और विशेष रूप से 'बगनिया' (चाय बागानों के श्रमिक) के पारंपरिक टैग को तोड़ने की जरूरत है, जिनकी असमिया समाज में निम्न स्थिति है। ये उद्यमी इस टैग को हटाना चाहते थे और वे चाय बागान उद्योग का हिस्सा बनने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए उद्यमिता में कूद पड़े। यह भावना तीन क्षेत्रों में रहने वाले लगभग सभी उद्यमियों द्वारा व्यक्त की गई थी क्योंकि असम में आदिवासी अक्सर चाय बागानों से संबंधित होते हैं और उन्हें मुंडा, ओरांव, खरिया और संथाल जनजातियों के बजाय 'पूर्व-चाय जनजाति' के रूप में लेबल किया जाता है। वास्तव में, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वापसी, उद्यमिता में उतरने के लिए एक प्रेरक कारक बन जाती है। मौजूदा साहित्य के निष्कर्षों को खारिज किए बिना, यह अध्ययन यह भी पुष्टि करता

है कि 33 प्रतिशत उद्‌यमियों ने, जिनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय को स्वीकार किया। बारह प्रतिशत उद्‌यमियों ने इसे एक स्वतंत्र मामले के रूप में लिया जहां वे मालिक हैं और स्वतंत्रता और लचीलेपन का प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर, उसका मानना है कि 58 प्रतिशत उद्‌यमियों को उद्‌यमिता में खींचा गया, जो कि प्रोत्साहन प्रेरणा से थोड़ा अधिक है।

तालिका 4:

उद्‌यम शुरू करने के कारण

कारण	**संख्या**	**प्रतिशत**
आजादी	14	12
एक अवसर देखा	10	8
इच्छा	43	36
बेरोजगारी	8	7
आजीविका	41	33
पिछली नौकरी से असंतुष्ट	2	2
रिटायर हो गया और कुछ करना चाहता था	2	2
कुल	**120**	**100**
प्रेरक कारक		
पुश	51	42
पुल	69	58
कुल	**120**	**100**

एक उद्‌यमी होने की प्रवृत्ति एक उद्‌यमशील समुदाय का हिस्सा होने के बजाय व्यक्तिगत गुणों पर अधिक निर्भर करती है जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया है, जहां पुश कारकों की उपेक्षा किए बिना इच्छा इन उद्‌यमियों की मुख्य प्रेरणा थी। विरासत में मिले अधिकांश व्यवसायों में हम देखते हैं कि एक ही व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है। इस प्रकार, अगली पीढ़ी में व्यवसाय शुरू करने के प्रारंभिक चरण (धन, संसाधन, बाजार, आदि की व्यवस्था) में शामिल संघर्षों और जोखिमों का अभाव है, जो एक उद्‌यमी होने की एक अनिवार्य विशेषता है। हालाँकि, अधिकांश उद्‌यमियों का मानना था कि स्वयं पर विश्वास और यह आत्मविश्वास कि 'मैं यह कर सकता हूँ और करूँगा', ने उन्हें व्यवसाय के साथ-साथ जीवन में भी कई बाधाओं को दूर करने में मदद की। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक स्थिति में ख़राब होने के कारण, इनमें से अधिकांश उद्‌यमियों के पास अपना उद्‌यम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने या तो चाय बागान उद्योग में या अन्य दुकानों और कार्यशालाओं में श्रमिक के रूप में और अन्य संस्थानों में वेतनभोगी श्रमिकों के रूप में काम किया। उन्हें अपनी कड़ी मेहनत और जोखिम लेने की क्षमता पर विश्वास था और परिणामस्वरूप, अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश उद्‌यमियों ने अपनी बचत (43 प्रतिशत) के साथ उद्‌यम शुरू किया, जैसा कि तालिका 5 में दिखाया गया है। उनमें से, 22 प्रतिशत ने उद्‌यम शुरू करने के

लिए अपने परिवार का समर्थन प्राप्त किया जो उद्यमिता के प्रति परिवार के सकारात्मक दृष्टिकोण को इंगित करता है जबकि 17.5 प्रतिशत ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, स्थानीय साहूकारों, एसएचजी, गैर सरकारी संगठनों और बैंकों से ऋण लिया। शायद ही कोई उद्यमी था जिसे मुद्रा ऋण जैसी सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ हो, जिसमें बहुत अधिक कागजी कार्रवाई शामिल थी। दरअसल, उद्यमियों को उनके लिए बनी सरकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इससे यह भी पता चलता है कि उद्यमी अपने उद्यमों के लिए धनराशि जुटाने के लिए समय लेने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे आसान पहुंच पसंद करते हैं और इसलिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय संस्थानों के बजाय स्थानीय साहूकार उद्यमियों को वित्तपोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तालिका 5:

उद्यम शुरू करने के लिए उद्यमियों द्वारा वित्तीय व्यवस्था

समर्थन	**संख्या**	**प्रतिशत**
खुद की बचत	52	43
परिवार	26	22
ऋृण	21	17.5
ऋण एवं बचत	21	17.5
कुल	**120**	**100**

तालिका 6 उद्यम के प्रकार का वितरण बताती है। लगभग 57 प्रतिशत उद्यम सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे जिनमें ज्यादातर स्कूल, हॉस्टल, रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सिलाई की दुकानें शामिल थीं। लगभग 39 प्रतिशत उद्यमी तेजी से बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार में थे और विनिर्माण क्षेत्र लगभग नगण्य था और केवल 4 प्रतिशत में बुनाई और निर्माण शामिल था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये न्यूनतम निवेश वाले सूक्ष्म उद्यम हैं।

तालिका 6:

उद्यम के प्रकार

प्रकार	**संख्या**	**प्रतिशत**
सेवा	68	57
व्यापार	47	39
उत्पादन	5	4
कुल	**120**	**100**

हालाँकि, जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कानूनी कारक उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को आकार देते हैं। हम एक ही समय में हर पहलू पर चर्चा नहीं कर सकते हैं,

लेकिन प्रत्येक पहलू का उद्यमशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो समय-समय पर और जगह-जगह बदलता रहता है। ऊपर चर्चा किए गए सामाजिक-आर्थिक और प्रेरक पहलुओं ने आदिवासी उद्यमियों की उद्यमशीलता प्रवृत्ति को कुछ हद तक प्रभावित किया है।

उद्यमशील प्रवृत्ति

इस अध्ययन में, उद्यमशीलता प्रवृत्ति से तात्पर्य उस डिग्री से है, जिस तक कोई व्यक्ति उद्यमशीलता की ओर झुका है। कई अन्य कारक उद्यमशीलता की प्रवृत्ति में योगदान कर सकते हैं, लेकिन यह अध्ययन पांच आयामों पर जोर देता है, अर्थात् व्यक्तिगत संसाधनशीलता, उपलब्धि अभिविन्यास, रणनीतिक दृष्टि, अवसर की तलाश और नवीनता जो कुल मिलाकर उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। व्यक्तिगत संसाधनशीलता, वास्तव में, स्थिर प्रक्रिया को तोड़ते हुए, जीवन के मौजूदा तरीके से परे जाने की व्यक्तिगत पहल पर जोर देती है। उपलब्धि अभिविन्यास का तात्पर्य चुनौतीपूर्ण और यथार्थवादी लक्ष्यों के साथ उच्च स्तर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की धारणा और ठोस प्रतिक्रिया के साथ काम करना है। रणनीतिक दृष्टि भविष्य-उन्मुख लक्ष्य-निर्धारण व्यवहार को इंगित करती है जिसमें परिवेशगत अवसरों और बाधाओं की स्पष्ट धारणा होना और सामान्य से असामान्य खोजना शामिल है। यह एक मजबूत नेतृत्व व्यवहार भी दर्शाता है। हालाँकि, अवसर की तलाश वह चरण है जहां एक व्यक्ति अपनी पहल, चुनौतीपूर्ण और यथार्थवादी लक्ष्यों और दृष्टि को एक साथ लाता है और इसे बाजार के माहौल में मूल्य साकार करने की दिशा में निर्देशित करता है। इसके अलावा, जब एक नया उद्यम (उत्पाद, बाजार, बाजार संयोजन, उत्पादन की विधि) बनाया जाता है और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में सक्षम होता है, तो इसे नवाचार कहा जाता है।

जैसा कि हम इनमें से प्रत्येक आयाम (तालिका 7) के औसत स्कोर को देखते हैं, यह पाया जाता है कि पूरे आयाम में उद्यमियों की प्रवृत्ति अधिक है। शायद, आदिवासी उद्यमियों के संदर्भ में, व्यक्तिगत संसाधनशीलता में रुचि 3.93 के औसत स्कोर के साथ अधिक है, जो स्पष्ट है क्योंकि वे अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और जोखिम लेने और उद्यम शुरू करने की इच्छा को महत्व देते हैं। वे व्यवसाय शुरू करने के विभिन्न निर्णयों में लगातार व्यक्तिगत संसाधनशीलता प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोगों के मन में एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार होता है, लेकिन वह केवल उनके दिमाग में ही रहता है। कई आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण इस विचार को वास्तविकता में बदलना सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कई भूमिकाएँ निभानी होती हैं और उसे हर चीज़ में संतुलन बनाना होता है। उसकी स्थिति में बदलाव एक बड़ा निर्णय है जिसके लिए बहुत साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर, एक उद्यमी को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए सभी बाधाओं को पार करना पड़ता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्तिगत संसाधनशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उद्यमी परिवार के पारंपरिक व्यवसाय से हटकर एक उद्यम शुरू करने के अपने उद्देश्यों के साथ अपनी कुशलता साबित करते हैं। दूसरी ओर, उपलब्धि अभिविन्यास माध्य स्कोर 3.58 है, जो आयामों के बीच दूसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्शाता है। उद्यमी अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बेताब थे, जो कि आगे बढ़ने और हासिल करने का एक मजबूत संकेत था।

अध्ययन के अन्य आयामों की तुलना में रणनीतिक दृष्टि के प्रति उद्यमियों का झुकाव 3.46 के औसत स्कोर के साथ कम था और नवाचार सबसे कम (3.44 औसत स्कोर) था। इसमें योगदान देने वाले मुख्य कारण सीमित शैक्षिक सुविधाएं और जोखिम की कमी है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति को परिवेशगत बाधाओं और अवसरों का बेहतर आकलन करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि साहित्य पुष्टि करता है।

तालिका 7:

प्रत्येक आयाम में प्रवृत्ति

आयाम	**माध्य अंक**
व्यक्तिगत साधनशीलता	3.93
उपलब्धि अभिविन्यास	3.58
कार्यनीतिक दृष्टि	3.46
अवसर की तलाश	3.49
नवप्रवर्तनशीलता	3.44

तालिका 8:

आदिवासी उद्यमियों की उद्यमशीलता प्रवृत्ति

औसत स्कोर	**प्रवृत्ति**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1 – 1.80	बहुत कम	----	----
1.81 – 2.60	कम	----	----
2.61 – 3.40	मध्यम	37	31
3.41 – 4.20	उच्च	79	66
4.21 – 5.00	बहुत ऊँचा	4	3
कुल		**120**	**100**

तालिका 8 में दिए गए परिणाम आवृत्ति विधि पर आधारित हैं। कुछ आयामों में कम रुझान के बावजूद, यह दर्शाता है कि आदिवासी उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता की प्रवृत्ति कम नहीं है। यह मध्यम से लेकर बहुत अधिक तक होता है। कुल मिलाकर, लगभग 31 प्रतिशत उद्यमियों में मध्यम उद्यमशीलता प्रवृत्ति (2.61 - 3.40 औसत स्कोर) है। लेकिन अधिकांश आबादी, यानी लगभग 66 प्रतिशत आदिवासी उद्यमी, 3.41 से 4.20 तक औसत स्कोर के साथ उच्च उद्यमशीलता प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर, केवल 3 प्रतिशत उद्यमी ही उच्च उद्यमशीलता प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार, अध्ययन से पता चलता है कि आदिवासी उद्यमियों की उद्यमशीलता की प्रवृत्ति अधिक है।

समापन

यह अध्ययन आदिवासी उद्यमियों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है और उद्यमशीलता की प्रवृत्ति में योगदान देने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को प्रदर्शित करता है। शैक्षिक सुविधाओं तक कम पहुंच वाले उद्यमियों के पास न्यूनतम योग्यता होती है जो कमाई के लिए उनके विकल्पों को सीमित करती है। अध्ययन से पता चलता है कि उद्यमियों द्वारा ऐतिहासिक रूप से सामना की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण परिवार के पारंपरिक व्यवसाय में बदलाव आ रहा है। परिणामस्वरूप, उद्यमियों ने स्वेच्छा से उद्यमिता को अपनाया, जो प्रेरणा के मजबूत प्रभाव को दर्शाता है। उद्यम के संदर्भ में, अधिकांश उद्यमी सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो वास्तव में, औपचारिक वित्तीय संस्थानों के बजाय उद्यमियों की बचत द्वारा शुरू और समर्थित है। हालाँकि, इस संबंध में परिवार के समर्थन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह एक शुरुआत है और इस समाज में उद्यमिता की सामाजिक स्वीकृति इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक परिवार से उत्पन्न होती है।

आदिवासियों के बीच उद्यमशीलता की प्रवृत्ति के संबंध में, अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्तिगत संसाधनशीलता में उद्यमियों की प्रवृत्ति प्रवृत्ति के अन्य आयामों की तुलना में अधिक है। कुल मिलाकर, आदिवासी उद्यमियों की प्रवृत्ति मध्यम से लेकर बहुत अधिक तक होती है और उनमें से अधिकांश उच्च उद्यमशीलता प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य समुदायों या उद्यमशील समुदायों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। यह अध्ययन केवल आदिवासी उद्यमियों (मुंडा, ओरांव, खरिया और संथाल जनजाति) तक सीमित है।

यह अध्ययन आदिवासी और उद्यमिता पर साहित्य और जातीय उद्यमिता के अध्ययन में भी योगदान देता है। यह उद्यमशीलता के संबंध में आदिवासियों पर आगे के अध्ययन के लिए एक आधार प्रदान करता है। अध्ययन की बाधाएँ उन क्षेत्रों, विशेष रूप से असम में आदिवासियों की आबादी, पंजीकृत और अपंजीकृत आदिवासी उद्यमों की संख्या, और अंततः असम में स्वदेशी जनजातियों (आदिवासियों) की उचित पहचान पर प्रकाश डालती हैं जहाँ भविष्य में अनुसंधान की आवश्यकता है।

लेखक का योगदान:

बिनीता टोपनो: विचार का निरूपण, डेटा संग्रह, कार्यप्रणाली और डेटा का विश्लेषण।

आर. ए. जे. सिंगकोन: पांडुलिपि का मसौदा तैयार करना, समीक्षा करना और अंतिम रूप देना।

संदर्भ:

Balakrishnan, S., Gopakumar, K., &Kanungo, R. N. (1998). Entrepreneurship and Innovation. New Delhi:

Sage Publication.

Bal, G. & Judge, P. S. (2010). Innovations, Entrepreneurship and Development: A Study on the Scheduled

Castes in Punjab. *Journal of Entrepreneurship, 19*(1), 43-62.

Bhandari, N. C. (2006). Intention for Entrepreneurship among Students in India. *Journal of Entrepreneurship, 15*(2), 169-179.

Bhowmik, S. (1985). Plantation labour in North-East India. *Economic and Political Weekly, 20*(13), 538-
541.

Borjas, G. J. (1986). The Self-employment Experience of Immigrants. *Journal of Human Resources, 21*,
485-506.

Chatterjee, S. & Gupta, R. D. (1981). Tea-labour in Assam: Recruitment and Government Policy, 1840-80.
Economic and Political Weekly, 16(44), 1861-1868.

Cromie, S. (1987). Motivations of Aspiring Male and Female Entrepreneurs. *Journal of Occupational*
Behaviour, 8(3), 251-261.

Fernandez, M. & Kim, K. C. (1998). Self-Employment Rates of Asian Immigrants' Groups: An Analysis of
Intra Group and Inter Group Differences. *International Migration Review, 32*(3).654-681.

Finlay, J. S. (1994). The Strategic Visioning Process. *Public Administration Quarterly, 18*(1), 64-74.

Gartner, W. B. (1988). "Who is an Entrepreneur" is the Wrong Question. *American Journal of Small Business, 13*, 11-32.

Gupta, A. (n.d). The Culture of Entrepreneurship. In B. Berger (Ed.), Indian Entrepreneurial Culture:
Bengal and Eastern India (pp. 104-141). California: ICS Press.

Hammarstedt, M. (2004). Self-employment among Immigrants in Sweden: An Analysis of Intra Group
Differences. *Small Business Economics, 23*(2), 115-126.

Harvey, A. M. (2005). Becoming Entrepreneurs Intersections of Race, Class and Gender at the Black
Beauty Salon. *Gender & Society, 19*(6), 789-808.

Iyer, R. &Schoar, A. (2008). Are there Cultural Determinants of Entrepreneurship? Retrieved March 10,
2014, from http://www.mit.edu/~aschoar/IyerSchoarNBER_v1.pdf.

Kalmins, A. & Chung, W. (2006). Social Capital, Geography and Survival: Gujrati Immigrant Entrepreneurs
in the U. S. Lodging Industry. *Management Science, 52*(2), 233-247.

Khanka, S. S. (2009). Motivational Orientation of Assamese Entrepreneurs in the SME Sector. *Journal of*
Entrepreneurship, 18(2), 209-218.

Koo, H. (1976). Small Entrepreneurship in a Developing Society: Patterns of Labour Absorption and Social
Mobility. *Social Forces, 54*(4), 775-787.

Kuratko, D. F., &Hodgetts, R. M. (1989). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. New York: Dryden.

Levenburg, N. M. & Schwarz, T. V. (2008). Entrepreneurial Orientation among the Youth of India: The

Impact of Culture, Education and Environment. *Journal of Entrepreneurship, 17*(1), 15-35.

The Entrepreneurial Propensity:… 75

Li, P. S (2001). Immigrants' Propensity to Self-employment: Evidence from Canada. *International*

Migration Review, 35(4), 1106 -1128.

Liebenstien, H. (1968). Entrepreneurship and Development. *American Economic Review, 58*(2), 75.

Mazur, A. & Rosa, E. (1977). An Empirical Test of McClelland's "Achieving society" Theory. *Social Forces,*

55(3), 769-774.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society, New York: Collier Macmillan Limited.

Minniti, M. & Nardone, C. (2007). Being in Someone Else's Shoes: The Role of Gender in Nascent

Entrepreneurship. *Small Business Economics, 28*, 223-238.

Mishra, S. & Kumar, S. (2000). Resourcefulness: A Proximal Conceptualization of Entrepreneurial

Behavior. *Journal of Entrepreneurship, 9*(2), 135-154

Mitchell, B. C. (2004). Motives of Entrepreneurs: A Case Study of South Africa. *Journal of*

Entrepreneurship, 13(20), 167-183.

Mitton, D. G. (1989).The Complete Entrepreneur. *Entrepreneurship Theory and Practice, 13*(3), 9-20.

Nandy, A. (1973). Entrepreneurial Cultures and Entrepreneurial Men. *Economic and Political Weekly, 8*

(47), 98-106.

Oommen, M. A. (1981). Mobility of Small-scale Entrepreneurs: A Kerala Experience. *Indian Journal of*

Industrial Relations, 17(1), 65-87.

Palatty, V. (2006). The Adivasis in Assam: Problems Policies and Prospects. *Mission Today, 8*, 5-12.

Panda, N. M. (2000). What Brings Entrepreneurial Success in a Developing Region? *Journal of*

Entrepreneurship, 9(2), 199-212.

Panda, T. K. (2002). Entrepreneurial Success and Risk Perception among Small–scale Entrepreneurs of

Eastern India. *Journal of Entrepreneurship, 11*(2), 173-190.

Rees, H. & Shah, A. (1986). An Empirical Analysis of Self-employment in the U.K. *Journal of Applied*

Econometrics, 1(1), 95-108.

Roy, S. C. (1912). The Mundas and Their Country. Jharkhand: Crown Publications.

Schumpeter, J. A. (1949). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Howard University

Press.

Shukla, P. K. (2011). The Adivasi Peasantry of Chotanagpur and the Nationalist Response (1920-1940s).

Social Scientist, 39(7), 55-64.

Srivastava, K. B. L. (2008). Examining the Relationship of Sociocultural Factors and Entrepreneurial

Propensity among Professional Students. *Entrepreneurial Management*, 184-203.

Thomas, A. S. & Mueller, S. L. (2000). A Case for Comparative Entrepreneurship: Assessing the

Relevance of Culture. *Journal of International Business Studies, 31*(2), 287-301.

Waldinger, R. & Gilbertson, G. (1994). Immigrants' Progress: Ethnic and Gender differences among U. S.

Immigrants in the 1980s. *Sociological Perspectives, 37*(3), 431-444.

ओडिशा में महिला स्व-सहायता समूहों और उनके उद्यमों की स्थिरता को मापना

नवीन कुमार राजपाल* और शर्मिला तमांग**

संक्षेप

एसएचजी कार्यक्रम ने वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण और शहरी गरीबों के जीवन में सफलतापूर्वक बदलाव लाया है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता धीरे-धीरे बढ़ते नामांकन से स्पष्ट होती है। महिलाओं को अपनी प्रमुख प्राथमिकता के रूप में लक्षित करके, प्रचार एजेंसियां/सरकार कार्यक्रम की पुनरावृत्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं। भारत में एसएचजी कार्यक्रम को नाबार्ड और विशेष राज्य एजेंसियों के उचित प्रयास से व्यापक कवरेज मिला है और दक्षिणी क्षेत्र में इसकी कवरेज सबसे अधिक है। यहां तक कि पूर्वी क्षेत्र भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रमुख उपस्थिति के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। वर्तमान अध्ययन बहुआयामी स्थिरता सूचकांक की मदद से ओडिशा के डब्ल्यूएसएचजी की स्थिरता स्थिति की जांच करने का प्रयास करता है। एसएचजी और उनके उद्यमों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दो तरह से विश्लेषण किया जाता है। प्रारंभ में, मूल्यांकन एसएचजी स्तर पर किया जाता है जबकि बाद में समग्र स्थिरता स्थिति का निष्कर्ष निकालने के लिए उद्यम-स्तर का विश्लेषण किया जाता है। हालाँकि कई अध्ययनों ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की रिपोर्ट दी है, लेकिन वास्तविक परिदृश्य काफी अलग है। समूह-स्तरीय विश्लेषण से पता चलता है कि अकेले वित्तीय सहायता से बहुआयामी गरीबी नहीं टूटेगी, इसलिए अध्ययन आवश्यक कौशल विकसित करने में सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी का सुझाव देता है।

मुख्य शब्द: डब्ल्यूएसएचजी, मिशन शक्ति, पोषण, प्रबंधकीय स्थिरता सूचकांक।

प्रस्तावना

कई अध्ययनों ने निर्दिष्ट आयामों में सुधार करने में भारत में एसएचजी-आधारित माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों के जबरदस्त प्रदर्शन पर प्रकाश डाला है। नोबेल समिति (2006) ने भी गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में माइक्रोफाइनेंस की क्षमता व्यक्त की है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, बोलीविया में बैंको सोल और इंडोनेशिया में बैंक राक्यत ने कई अविकसित देशों को समूह ऋण देने के उद्देश्यों को पूरा किया था। भारत में, माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम नाबार्ड के दिशानिर्देशों और राज्य प्राधिकरण के नियंत्रण के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके अलावा, नाबार्ड ने नीतियां बनाने और विभिन्न स्रोतों से सेवाओं की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (यानी औपचारिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं और गैर-सरकारी संगठनों, विशेष संस्थानों और अन्य के माध्यम से गैर-वित्तीय सेवाएं)। आज, एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम के रूप में खड़ा है, जो एक करोड़ से अधिक एसएचजी को कवर करता है, जिससे 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत के साथ 12 करोड़ परिवारों को सेवा मिलती है (एसएमएफआई, 2019)।

नाबार्ड रिपोर्ट (2018) के अनुसार, 100 से अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 300 डीसीसीबी, 27 राज्य मिशन और 5000 गैर सरकारी संगठन भारत में एसएचजी को वित्तीय/मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं (दास और गुहा, 2019)। इसके अलावा, 2008-09 की तुलना में, 2019 में एसएचजी की बचत लिंकेज दक्षिणी क्षेत्र की सबसे अधिक हिस्सेदारी के साथ 50 लाख रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो गई है, यानी 38 प्रतिशत (2008-09 में 48 प्रतिशत की तुलना में) हुआ है । दूसरी ओर, एसएचजी को ऋण लिंकेज में भी प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (बचत में 13 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में) और दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक संवितरण यानी 73 प्रतिशत (2008-09 में 74 प्रतिशत की तुलना में) हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, केवल कुछ मुट्ठी भर राज्य, ज्यादातर दक्षिण भारत से, लगभग तीन-चौथाई क्रेडिट लिंकेज के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश अग्रणी है (चक्रवर्ती, 2004) और वही पैटर्न और आउटरीच आज तक देखी जा रही है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता सामुदायिक भागीदारी की विकेन्द्रीकृत संरचना के माध्यम से पहुंच से बाहर लोगों तक पहुंचना है और वित्तीय समावेशन और इसकी सेवाओं को हाशिए पर रहने वालों के लिए सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। गरीबों की वित्तीय ज़रूरतें छोटी उद्यमशीलता गतिविधियों के वित्तपोषण से लेकर विभिन्न सामाजिक दायित्वों को पूरा करने तक भिन्न होती हैं। इतिहास वित्तपोषण के कई लचीले संस्थानों जैसे आरओएससीए, पॉनशॉप और साहूकार (सरकार और सिंह, 2006) के अस्तित्व को दर्शाता है। उपरोक्त योजनाओं का प्रमुख दोष उच्च-ब्याज दरों और/या भौतिक बंधक का अस्तित्व है। कार्यक्रम सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा और सामाजिक विनियमन (प्रियदर्शी, 2016) सहित सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों को कवर करने का प्रयास करता है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उत्थान और सुधार के विश्वास के आधार पर, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर नामांकन देखा गया है (राजपाल, 2016)। किसी भी कार्यक्रम की सफलता लक्षित/कमजोर वर्गों तक उसकी पहुंच पर निर्भर करती है जबकि इसके प्रभाव को उप-वर्गों के बीच कार्यक्रम की पहुंच के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गरीब लोगों को तीन उप-शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है, यानी गरीबों में सबसे अमीर,

अमीरों में सबसे गरीब और गरीबों में सबसे गरीब (नवाजस, श्राइनर, मेयर, गोंजालेज-वेगा और रोड्रिग्ज, 2000) और प्रशासनिक विफलता और सुविधा प्रदाताओं और प्रवर्तकों के भ्रष्टाचार के कारण, कार्यक्रम पहली दो श्रेणियों के लिए बेहतर काम करता है। राजपाल और तमांग (2017) ने ओडिशा के आदिवासियों पर अपने अध्ययन में पाया कि संपार्श्विक और पुनर्भुगतान क्षमता की अनुपलब्धता के कारण सबसे गरीब लोगों को समूह से बाहर रखा गया है।

माइक्रोफाइनेंस का परिचालन ढांचा समूह गठन, समूह लिंकेज, समान पहुंच और स्थिरता के आधार पर निर्भर करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक लाभदायक उद्यम के विकास या पुनर्भुगतान के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर करता है। यहां तक कि समूहों का पोषण भी ज्यादातर एजेंसियों की बातचीत, मध्यस्थता और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने, यानी समूह के साथ बातचीत, वित्तीय संस्थानों और सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच मध्यस्थता और योजनाओं/नीतियों/प्रचार उपायों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में, पंजीकृत भागीदारों के माध्यम से कुछ राज्यों के एसएचजी के लिए माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के तहत अन्य सेवाओं के दरवाजे खोले गए हैं। इसके अलावा, इसके कवरेज और प्रभाव के बारे में अब तक कोई औपचारिक रिपोर्ट संकलित नहीं की गई है। यहां तक कि नाबार्ड, जो भारत में माइक्रोफाइनेंस सेवाओं की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है, ने भी बचत, ऋण और एनपीए को छोड़कर माइक्रोफाइनेंस की अन्य सेवाओं पर कभी रिपोर्ट नहीं की है।

ओडिशा में, मिशन शक्ति गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के लिए लक्षित ग्रामीण पहल (टीआर आईपीटीआई) और ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम) के साथ-साथ एसएचजी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रचार के लिए एक नोडल संगठन के रूप में कार्य करता है। मोहराणा (2006) ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मिशन शक्ति के प्रदर्शन को "लक्ष्य से परे सफल" बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) से प्राप्त मिशन शक्ति के अंतिम प्रकाशन में बताया गया है कि (मार्च 2013 तक) ओडिशा में 1.26 लाख डब्ल्यूएसएचजी 19.98 लाख परिवारों को कवरेज प्रदान करने के लिए उपलब्ध थे। इसके अलावा, उक्त कार्यकाल के दौरान 2.33 लाख डब्ल्यूएसएचजी द्वारा (बार-बार ऋण सहित) ऋण सुविधा का उपयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन दो खंडों में विभाजित है। पहला एसएचजी स्तर पर कार्यक्रम ज्ञान, पहुंच, संगठन और प्रबंधन जैसे कई आयामों के माध्यम से जमीनी स्तर पर एसएचजी की स्थिरता का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। दूसरे, उद्यमों की स्थिरता के लिए, वित्तीय संरचना/निवेश, रोजगार के दिन, निवेश पर वापसी की मासिक दर और उद्यमों की आय के योगदान जैसे व्यापक संकेतकों का विश्लेषण किया गया।

कार्यप्रणाली एवं अध्ययन क्षेत्र

चूंकि अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है, इसलिए अध्ययन क्षेत्र का चयन शहरीकरण, बीपीएल स्थिति, बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, साक्षरता, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी सहित विकास प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। अध्ययन के लिए बालासोर जिले की पहचान जानबूझकर की गई थी। प्राथमिक डेटा के संग्रह के लिए नमूने का चयन बहु-चरणीय स्तरीकृत

यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के माध्यम से किया जाता है। जिले के ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से दो क्षेत्रों/खंडों में विभाजित किया गया है, यानी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के ब्लॉक। प्रत्येक क्षेत्र से तीन ब्लॉकों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। दूसरे, प्रत्येक चयनित विकास खंड से, समूह, ऋण और गतिविधियों के प्रबंधन में विविधीकरण की पहचान करने के लिए दो पंचायतों का चयन किया गया था। तीसरे चरण में, प्रत्येक चयनित पंचायत से, सामाजिक-आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक गांव का चयन किया गया और अंत में, प्रत्येक चयनित गांव से, 10 डब्ल्यूएसएचजी सदस्यों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। इसलिए, अध्ययन 15 डब्लूएसएचजी से संबद्ध 120 डब्लूएसएचजी सदस्यों/परिवारों पर निष्पादित किया गया है (शोधकर्ता ने सर्वेक्षण के समय प्रत्येक परिवार से एकल सदस्यता के प्रतिनिधित्व की पुष्टि की है)।

आकृति 1

चयनित पंचायत और नमूना परिवारों को निर्दिष्ट करने वाला मानचित्र

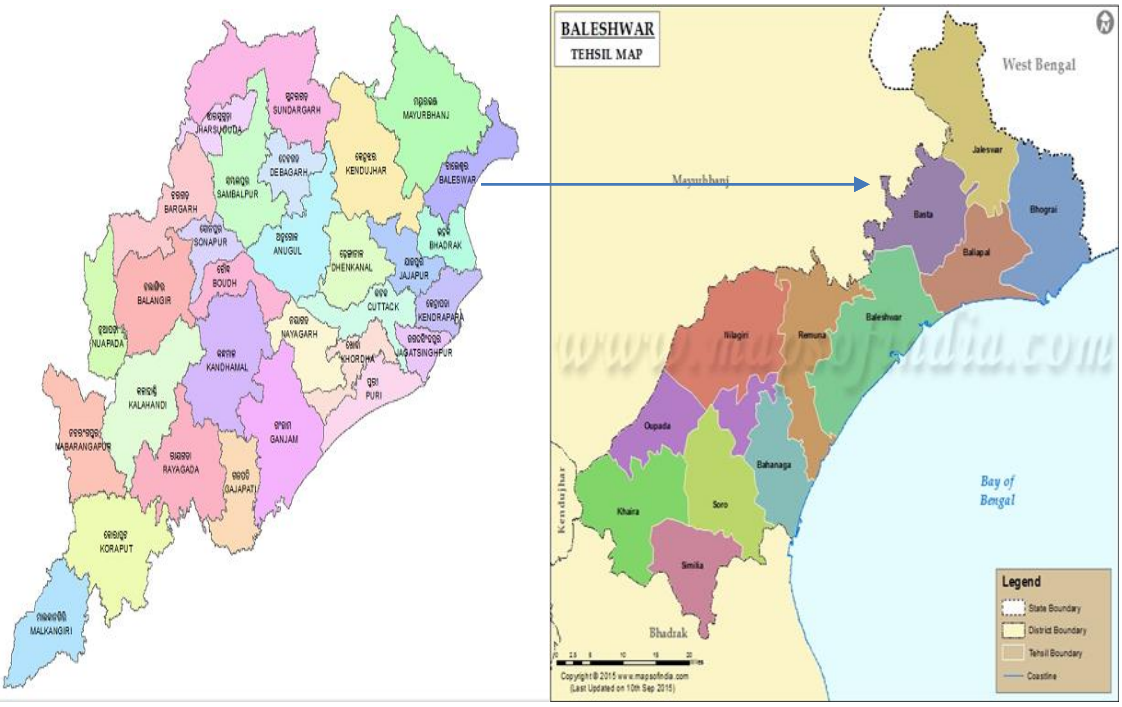

स्रोत: गूगल छवियां 27.09.2019 को 22:50 बजे एक्सेस की गईं (पैमाने के अनुसार नहीं)

चयनित ब्लॉकों एवं पंचायतों का विवरण इस प्रकार है:

ब्लॉक	**पंचायत 1**	**पंचायत 2**
बलियापाल	घंटुआ	श्रीरामपुर
बस्ता	ब्रह्माण्ड	मथुनी
जलेश्वर	अरुहा	लक्ष्मणनाथ
नीलगिरि	जदीदा	खलिया राज
रेमुना	कुरुदा	सियारगढ़
सोरो	नटपाड़ा	साबिरा

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का व्यापक उद्देश्य ओडिशा में डब्ल्यूएसएचजी और उनके उद्यमों की स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखकर उजागर करना है

- अध्ययन क्षेत्र में डब्ल्यूएसएचजी सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा
- एसएचजी और उनके उद्यमों का प्रबंधकीय प्रदर्शन
- डब्ल्यूएसएचजी और उनके निवेशित उद्यम की वित्तीय, संगठनात्मक और उद्यमशीलता स्थिति
- डब्ल्यूएसएचजी सदस्यों के क्षमता निर्माण, निर्णय लेने और उद्यमों के विकास में कार्यक्रम की प्रभावशीलता

विश्लेषण एवं व्याख्या

बालासोर जिले में एसएचजी कार्यक्रम राज्य के माइक्रोफाइनेंस संचालन के दोनों प्रमुख संगठनों, यानी मिशन शक्ति और टीआरआईपीटीआई (गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के लिए लक्षित ग्रामीण पहल) के दायरे में है। इसके अलावा, कार्यक्रम के निष्पादन और डेटाबेस रखरखाव की जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण कार्यालय की है। कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर आईसीडीएस कर्मचारियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा, कई सहायक एजेंसियां (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अध्ययन में 15 महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को शामिल किया गया है।

खंड I: डब्ल्यूएसएचजी का संगठन और प्रबंधन स्थिरता

जिले में एसएचजी कार्यक्रम ओडिशा के अन्य जिलों के समान है, यानी इसमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं और पूरे जिले में किसी भी एसएचजी में पुरुष सदस्य नहीं होने की सूचना है। डीआरडीए, आईसीडीएस और डीएसडब्ल्यूओ के साथ बातचीत से बालासोर और यहां तक कि ओडिशा के अन्य जिलों में पुरुष स्वयं सहायता समूहों की अनुपलब्धता की भी पुष्टि होती है (राजपाल, 2016)। दास और गुहा (2019) ने संगठनात्मक, प्रबंधकीय और वित्तीय सूचकांक का निर्माण करके स्थिरता के मुद्दे को संबोधित किया है। इस अध्ययन ने उप मापदंडों का विस्तार किया है और व्यापक आयामों, यानी सामाजिक, पारंपरिक और सूचना/ज्ञान कारकों को शामिल किया है। एसएचजी का प्रदर्शन इसकी सदस्यता संरचना, समूह बैठकों सहित कामकाज, समूह निर्णय सृजन, नेतृत्व चयन, रिकॉर्ड रखरखाव और वित्तीय लिंकेज और संसाधन प्रबंधन पर निर्भर करता है।

ओडिशा में स्व-सहायता समूहों का कार्य

एसएचजी का गठन गांव में आईसीडीएस कर्मचारियों (न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 सदस्यों) के साथ किया जाता है और सफल गठन और बैंक के साथ इसके जुड़ाव के बदले में 500 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रारंभ में, समूह को पास के वाणिज्यिक बैंक/आरआरबी से बचत लिंकेज सुविधा प्रदान की जाती है और निर्दिष्ट राशि (जैसा कि समूह की पहली बैठक के दौरान संकल्प का मसौदा तैयार करते समय तय किया गया था) एकत्र की जाती है और समूह के नाम पर जमा की जाती है, जिसे कॉर्पस फंड भी कहा जाता है। पहले सेमेस्टर के लिए लगातार जमा करने के बाद, समूह को जमा राशि का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में निकालने और नियमित बचत जमा के साथ आगामी सेमेस्टर के दौरान ब्याज के साथ समान किस्त में चुकाने का निर्देश दिया जाता है। लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, कॉर्पस फंड में बचत के गुणक में उस विशेष समूह को क्रेडिट लिंकेज सुविधा प्रदान की जाती है। समूह को ऋण चुकौती के प्रारंभिक सेमेस्टर के दौरान अपने कॉर्पस फंड/बचत से निकासी की अनुमति नहीं है।

एसएचजी की स्थिरता मोटे तौर पर कई सामाजिक, प्रबंधकीय, वित्तीय और पारंपरिक/निर्णय लेने वाले कारकों पर निर्भर करती है। शीर्ष एजेंसी यानी नाबार्ड की सिफारिश पर नोडल एजेंसी (यानी मिशन शक्ति) द्वारा निर्दिष्ट एसएचजी द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ दिशानिर्देश मौजूद हैं। ये विनियम (तालिका 1 में) एसएचजी की स्थिरता विकसित करने में प्रत्येक घटक की निर्भरता/महत्व को समझाते हैं।

तालिका 1:

स्वयं सहायता समूह स्थिरता के लिए मानक मानदंड और विनियम

घटक	संकेतक	विवरण	वर्गीकरण	अनुपात
गठन/संगठनात्मक और परिचालन/प्रबंधकीय घटक (ओएमआई)	समूह सदस्यता	समूह सजातीय होना चाहिए और इसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 सदस्य होने चाहिए। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एकाधिक सदस्यता की अनुमति नहीं है और प्रत्येक परिवार से केवल एक सदस्य को एसएचजी में अनुमति है।	≤10	3
			11 – 12	2
			12 से ऊपर	1
	समूह रचना	ओडिशा में एसएचजी में प्रमुख रूप से महिला नामांकन और भागीदारी शामिल है। प्रचार एजेंसियों को विवाहित और विधवा सदस्यों के नामांकन के लिए सलाह दी जाती है। अविवाहित सदस्यों को भी विवाहित/विधवा सदस्यों की अनुपलब्धता या समूह की प्राथमिकता/दायित्व के अधीन अनुमति दी	विवाहित	3
			विवाहित और विधवा	2
			विवाहित + विधवा + अविवाहित	1

		जाती है।		
	बैठक का कार्यक्रम	एसएचजी को निर्धारित एजेंडा के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता होती है। समूह संचालन एवं विकास हेतु चर्चा, समझ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु बैठक एक आवश्यक तत्व है। बैठक आमतौर पर सप्ताह में एक बार, पाक्षिक या मासिक रूप से की जाती है।	साप्ताहिक	3
			पाक्षिक	2
			मासिक	1
	अभिलेखों के रखरखाव	अभिलेखों के रखरखाव का ज्ञान एसएचजी की स्थिरता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवगठित समूहों को अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित प्रशिक्षण आंगनवाड़ी/आईसीडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राप्ति, व्यय, अग्रिम आदि से संबंधित प्रविष्टि दैनिक/वास्तविक समय के आधार पर दर्ज की जानी आवश्यक है।	स्वयं/समूह सदस्य	3
			प्रचार एजेंसी	2
			अन्य	1
	समूह बैठक का समय	बैठक का समय सदस्यों के योगदान के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि महिला सदस्य या तो घरेलू कामकाज करती हैं या फिर खेत में काम करती हैं। इसलिए, शाम का समय सबसे अनुकूल विकल्प माना जाता है।	शाम	3
			दोपहर	2
			सुबह	1
	बैठक में उपस्थिति	बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। हालाँकि समूह प्रस्ताव पारित करने के लिए फोरम में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य शामिल होने चाहिए। लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने वालों को जुर्माना देना होगा।	90 – 100 प्रतिशत	3
			75 – 90 प्रतिशत	2
			50 – 75 प्रतिशत	1
	निर्णय सृजन	समूह प्रबंधन में व्यक्तिगत निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। हालाँकि निर्णय का अधिनियमन अध्यक्ष और सचिव (नेताओं) द्वारा किया जाना है, फिर भी व्यक्तिगत सदस्य की सहमति की आवश्यकता है।	सर्वसम्मति	3
			नेता	2
			प्रचार एजेंसी	1
	आर्थिक गतिविधि	आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में समूह को समूह या व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए स्वायत्तता प्रदान की जाती है। बताया गया है कि व्यक्तिगत व्यवसाय में जोखिम समूह गतिविधियों	समूह	3
			संयुक्त रूप से	2
			व्यक्तिगत	1

		की तुलना में अधिक है।		
	नेता चयन प्रक्रिया	एसएचजी कार्यक्रम सदस्य द्वारा, सदस्य और सदस्य के लिए के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए, सशक्तिकरण के निर्धारण में व्यक्तिगत सदस्य की पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसएचजी नेता के चयन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक पसंदीदा पद्धति के रूप में देखा जाता है।	मतदान	3
			प्रचार एजेंसी	2
			अन्य	1
	नेतृत्व में रोटेशन	रोटेशन के साथ नेतृत्व आत्म-विकास और संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह समूह की पहचान को आकार देने के लिए प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्रदान करता है।	वार्षिक	3
			दो वर्ष	2
			कोई रोटेशन नहीं/	1
	संघर्ष समाधान प्रक्रिया	ऐसे लोकतांत्रिक तंत्र के साथ काम करने से विभेदक/व्यक्तिगत हितों से संबंधित विवाद पैदा होते हैं। इसलिए, आंतरिक संघर्ष को इसके ढांचे के भीतर हल किया जाना चाहिए। असाधारण स्थितियों के मामले में, महासंघ और प्रचार एजेंसियों से सहायता ली जाती है।	समूह के भीतर	3
			प्रचार एजेंसी	2
			अन्य	1
	अभिलेख लेखापरीक्षा	पारदर्शिता और प्रमाणीकरण के लिए, समूहों को हर साल/प्रत्येक ऋण के पूरा होने पर अपने समाधान और बहीखाता की आंतरिक/बाहरी लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।	लेखा परीक्षक	3
			प्रचार एजेंसी	2
			स्वयं/कोई लेखापरीक्षा नहीं	1
	सरकारी परियोजनाओं की सेवा	कई एसएचजी सरकारी परियोजनाओं जैसे एमडीएम, पीडीएस में भोजन तैयार करना, स्थानीय सतर्कता समितियों के सदस्य आदि की सेवा में लगे हुए पाए जाते हैं। कभी-कभी यह भूमिका एक व्यक्तिगत समूह या एक ही गांव/पंचायत के दो से तीन समूहों को सौंपी जाती है।	अकेले	3
			संयुक्त रूप से	2
			कोई कार्य नहीं	1
स्रोत: मिशन शक्ति, ओएलएम, नाबार्ड, डीडब्ल्यूसीडी और टीआरआईपीटीआई की रिपोर्टों से संकलित				

उपरोक्त 13 संकेतक समूह गठन और पदाधिकारियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एसएचजी की स्थिरता मोटे तौर पर गठन, संचालन, प्रबंधन, वित्तीय और पारंपरिक कारकों पर निर्भर करती है। दास और गुहा (2019) ने संगठनात्मक, प्रबंधकीय और वित्तीय सूचकांक का निर्माण करके स्थिरता के मुद्दों को संबोधित किया है।

तालिका 2.

उप-घटक वर्गीकरण और अंतिम घटक स्कोर

संगठनात्मक घटक	समूह सदस्यता	बैठक का कार्यक्रम	नेतृत्व में रोटेशन	समूह रचना	नेता चयन प्रक्रिया	समूह बैठक का समय
औसत अंक	**1.89**	**1.43**	**2.01**	**2.58**	**2.01**	**2.43**

संगठनात्मक घटक	अभिलेख रखरखाव	बैठक में उपस्थिति	अभिलेख लेखापरीक्षा	निर्णय लेना	आर्थिक गतिविधि	संघर्ष समाधान प्रक्रिया	सरकारी परियोजनाएँ
औसत अंक	**2.65**	**1.93**	**1.41**	**2.23**	**1.33**	**2.70**	**1.21**

घटक स्कोर	***1.00 – 1.40***	***1.41 – 1.80***	***1.81 - 2.20***	***2.21 – 2.60***	***2.60*** से ऊपर
श्रेणी/स्थिति	बहुत ख़राब	ख़राब	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा

स्रोत: विभिन्न साहित्य समीक्षाओं से संकलन

इस अध्ययन में संगठनात्मक प्रबंधकीय सूचकांक (ओएमआई) की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया है जो औसत संगठनात्मक घटक सूचकांक स्कोर और परिचालन घटक सूचकांक स्कोर (तालिका 2 में वर्गीकृत घटक) का योग है।

$$\textbf{OMI} = \frac{1}{2}\,(ORCI + OPCI)$$

जहां, ओआरसीआई - संगठनात्मक घटक सूचकांक, और

ओपीसीआई - परिचालन घटक सूचकांक

Or summing up the average score of all indicators reflected in Table 1. Let Z_{ij}denote the value of jth indicators of organisational and operational sustainability index of WSHGs ($\mathrm{OMI}^{\mathrm{WSHG}}$) can be expressed as

$$\textbf{OMI} = \frac{1}{13}\sum_{i=1}^{13} Z_{ij}\,,\ 1 \le \mathrm{OMI} \le 3$$

इस अध्ययन ने संगठनात्मक और परिचालन उप-मापदंडों का विस्तार किया है और तालिका 2 में दो उप-घटकों के तहत वर्गीकृत व्यापक आयामों को शामिल किया है। संगठनात्मक और प्रबंधकीय संकेतक (ओएमआई) स्कोर का समग्र परिणाम तालिका 2 के अनुसार एसएचजी की औसत स्थिति (1.98) दर्शाता है। संगठनात्मक घटक स्कोर 2.05 है जबकि परिचालन घटक स्कोर 1.92 है जो ओएमआई मापदंडों में एसएचजी के औसत प्रदर्शन को दर्शाता है। उप-घटक विश्लेषण से पता चलता है कि बैठक कार्यक्रम (1.43)

के खराब प्रदर्शन के कारण संगठन घटकों का औसत स्कोर काफी प्रभावित हुआ है, जबकि समूह सदस्यता, नेतृत्व में रोटेशन और नेता चयन प्रक्रिया औसत प्रदर्शन (क्रमशः 1.89, 2.01 और 2.01) दिखाती है।

समूह संरचना और समूह बैठक का समय पांच-बिंदु पैमाने (2.58 और 2.43) पर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। बैठक कार्यक्रम का खराब स्कोर अध्ययन क्षेत्र में 67 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों द्वारा अनियमित बैठकों/महीने में एक या दो बार बैठकें आयोजित करने के कारण है। इसके अलावा, परिचालन घटक विश्लेषण से सरकारी परियोजनाओं (1.21) और आर्थिक गतिविधियों (1.33) के साथ जुड़ाव में एसएचजी के बहुत खराब प्रदर्शन का पता चलता है, जबकि ऑडिटिंग रिकॉर्ड करने पर खराब स्थिति देखी गई है, हालांकि बहुत खराब स्थिति के करीब है (1.41)। अधिकांश एसएचजी व्यक्तिगत स्वामित्व वाले व्यवसाय की अनुमति दे रहे हैं और बहुत कम यानी केवल एक एसएचजी ने राशन की आपूर्ति ली है, जबकि तीन ने स्कूलों में संयुक्त रूप से मध्याह्न भोजन तैयार करने का काम किया है। केवल 13 प्रतिशत एसएचजी अधिकारियों/सीए से नियमित ऑडिट कराते हैं, जबकि 27 प्रतिशत एसएचजी का ऑडिट उनकी प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, अध्ययन क्षेत्र में 60 प्रतिशत एसएचजी ने कभी भी कोई बाहरी ऑडिटिंग नहीं की। बैठकों में उपस्थिति औसत (1.93) है और निर्णय लेने की क्षमता अच्छी (2.23) है, जबकि रिकॉर्ड का रखरखाव और संघर्ष-समाधान प्रक्रिया 'बहुत अच्छी' स्थिति दर्शाती है।

समग्र परिणाम से पता चलता है कि चयनित एसडीजी में से 13 प्रतिशत अच्छे प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में आते हैं। जबकि 67 प्रतिशत एसएचजी औसत प्रदर्शन करने वाले हैं, ओएमआई सूचकांक के अनुसार 20 प्रतिशत खराब प्रदर्शन करने वाले हैं। युग्मित नमूना टी-परीक्षण (अनुलग्नक I) विचाराधीन एसएचजी में संगठनात्मक घटक स्कोर और परिचालन घटक स्कोर के बीच एक महत्वपूर्ण औसत अंतर दिखाता है (टी119 = 2.923, पी <0.01)। विचाराधीन दोनों घटक (अनुलग्नक II) कमजोर और नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं (आर = - .254, पी <0.01)। संगठनात्मक स्कोर (2.05) की तुलना में परिचालन स्कोर कम (1.92) पाया गया है।

अंत में, ओडिशा में एसएचजी की स्थिरता स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए वित्तीय स्थिरता सूचकांक (एफएसआई) विकसित किया गया। उपलब्ध साहित्य समीक्षा और अग्रणी बैंक, प्रचार एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत के अनुसार एसएचजी के लिए वित्तीय स्थिरता सूचकांक तालिका 3 में निम्नलिखित व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यूको बैंक 23 शाखाओं के साथ जिले के अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करता है और कुल 113 वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में योगदान देता है। सबसे अधिक बैंक शाखाएँ बालासोरब्लॉक (47 शाखाएँ) में देखी गईं, जबकि सबसे कम औपाडा ब्लॉक में थीं (2011 की जनगणना के अनुसार 82,917 की आबादी को सेवा प्रदान करने वाली केवल 5 वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ)। इसके अलावा, ओडिशा ग्राम्य बैंक (53 शाखाओं वाला आरआरबी) और बालासोर नामक दो सहकारी बैंक मौजूद हैं - भद्रक केंद्रीय सहकारी बैंक और बालासोर सहकारी शहरी बैंक। हमारे अध्ययन में, 47 प्रतिशत डब्ल्यूएसएचजी वाणिज्यिक बैंकों से, 33 प्रतिशत आरआरबी से और 20 प्रतिशत सहकारी बैंकों से जुड़े हुए हैं।

ओडिशा में डब्ल्यूएसएचजी की वित्तीय व्यवहार्यता को समझने के लिए, तालिका 3 और अनुबंध IV ओडिशा में डब्ल्यूएसएचजी में एफएसआई संकेतकों के विवरण की जानकारी प्रदान करता है।

तालिका 3:

वित्तीय स्थिरता सूचकांक के संकेतक

क्र.सं.	संकेतक	विवरण	श्रेणी	स्कोर
1.	कॉर्पस फंड (बचत) आईएनआर	कॉर्पस फंड सदस्यों द्वारा साप्ताहिक/मासिक आधार पर योगदान की गई आंतरिक रूप से जमा की गई धनराशि है। उच्च कॉर्पस फंड के लिए, ऋण का आवंटन अधिक होगा।	10000 से अधिक	3
			7500 - 10000	2
			5000 - 7500	1
2.	ऋण की संख्या	आवंटित ऋणों की संख्या कॉर्पस फंड, पिछले ऋण चुकौती की स्थिति और एसएचजी के अस्तित्व के वर्षों पर निर्भर करती है। यह विकास/एसएचजी के इंजन को चलाने के लिए नियमित ईंधन के रूप में कार्य करता है।	3 से अधिक	3
			2 - 3	2
			केवल 1	1
3.	ऋण की राशि (आईएनआर)	एसएचजी के ऋण की राशि उद्यमों की स्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ऋण राशि में वृद्धि व्यवसाय के निश्चित और आवर्ती खर्चों को बढ़ाने के एक पैरामीटर के रूप में कार्य करती है।	200000 से अधिक	3
			100000 - 200000	2
			100000 से कम	1
4.	सब्सिडी/बीज राशि का लाभ उठाया गया	गठन के छह महीने पूरे होने के बाद, एसएचजी के खाते में एकमुश्त बीज/सब्सिडी राशि जमा की जाती है। यह राशि आमतौर पर एनआरएलएम के तहत पंजीकृत एसएचजी को वितरित की जाती है।	दोनों	3
			केवल बीज धन/सब्सिडी	2
			कोई नहीं	1
5.	पुनर्भुगतान में नियमितता	बैंकों द्वारा निर्धारित ईएमआई के अनुसार पुनर्भुगतान में नियमितता वित्तीय और संकट प्रबंधन का एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करती है। व्यक्तिगत सदस्यों से वसूली के बाद ईएमआई का नियमित पुनर्भुगतान सहकर्मी दबाव और समन्वय के लिए प्रॉक्सी का काम करता है।	90 प्रतिशत से अधिक	3
			70 – 90 प्रतिशत	2
			50 – 70 प्रतिशत	1
6.	अन्य स्रोतों से ऋण	अन्य स्रोतों से ऋण सदस्यों की उत्पादक और अनुत्पादक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त धन/समर्थन के लिए एक प्रॉक्सी के	कोई नहीं	3
			20 प्रतिशत से कम	2
			20 प्रतिशत से भी अधिक	1

		रूप में कार्य करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक ऋण के माध्यम से सदस्यों की वांछनीयताओं को पूरा करना है।		
7.	परिक्रामी निधि का उपयोग/निकासी	समाधान निधि ऋण स्वीकृत करने के लिए गारंटर/बंधक के रूप में कार्य करती है। परिक्रामी निधि जितनी अधिक होगी, स्वीकृत ऋण की राशि उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार सरगम को बढ़ाने के लिए, कॉर्पस फंड का एक हिस्सा उचित रुचि वाले सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है।	नियमित रूप से	3
			कभी-कभी	2
			कभी नहीं	1
8.	ऋण प्राप्त करने के लिए लिंक्ड एफआई पर की गई यात्राओं की संख्या	लिंक किए गए वित्तीय संस्थानों के समर्थन का विश्लेषण बाद के ऋण प्राप्त करने के लिए एसएचजी द्वारा की गई यात्राओं की संख्या के माध्यम से किया जाता है। जितनी अधिक यात्राएँ होंगी, एसएचजी की स्थिरता के लिए वित्तीय संस्थानों का समर्थन उतना ही कम और इसके विपरीत होगा।	1 – 2 बार	3
			3 – 5 बार	2
			5 से अधिक बार	1
9.	पुनर्भुगतान दर	संयुक्त ऋणों की पुनर्भुगतान दर वित्तीय स्थिरता के एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करती है। पुनर्भुगतान दर जितनी अधिक होगी, एसएचजी की वित्तीय स्थिरता उतनी ही अधिक होगी।	60 प्रतिशत से अधिक	3
			40 - 60 प्रतिशत	2
			40 प्रतिशत से कम	1
10.	उत्पादक उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग	स्वीकृत ऋण का उपयोग एसएचजी की क्षमता/दक्षता के विश्लेषण के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। उपयोग अनुपात जितना अधिक होगा, उत्पादक गतिविधियों में व्यय/निवेश उतना ही अधिक होगा।	75 प्रतिशत और उससे अधिक	3
			50 – 75 प्रतिशत	2
			50 प्रतिशत से कम	1

घटक स्कोर	***1.00 – 1.40***	***1.41 – 1.80***	***1.81 - 2.20***	***2.21 – 2.60***	***2.60*** से अधिक
श्रेणी/स्थिति	बहुत ख़राब	ख़राब	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा

स्रोत: प्राथमिक डेटा, साहित्य समीक्षा और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत पर आधारित गणना

गहन विश्लेषण से माइक्रोफाइनेंस व्यवसायों में एसबीआई, यूको, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक जैसे विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की भागीदारी का पता चलता है। प्रत्येक डब्लूएसएचजी सदस्य द्वारा किया गया औसत योगदान 30 रुपये से 100 रुपये प्रति माह तक है, जिसकी सदस्यता अवधि 6.2 वर्ष (औसत) और औसत 6 वर्ष है। यह कम औसत बचत उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति

(बीपीएल सदस्यों का 82 प्रतिशत) और परिवार पर निर्भरता के कारण है। चूंकि डब्ल्यूएसएचजी द्वारा की गई बचत आवंटित किए जाने वाले ऋण की राशि निर्धारित करती है, चयनित अध्ययन क्षेत्र में प्रचार एजेंसियां और बैंकर लाभार्थियों को अपना फंड (यहां तक कि आपातकालीन स्थिति के दौरान भी) नहीं निकालने के लिए मजबूर करते हैं । अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत डब्ल्यूएसएचजी के पास 10,000 रुपये से अधिक की बचत थी जबकि 40 प्रतिशत के पास 7,500-10,000 रुपये के बीच की बचत थी। दूसरी ओर नाबार्ड की रिपोर्ट "भारत में माइक्रोफाइनेंस की स्थिति 2013 - 14" के अनुसार, ओडिशा में डब्ल्यूएसएचजी की औसत बचत 8,839 रुपये है जो स्पष्ट रूप से बालासोर जिले के डब्ल्यूएसएचजी (20,619 रुपये) की बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

अध्ययन क्षेत्र में डब्ल्यूएसएचजी द्वारा लिए गए ऋणों की औसत संख्या तीन है, जिनमें सबसे अधिक ऋणों की संख्या पांच और सबसे कम है। इसके अलावा, 33 प्रतिशत डब्ल्यूएसएचजी ने तीन बार से अधिक ऋण लिया है, जबकि 40 प्रतिशत (2 - 3 बार) और 27 प्रतिशत ने केवल एक बार ऋण लिया है। अध्ययन क्षेत्र में डब्ल्यूएसएचजी के अस्तित्व की अवधि और ऋण की संख्या (आर = .522 <0.01) के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध देखा गया है।

शुरुआत से अध्ययन क्षेत्र में डब्ल्यूएसएचजी को दिया गया औसत ऋण 2,19,891 रुपये है, जिसमें उच्चतम ऋण 6,00,000 रुपये और सबसे कम 16,000 रुपये है। 2,00,000 रुपये से अधिक का ऋण लेने वाले डब्ल्यूएसएचजी की संख्या 47 प्रतिशत, 1,00,000 रुपये - 2,00,000 रुपये (20 प्रतिशत) और 1,00,000 रुपये से कम (33 प्रतिशत) है। इसके अलावा, अध्ययन क्षेत्र में डब्ल्यूएसएचजी ने सरकार और शीर्ष एजेंसियों के दबाव के कारण दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक ऋण लिया है। एजेंसी-वार संवितरण सहकारी बैंकों (4,29,700 रुपये) द्वारा उच्चतम औसत ऋण वितरण दर्शाता है, इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों (2,22,982 रुपये) और आरआरबी (1,18,209 रुपये) का स्थान है। बीज धन और सब्सिडी के बारे में बातचीत से भ्रष्टाचार और गरीब परिवारों के साथ धोखाधड़ी का पता चलता है क्योंकि किसी भी स्वयं सहायता समूह को बीज धन नहीं मिला है जबकि केवल 33 प्रतिशत समूहों को एसजीएसवाई के तहत सब्सिडी प्रदान की गई है, जिसमें समूह के प्रत्येक बीपीएल सदस्य को 10,000 रुपये का सामान्य आवंटन होता है और प्रति समूह 1 लाख रुपये की सीमा होती है। औसतन, सभी डब्लूएसएचजी सदस्यों ने एकल ऋण प्राप्त करने के लिए सभी जुड़े वित्तीय संस्थानों में 3-4 बार दौरा किया है।

डब्लूएसएचजी सदस्यों द्वारा पुनर्भुगतान में नियमितता मौजूद है जिसे बलपूर्वक या इच्छाशक्ति द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में डब्ल्यूएसएचजी द्वारा चुकाए गए ऋण की औसत राशि 1,77,508 रुपये है, जो 81 प्रतिशत का पुनर्भुगतान अनुपात दर्शाता है। अध्ययन में पाया गया कि 40 प्रतिशत डब्ल्यूएसएचजी का पुनर्भुगतान अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक है, 27 प्रतिशत का पुनर्भुगतान अनुपात 70-90 प्रतिशत के बीच है जबकि 33 प्रतिशत का पुनर्भुगतान अनुपात 70 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, एसएचजी पर एक मजबूत निर्भरता देखी गई है क्योंकि केवल एक डब्ल्यूएसएचजी सदस्य ने अन्य स्रोतों से ऋण लिया है, जबकि 33 प्रतिशत अपनी जरूरतों/आवश्यकताओं के लिए कॉर्पस फंड पर निर्भर हैं।

अध्ययन ने डब्ल्यूएसएचजी की वर्तमान स्थिति को दिखाने के लिए पिछले ऋण विवरण का मूल्यांकन किया है। नए ऋण पिछले ऋणों की पूर्ण चुकौती पर ही प्रदान किए जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 13 प्रतिशत डब्ल्यूएसएचजी ने अपना 60 प्रतिशत पुनर्भुगतान (अनुमानित ब्याज सहित), 50 - 60 प्रतिशत पुनर्भुगतान (47 प्रतिशत) और 50 प्रतिशत से कम (40 प्रतिशत) पूरा कर लिया है। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर वित्तीय स्थिरता सूचकांक (एफएसआई) निम्नानुसार विकसित किया गया है:

$$FSI = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} Z_{ij}\, ,\, 1 \leq \text{FSI} \leq 3$$

विभिन्न वितीय संकेतकों का मूल्यांकन 1.89 के एफएसआई स्कोर के साथ बालासोर जिले में एसएचजी के औसत प्रदर्शन को दर्शाता है। किसी भी डब्ल्यूएसएचजी ने बहुत अच्छे या अच्छे एफएसआई डब्ल्यूएसएचजी स्कोर श्रेणियों में जगह नहीं बनाई। इसके अलावा, 43 प्रतिशत एसएचजी औसत प्रदर्शन श्रेणी में हैं और 57 प्रतिशत एसएचजी खराब प्रदर्शन श्रेणी में हैं (हालांकि दो एसएचजी का औसत स्कोर 1.80 है, जो औसत प्रदर्शन श्रेणी के बहुत करीब है)। एफएसआई डब्लूएसएचजी स्कोर के बैकलॉग के लिए प्रमुख उप-संकेतक उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण का उपयोग (1.00), अंतर-ऋण के लिए परिक्रामी निधि का उपयोग/निकासी (1.375), प्रारंभिक बीज और सब्सिडी (1.30), पुनर्भुगतान दर (1.725) हैं और ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में जाने की संख्या (1.86)। इस बैकलॉग का प्रमुख कारण प्रचार एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों दोनों से आवश्यक जानकारी का प्रसार न होना है। इसके अलावा, किसी भी एसएचजी ने बीज रुपये के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं लिया है और केवल 33 प्रतिशत ने सब्सिडी का लाभ उठाया है। यहां तक कि एसएचजी सदस्यों द्वारा स्वीकृत ऋण के न्यूनतम हिस्से का उपयोग करने की भी सूचना है।

तालिका 4:

एसएचजी का बहुआयामी स्थिरता सूचकांक

एसएचजी का नाम	संगठनात्मक स्कोर (ओआरसीआई)	परिचालन स्कोर (ओपीसीआई)	वित्तीय स्कोर (एफएसआई)	समग्र/एसएचजी स्थिरता स्कोर
बाबा खजूरेश्वर एसएचजी	2.67	2.00	1.70	2.12
बाघदेवी शक्ति एसएचजी	2.00	2.28	1.70	2.00
गोपाल यहूदी एसएचजी	2.33	2.14	1.70	2.06
जगद्धात्री एसएचजी	1.83	2.14	1.90	1.96
जय हनुमान एसएचजी	1.67	1.86	2.00	1.84
मां बसौली एसएचजी	2.33	2.00	2.10	2.14
माँ बसौली शक्ति एसएचजी	1.50	2.28	1.80	1.86
माँ बीनापानी एसएचजी	2.17	1.71	2.10	1.99
मां बिस्लाक्षी एसएचजी	2.83	1.48	1.70	2.00

माँ कालिका एसएचजी	1.83	2.00	2.00	1.94
माँ कुसुमी एसएचजी	1.83	1.71	1.70	1.75
माँ मंगला एसएचजी	1.67	1.71	2.10	1.83
मां सिंहबाहिनी एसएचजी	1.83	1.86	2.20	1.96
शक्ति ग्रुप सरकारनाथ एसएचजी	2.17	2.00	2.00	2.06
श्री राम एसएचजी	1.67	2.14	1.80	1.87
समग्र स्कोर	**2.06**	**1.92**	**1.90**	**1.96**

स्रोतः लेखक की अपनी गणना

तालिका 4 में समग्र परिणाम दर्शाते हैं कि 93 प्रतिशत एसएचजी बहु-आयामी स्थिरता सूचकांक में औसत प्रदर्शनकर्ता श्रेणी से नीचे आते हैं, जबकि 7 प्रतिशत खराब स्थिरता स्थिति दिखा रहे हैं। कोई भी एसएचजी बहुत अच्छी, अच्छी और बहुत खराब स्थिरता श्रेणी में नहीं है। अनुलग्नक V में सहसंबंध मैट्रिक्स 1 प्रतिशत के स्तर पर प्रबंधकीय संकेतक (-.255) और वित्तीय संकेतक (-.377) के साथ कम संगठनात्मक संकेतक (ओआई) के बावजूद एक नकारात्मक महत्वपूर्ण सहसंबंध को दर्शाता है। इसी प्रकार, प्रबंधकीय सूचकांक संगठनात्मक सूचकांक (-.255) के साथ एक नकारात्मक महत्वपूर्ण सहसंबंध दर्शाता है जबकि वित्तीय सूचकांक (-.155) के साथ एक नकारात्मक लेकिन कम महत्वहीन सहसंबंध दर्शाता है।

खंड II: एसएचजी सदस्यों/उद्यमियों की सामाजिक स्थिति और उद्यम स्थिरता

हमारे अध्ययन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए उद्यमिता और उद्यमों के विकास पर एसएचजी कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त संबद्ध एसएचजी (तालिका 4) से चयनित 120 सदस्य/परिवार हिंदू समुदाय (99 प्रतिशत) से हैं जिनमें एकरूपता है (यानि एक ही जाति, इलाके और रिश्ते में से कोई एक)।

तालिका 5:

नमूना प्रतिवादी की मूल जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

मापदंड	माध्य	माध्यिका	एस.डी
उत्तरदाताओं की आयु	39.4	38.0	10.75
समूह में शामिल होने के वर्ष	6.2	6.0	3.1
गुंटा में भूमि स्वामित्व (दशमलव x 2.5 के लिए)	16.5	15.0	11.3
	प्रतिशत		
वैवाहिक स्थिति	विवाहित		94
	अविवाहित		3
	तलाकशुदा/पृथक		3
जाति	सामान्य		53
	अनुसूचित जाति		8
	अनुसूचित जनजाति		7
	अन्य पिछड़ा वर्ग		32

शैक्षणिक स्थिति	निरक्षर	23
	6 वीं कक्षा तक	35
	7-10वीं कक्षा	34
	11-12वीं कक्षा	3
	स्नातक और उससे ऊपर	5
आर्थिक स्थिति	गरीबी रेखा से नीचे	82
	एपीएल	18

स्रोत: प्राथमिक डेटा

इसके अलावा, कार्यक्रम में विभिन्न जातियों के लोगों को शामिल किया गया है, जिससे जिले की संरचना के अनुसार समावेशन परिलक्षित होता है। अधिकतम उत्तरदाता सामान्य (53 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ी जातियों (32 प्रतिशत) से हैं और 77 प्रतिशत साक्षर सदस्य हैं। जिले की औसत महिला साक्षरता 72 प्रतिशत है और लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 957 महिलाओं का है। चयनित डब्ल्यूएसएचजी सदस्यों के परिवारों की औसत भूमि जोत 11.3 के मानक विचलन के साथ 16.5 गुंठा है, जिसमें मुख्य रूप से धान, मूंगफली, सरसों, मूंग, बीड़ी दाल और सब्जियों का उत्पादन करने वाले खेती (पट्टे पर/कब्जा/स्वामित्व) का प्रमुख/पारिवारिक व्यवसाय है। कई एसएचजी सदस्यों ने अपनी ऋण राशि को पट्टे पर दी गई और कब्जे वाली दोनों तरह की भूमि पर खेती में निवेश किया है। कार्यक्रम में सामाजिक और आर्थिक वर्ग की परवाह किए बिना महिलाओं के सभी वर्गों को शामिल किया गया है (साहित्य समीक्षा और मिशन शक्ति के माध्यमिक आंकड़ों के अनुसार) और ऐसा ही देखा गया है कि चयनित नमूनों में से 82 प्रतिशत बीपीएल श्रेणी से हैं। एसएचजी सदस्यों की शैक्षिक स्थिति खराब है क्योंकि 23 प्रतिशत निरक्षर हैं जबकि 35 प्रतिशत ने कक्षा 6 तक पढ़ाई की है और 34 प्रतिशत ने कक्षा 7 से 10 के बीच की पढ़ाई की है। केवल 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उच्चतर माध्यमिक और 5 प्रतिशत ने उच्च शिक्षा (स्नातक और ऊपर) का अध्ययन किया।

डब्लूएसएचजी उद्यम और उद्यमिता विकास

आजीविका के समर्थन के लिए उद्यमशीलता गतिविधियाँ चलाना भारत में एसएचजी कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। स्थिरता विश्लेषण के लिए उद्यमों के साथ-साथ उद्यमिता विकास के लिए विस्तारित समर्थन दोनों का मूल्यांकन किया जाता है।

तालिका 6

डब्ल्यूएसएचजी सदस्य उद्यम विवरण

संकेतक	विवरण	वर्गीकरण	स्कोर
वित्तपोषित गतिविधि की संख्या	आवंटित एसएचजी के माध्यम से वित्त पोषण को अनुमोदित परियोजनाओं में निवेश करना अनिवार्य है। कुछ सदस्य जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए विविध गतिविधियों में निवेश करते हैं।	एकाधिक	3
		अकेले	2
		कोई गतिविधि नहीं	1
रोजगार के कुल दिनों में से बनाए गए रोजगार के समूह दिवस	एसएचजी के माध्यम से वित्तपोषित उद्यमशीलता गतिविधियों में संलग्न होने के कारण सृजित रोजगार के दिन आजीविका के समर्थन में वर्तमान व्यवसायों के योगदान और भविष्य को निर्धारित करते हैं।	60 प्रतिशत से भी अधिक	3
		40 - 60 प्रतिशत	2
		40 प्रतिशत से कम	1
निवेश के रूप में उपयोग किए गए ऋण का प्रतिशत	निवेश के लिए उपयोग किए गए ऋण का प्रतिशत (निश्चित और परिवर्तनीय) सदस्यों की ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है और उपभोग, सामाजिक दायित्वों आदि में व्यय जैसे रिसाव को रोकता है।	75 प्रतिशत से भी अधिक	3
		51 - 75 प्रतिशत	2
		50 प्रतिशत से कम	1
उद्यम से आय (कुल आय का %)	उद्यमों में निवेश से अर्जित कुल आय का प्रतिशत कार्यक्रम में उनकी निर्भरता और योगदान को मापने के लिए प्रॉक्सी का काम करता है।	50 प्रतिशत से ऊपर	3
		35 - 50 प्रतिशत	2
		35 प्रतिशत से कम	1
आय-निवेश अनुपात (मासिक रिटर्न)	आय-निवेश अनुपात उद्यमी द्वारा निवेश से अर्जित लाभ की राशि है। आईआरआर जितना अधिक होगा, निवेश और स्थिरता के लिए प्रोत्साहन उतना ही अधिक होगा।	10 प्रतिशत से ऊपर	3
		6 - 10 प्रतिशत	2
		0 - 5 प्रतिशत	1
वित्तपोषित व्यवसाय में परिवार के सदस्यों की भागीदारी	प्रत्येक सदस्य स्वयं या परिवार के सदस्यों को शामिल करके अपना व्यवसाय संचालित करता है। परिवार के सदस्यों पर अधिक निर्भरता से अन्य स्रोतों से आय कम हो जाती है और उद्यम पर निर्भरता बढ़ जाती है।	स्वयं	3
		स्वयं और पति	2
		परिवार के सभी सदस्य	1
उत्पादन/भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता	उत्पादन या भंडारण सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचे के समर्थन की उपलब्धता बेहतर कीमतों और बाजार पहुंच के लिए धारण क्षमता की सुविधा प्रदान करती है।	व्यक्ति	3
		समूह/समुदाय	2
		स्वयं का घर	1
उद्यमिता विकसित करने के लिए सहायता/समर्थन			

उद्यमिता और उद्यमों के लिए प्रशिक्षण	क्षमता विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण एसएचजी कार्यक्रम के एक विशिष्ट तत्व के रूप में कार्य करता है। उद्यम प्रबंधन और सामाजिक विकास के लिए कौशल वृद्धि उद्यम की स्थिरता के लिए आवश्यक है।	नियमित	3
		कभी-कभी	2
		कभी नहीं	1
विपणन सहायता	एसएचजी एसएचजी सदस्य उद्यमों को सूचना, मूल्य निर्धारण और बाजार पहुंच के रूप में विपणन सहायता प्रदान करते हैं।	संतोषजनक	3
		औसत	2
		कम	1
प्रचार एजेंसियों/सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत	स्थिरता विश्लेषण के लिए उद्यम के विकास, अनुकूलित प्रशिक्षण, सहकारी समितियों के साथ जुड़ाव, समस्याओं पर चर्चा आदि के लिए सदस्यों की बातचीत का मूल्यांकन किया जाता है।	अच्छा	3
		औसत	2
		कम	1

स्रोत: विभिन्न साहित्य समीक्षा और प्राथमिक डेटा सर्वेक्षण से संकलित।

बालासोर जिले में एसएचजी के उद्यमों के लिए उद्यम स्थिरता प्राप्त करने के लिए वित्तीय, प्रबंधकीय और सहायक घटकों को तालिका 6 में संयोजित किया गया था। विश्लेषण से पता चलता है कि समूह ऋण के माध्यम से वित्तपोषित गतिविधियां वांछनीयता और अवसरों के साथ बदलती रहती हैं। डब्ल्यूएसएचजी सदस्यों में से केवल 21 प्रतिशत ने कई गतिविधियाँ की हैं, जबकि अन्य एक ही व्यवसाय (ज्यादातर पारंपरिक यानी खेती या पशुपालन) पर निर्भर हैं। उद्यमशीलता गतिविधियों में लगे सभी लोगों का औसत स्कोर 2.20 है। डब्ल्यूएसएचजी के अधिकांश सदस्यों ने पशुपालन (गाय, बकरी, मुर्गी, बत्तख और बैल का पालन) और खेती (स्वामित्व और पट्टे पर) को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाया है, इसके बाद मछली व्यवसाय, पत्ती प्लेट और कटोरा बनाना, चावल व्यवसाय (फूले हुए और चपटे चावल सहित) और पापड़/बड़ी (सोया नगेट्स) बनाना शामिल हैं।

एसएचजी कार्यक्रम स्कोर का औसत रोजगार योगदान 2.13 है, जिसमें रोजगार के कुल दिनों में लगभग 55 प्रतिशत योगदान है। उद्यमशीलता गतिविधियों के माध्यम से सृजित रोजगार के औसत दिन 3.35 के मानक विचलन के साथ 12 कार्य दिवस हैं। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मासिक रूप से कुल रोजगार दिवसों में से 40-60 प्रतिशत रोजगार सृजित किए हैं, जबकि 22 प्रतिशत सदस्यों ने कुल रोजगार दिवसों में से 60 प्रतिशत से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इसके अलावा, चूंकि ऋण राशि का उपयोग एक चिंता का विषय है, आवंटित ऋण की औसत राशि 15,906 के मानक विचलन के साथ 18,481 रुपये है जबकि उपयोग राशि 12,641 रुपये के मानक विचलन के साथ 14,938 रुपये है। ऋण उपयोगिता स्कोर 0.427 के मानक विचलन के साथ बहुत अच्छा 2.79 है। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आवंटित ऋण का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया है जबकि 19 प्रतिशत ने 51-75 प्रतिशत का उपयोग किया है और केवल एक प्रतिशत ने स्वीकृत ऋण का 50

प्रतिशत से कम उपयोग किया है। अध्ययन क्षेत्र में प्रतिवादी द्वारा लिए गए ऋण और उपयोग किए गए ऋण के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध देखा गया है।

एसएचजी सदस्य स्कोर के उद्यम से आय 0.700 के मानक विचलन के साथ 2.38 है। समूह गतिविधियों से कुल आय का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 51 प्रतिशत है, इसके बाद 35-50 प्रतिशत (37 प्रतिशत) और 35 प्रतिशत से कम 12 प्रतिशत प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत है। लाभ मापने का दूसरा पैरामीटर यानी आईआरआर स्कोर 0.900 के मानक विचलन के साथ 2.25 है। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उद्यम से रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर) 10 प्रतिशत से अधिक है, 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का आईआरआर 6-10 प्रतिशत के बीच है और 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उद्यम रिटर्न प्रति माह उद्यम से 5 प्रतिशत से कम है। उद्यम स्कोर में घर के सदस्यों की भागीदारी 2.30 है, जिसमें 45 प्रतिशत सदस्य अकेले लगे हुए हैं, जबकि 41 प्रतिशत उद्यम उत्तरदाताओं और उनके पति द्वारा संचालित हैं। केवल 14 प्रतिशत उद्यम परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करके संचालित किये जाते हैं। अंत में, अध्ययन क्षेत्र में उत्पादन और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा बहुत खराब है क्योंकि स्कोर 1.37 है। अधिकांश सदस्य घर पर अपना उत्पादन या भंडारण करते हैं (64 प्रतिशत), और समूह/सामुदायिक सुविधा तक पहुंच (34 प्रतिशत) है जबकि केवल 2 प्रतिशत सदस्यों के पास व्यक्तिगत भंडारण/उत्पादन समर्पित घर हैं (अनुलग्नक VIII देखें)।

तालिका 7

एसएचजी और उनके विभिन्न स्थिरता स्कोर

एसएचजी का नाम	उद्यम स्थिरता स्कोर (ए)	उद्यम सहायता स्कोर (बी)	संयुक्त उद्यम स्थिरता स्कोर (ए + बी)	समूह (एसएचजी) स्थिरता स्कोर (सी)	समग्र स्थिरता स्कोर (ए+बी+सी)
बाबा खजूरेश्वर एसएचजी	2.44	1.43	1.93	2.12	2.02
बाघदेवी शक्ति एसएचजी	2.31	1.53	1.92	2.00	1.96
गोपाल यहूदी एसएचजी	2.41	1.60	2.00	2.06	2.03
जगद्धात्री एसएचजी	2.28	1.55	1.92	1.96	1.94
जय हनुमान एसएचजी	2.01	1.37	1.69	1.84	1.76
मां बसौली एसएचजी	2.39	1.49	1.94	2.14	2.04
माँ बसौली शक्ति एसएचजी	2.05	1.53	1.79	1.86	1.82
माँ बीनापानी एसएचजी	2.04	1.94	1.99	1.99	1.99
मां बिस्लाक्षी एसएचजी	2.27	1.80	2.03	2.00	2.02
माँ कालिका एसएचजी	2.00	1.83	1.92	1.94	1.92
माँ कुसुमी एसएचजी	2.11	1.40	1.75	1.75	1.75
माँ मंगला एसएचजी	2.29	1.56	1.93	1.83	1.88
मां सिंहबाहिनी एसएचजी	2.22	1.63	1.93	1.96	1.94

शक्ति ग्रुप सरकारनाथ एसएचजी	1.87	1.76	1.81	2.06	1.94
श्री राम एसएचजी	2.08	1.46	1.77	1.87	1.82
समग्र स्कोर	**2.20**	**1.57**	**1.89**	**1.96**	**1.92**
घटक स्कोर	***1.00 – 1.40***	***1.41 – 1.80***	***1.81 - 2.20***	***2.21 – 2.60***	***2.60*** से ऊपर
श्रेणी/स्थिति	बहुत ख़राब	ख़राब	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा

स्रोत: स्व-गणना।

व्यक्तिगत उद्यम स्कोर विकसित करने के लिए एसएचजी से कुल सहायता 1.25 (बहुत खराब) है क्योंकि 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्पादन/उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, जबकि केवल 26 प्रतिशत ने कभी-कभार प्रशिक्षण में भाग लिया है। किसी भी सदस्य ने अपने उद्यम के विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है। विपणन सहायता स्कोर 1.31 (बहुत खराब) है जबकि प्रचार एजेंसी स्कोर के साथ बातचीत औसत/संतोषजनक (2.15) देखी गई है। डब्लूएसएचजी सदस्य उद्यम स्थिरता स्कोर संतोषजनक/औसत लेकिन अच्छे (2.20) के करीब पाया गया है जबकि उद्यम विकास स्कोर के लिए सहायता खराब (1.57) है।

समग्र एसएचजी कार्यक्रम स्थिरता सूचकांक से पता चलता है कि 87 प्रतिशत एसएचजी औसत प्रदर्शन दिखा रहे हैं जबकि 13 प्रतिशत एसएचजी की 3-पॉइंट स्केलिंग के तहत खराब स्थिति है। अनुलग्नक VI एसएचजी स्थिरता स्कोर (1.96) और उद्यम स्थिरता स्कोर (1.89) के बीच अंतर को दर्शाता है जो 0.01 प्रतिशत स्तर (टी119 = -3.670 <0.01 प्रतिशत) पर महत्वपूर्ण है। 2.20 के औसत स्कोर के साथ एसएचजी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संगठित और प्रबंधित व्यक्तिगत उद्यमों में संभावनाएं मौजूद हैं (जैसा कि उद्यम स्थिरता स्कोर द्वारा दर्शाया गया है) जो उच्च स्तर यानी अच्छे प्रदर्शन श्रेणी के बहुत करीब है। समस्या 1.57 के उद्यम सहायता स्कोर के साथ देखी गई है, जो खराब है।

निष्कर्ष

डब्ल्यूएसएचजी की सूक्ष्म बचत के मामले में बालासोर जिला अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक है। समूह के नियमों और विनियमों को तैयार करते समय प्रचार एजेंसियों द्वारा मानक प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया। ओआरसीआई और ओपीसीआई विचाराधीन एसएचजी की औसत स्थिति दर्शाते हैं। इसके अलावा, अनुत्पादक उद्देश्यों, सब्सिडी और कॉर्पस फंड स्कोर के उपयोग के लिए धन के विचलन के कारण एसएचजी की वित्तीय स्थिरता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। यहां तक कि ये एसएचजी ऋणों की संख्या, ऋण राशि, पुनर्भुगतान में अनियमितता, पुनर्भुगतान दर और लिंक्ड एफआई के दौरों की संख्या के मामले में औसत स्थिति दर्शाते हैं। जबकि एसएचजी सदस्यों द्वारा संचालित व्यक्तिगत उद्यम के मामले में औसत से अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्यम देखे गए। मासिक आईआरआर 27 प्रतिशत से अधिक है जबकि समस्या संगठन और उद्यम विकास घटकों के लिए सहायता को लेकर है। उत्पादक और उद्यम-संबंधित विकास, विपणन सहायता और बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए प्रशिक्षण समय की मांग है। इस प्रकार, अध्ययन एजेंसियों और जमीनी स्तर के सुविधा प्रदाताओं को बढ़ावा देकर एसएचजी कार्यक्रम के नियमों

और नीतियों के सख्त कार्यान्वयन की सिफारिश करता है, जिससे सारे पहलुओं का विस्तार होता है और बाजार-उन्मुख उत्पादक व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, फेडरेशन के हस्तक्षेप के माध्यम से विपणन को चैनलाइज़ किया जाता है और उत्पादक गतिविधियों के नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल वृद्धि की जाती है।

लेखक का योगदान:

नवीन कुमार राजपाल: साहित्य समीक्षा, कार्यप्रणाली, प्राथमिक डेटा संग्रह और स्केलिंग, डेटा विश्लेषण और व्याख्या

शर्मिला तमांग: साहित्य समीक्षा, माध्यमिक डेटा विश्लेषण, प्राथमिक डेटा संग्रह और अपलोडिंग, और व्याख्या

संदर्भ:

Bayulgen, O. (2008).Muhammad Yunus, Grameen Bank and the Nobel Peace Prize: What Political Science Can Contribute to and Learn from the Study of Microcredit, International Studies Review, 10 (3), 525 – 547.

Chakrabarti, R. (2004). The India Microfinance Experience: Accomplishments and Challenges. In Integrating the Rural Poor into Markets, edited by B. Debroy and A. U. Khan, 32–67. New Delhi: Academic Foundation.

Das &Guha (2019).Measuring Women's Self-Help Group Sustainability: A Study of Rural Assam, International Journal of Rural Management, 15 (1), pp. 116 -136.

Maharana, B. (2006). Mission Shakti: Success beyond Target, Orissa Review, 62 (7), 85-87.

NABARD Report (2019), Status of Microfinance in India (SMFI).

Navajas et.al. (2000), Microcredit and the poorest of the poor: Theory and Evidences from Bolivia, World Development, 28 (2).

Priyadarshee, A. (2016). Microfinance and Poverty Reduction: Is Social Protection the Missing Link, Journal of Development, Policy and Practice, Sage Publications, I (I), 35 – 52.

Rajpal, N.(2016), Microfinance and Tribal Women Entrepreneurs, Educreation Publications, India.

Sarkar & Singh (2006). Saving-led microfinance to bank the Unbankables: Sharing of Global Experience, Global Business Review, 7 (2), 271-295.

Tamang, S. (2014).Role of SHGs in the development of Entrepreneurship among rural women in Balasore district of Odisha, Unpublished M. Phil. Dissertation, Mizoram University.

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

संगठनात्मक घटक स्कोर (ओआरसीआई) और परिचालन घटक स्कोर (ओपीसीआई) के लिए युग्मित नमूना टी-परीक्षण

संगठनात्मक घटक अंतिम स्कोर - परिचालन घटक अंतिम स्कोर	युग्मित अंतर					टी	डीएफ	एसआईजी (2-टेल्ड)
	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि माध्य	अंतर का 95% प्रतीति अंतराल				
				निचला	ऊपरी			
	.13494	.50372	.04598	.04389	.22600	2.935	119	.004

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक II:

ओआरसीआई और ओपीसीआई स्कोर के लिए सहसंबंध गुणांक

सहसंबंध			
		परिचालन घटक अंतिम स्कोर	संगठनात्मक घटक अंतिम स्कोर
परिचालन घटक अंतिम स्कोर	पियर्सन सहसंबंध	1	-.254**
	एसआईजी (2-टेल्ड)		.005
	एन	120	120
संगठनात्मक घटक अंतिम स्कोर	पियर्सन सहसंबंध	-.254**	1
	एसआईजी (2-टेल्ड)	.005	
	एन	120	120
**. सहसंबंध 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है (2- टेल्ड)			

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक III:

ओआरसीआई स्कोर, ओपीसीआई स्कोर और ओएमआई स्कोर गणना

ओआरसीआई संकेतक	समूह सदस्यता	बैठक का कार्यक्रम	नेतृत्व में रोटेशन	समूह रचना	नेता चयन प्रक्रिया	समूह बैठक का समय	ओआर सीआइ स्कोर
औसत स्कोर	**1.89**	**1.43**	**2.01**	**2.58**	**2.01**	**2.43**	**2.05**

ओपीसीआई संकेतक	रिकार्ड का रखरखाव	बैठक में उपस्थिति	रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा	निर्णय सृजन	आर्थिक गतिविधि	संघर्ष समाधान प्रक्रिया	सरकारी परियोजनाएँ	ओपीसीआई स्कोर
औसत स्कोर	**2.65**	**1.93**	**1.41**	**2.23**	**1.33**	**2.70**	**1.21**	**1.92**

एफएसआई संकेतक	कॉर्पस फंड	ऋण की संख्या	ऋण की राशि	प्राप्त हुई सब्सिडी/ बीज राशि	पुनर्भुगतान में नियमितता	अन्य स्रोतों से ऋण	परिक्रामी निधि का उपयोग	ऋण के लिए एफआई की यात्रा की संख्या	चुकौती दर	निधियों का उत्पादक उपयोग	एफएसआई औसत स्कोर
औसत स्कोर	**2.63**	**2.04**	**2.05**	**1.30**	**2.03**	**2.95**	**1.37**	**1.85**	**1.72**	**1.00**	**1.89**

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक IV:

एफएसआई के विभिन्न संकेतकों पर उत्तरदाताओं की स्थिति

एफएसआई घटक	**माध्य**	**मानक विचलन**	**माध्यिका**
कॉर्पस फंड (बचत) आईएनआर	20,619	10,567	20,900
ऋण की संख्या	2.79	1.44	3.00
ऋण की राशि (आईएनआर)	2,19,891	1,89,089	1,85,000
सब्सिडी/बीज राशि का लाभ उठाया गया	31,958	48,543	n.a.
पुनर्भुगतान में नियमितता/ औसत ऋण चुकाया गया	1,77,508	1,59,900	1,08,287
अन्य स्रोतों से ऋण	2,500	n.a.	n.a.
परिक्रामी निधि स्कोर का उपयोग/निकासी	1.37	.486	1.00
ऋण प्राप्त करने के लिए लिंक्ड एफआई पर की गई यात्राओं की संख्या	3.50	0.98	3.00
उत्पादक प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग (%)	86.89	15.79	92.4

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक V:

ओआरसीआई, ओपीसीआई और एफएसआई का सहसंबंध मैट्रिक्स

सहसंबंध				
		संगठनात्मक स्कोर	परिचालन स्कोर	एफएसआई स्कोर
संगठनात्मक स्कोर	पियर्सन सहसंबंध	1	-.255**	-.377**
	एसआईजी (2-टेल्ड)		.005	.000
	एन	120	120	120
परिचालन स्कोर	पियर्सन सहसंबंध	-.255**	1	-.155
	एसआईजी (2-टेल्ड)	.005		.092
	एन	120	120	120
एफएसआई स्कोर	पियर्सन सहसंबंध	-.377**	-.155	1
	एसआईजी (2-टेल्ड)	.000	.092	
	एन	120	120	120
**. सहसंबंध 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है (2- टेल्ड)				

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक VI:

एसएचजी और उद्यम स्थिरता स्कोर के लिए युग्मित नमूना टी-टेस्ट

एसएचजी स्थिरता स्कोर और उद्यम स्थिरता स्कोर	युग्मित अंतर					टी	डीएफ	एसआईजी (2-टेल्ड)
	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि माध्य	अंतर का 95% प्रतीति अंतराल				
				निचला	ऊपरी			
	-.06833	.20396	.01862	-.10520	-.03147	-3.670	119	.000

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक VII:

ओएमआई स्कोर गणना

ओपीसीआई संकेतक	रिकार्ड का रखरखाव	बैठक में उपस्थिति	रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा	निर्णय सृजन	आर्थिक गतिविधि	संघर्ष समाधान प्रक्रिया	सरकारी परियोजनाएँ	ओपीसीआई स्कोर
औसत स्कोर	**2.65**	**1.93**	**1.41**	**2.23**	**1.33**	**2.70**	**1.21**	**1.92**

ओआरसीआई संकेतक	समूह सदस्यता	बैठक का कार्यक्रम	नेतृत्व में रोटेशन	समूह रचना	नेता चयन प्रक्रिया	समूह बैठक का समय		ओआरसी आई स्कोर
औसत स्कोर	**1.89**	**1.43**	**2.01**	**2.58**	**2.01**	**2.43**		**2.05**

$$OMI^{WSHG} = \frac{1}{2}\sum \quad \text{ORCI} + \text{OPCI} \ \ (1 < OMI < 3)$$

or

$$OMI^{WSHG} = \frac{1}{13}\sum \quad \text{MR} + \text{AM} + \text{RA} + \text{DM} + \text{EA} + \text{CRP} + \text{GP} + \text{GM} + \text{MS} + \text{RL} + \text{GC} + \text{LP} + \text{GT} \ \ (1 < OMI < 3)$$

1.98

स्रोत: प्राथमिक डेटा

अनुलग्नक VIII:

एसएचजी उद्यम प्रदर्शन और सहायता स्कोर

एसएचजी उद्यम संगठन का प्रदर्शन	Score
वित्तपोषित गतिविधि की संख्या	2.21
रोजगार के कुल दिनों में से बनाए गए रोजगार के समूह दिवस	2.13
निवेश के रूप में उपयोग किए गए ऋण का प्रतिशत	2.79
उद्यम से आय (कुल आय का %)	2.38
आय-निवेश अनुपात (मासिक रिटर्न)	2.25
वित्तपोषित व्यवसाय में परिवार के सदस्यों की भागीदारी	2.30
उत्पादन/भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता	1.37
एसएचजी उद्यम सहायता	**Score**
उद्यमिता और उद्यमों के लिए प्रशिक्षण	1.26
विपणन सहायता	1.31
प्रचार एजेंसियों/सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत	2.15

स्रोत: प्राथमिक डेटा

पुस्तक समीक्षा: वॉट वर्क्स: जेंडर इक्वैलिटी बाय डिज़ाइन बाय आइरिस बोहनेट, 2016, बेल्कनैप प्रेस: एन इम्प्रिंट ऑफ़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेपरबैक संस्करण, पृष्ठ 400, आईएनआर 599

* अनुराधा पल्ला

प्रस्तावना

आइरिस बोहनेट द्वारा लिखित 'व्हाट वर्क्स: जेंडर इक्वेलिटी बाय डिज़ाइन' संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए अभिकल्पना और मार्ग प्रशस्त करता है। यह पुस्तक लैंगिक समानता की अभिकल्पना करने और बेहतर मूल्यांकन प्रक्रियाएँ बनाने के लिए परिमाणित पैरामीटर भी देती है। आइरिस बोहनेट द्वारा किया गया विश्लेषण एक दिलचस्प विशेषता पर जोर देता है कि लैंगिक असमानताएं सामयिक हैं और सरकारी नीतियों एवं लोकतांत्रिक व्यवहार में पारदर्शिता की शक्ति पर निर्भर करती हैं।

समस्या

यह पुस्तक चार भागों में विभाजित है। पहला भाग समस्या का विश्लेषण करता है और दूसरा भाग प्रतिभा प्रबंधन को डिज़ाइन करने के तरीके बताता है। स्कूलों और काम को कैसे डिज़ाइन किया जाए, और महिलाओं की गतिविधियों की विविधता को कैसे डिज़ाइन किया जाए, इसे अगले दो भागों में समझाया गया है। जहां तक समस्या का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जीत नहीं सकतीं क्योंकि वे दूसरों का पालन-पोषण करने और उनकी देखभाल करने की स्त्रियोचित रूढ़ि के अनुरूप होती हैं। महिलाओं पर किए गए अधिकांश अध्ययनों में पुरुषों के वर्चस्व वाली भूमिकाओं में महिलाओं के प्रति अंतर्निहित सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रह देखा गया है। कोई व्यक्ति फिट बैठता है या नहीं, इसके बारे में पूर्वाग्रह मायने रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1970 के दशक में, केवल पाँच प्रतिशत संगीतकारों ने शीर्ष पाँच ऑर्केस्ट्रा में प्रदर्शन किया। 2020 में उनका प्रतिशत बढ़कर 35 हो गया, जो संयोग से नहीं हुआ। इसमें लैंगिक समानता की दिशा में प्रमुख संगीत कंपनियों और सरकारी नीतियों द्वारा जानबूझकर हस्तक्षेप की आवश्यकता थी

मन को पूर्वाग्रह से मुक्त करना कठिन है; इसके लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता की आवश्यकता होती है, जिससे नैतिक लाइसेंस प्राप्त होता है जहां लोग महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने पर प्रतिक्रिया देते हैं। भारत में, एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी टीवी शो, सत्यमेव जयते के प्रदर्शन के माध्यम से कई प्रयोग किए गए। कार्यक्रम में उन अत्याचारों और असमानताओं का दस्तावेजीकरण किया गया जो निचली जाति के लोग अक्सर अनुभव करते हैं। बताया जाता है कि इस कार्यक्रम के फीडबैक की सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने सराहना की है।

डिजाइनिंग प्रतिभा प्रबंधन

इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लोगों के निर्णयों को डिजाइन करने के लिए डेटा या माप की आवश्यकता होती है। जो चीज़ मापी नहीं जाती, उसकी गिनती नहीं होती. Google का प्रयोग कर्मचारियों की ख़ुशी को मापता है और उन्हें अधिक उत्पादक बनाता है (इस प्रयोग का विवरण जोड़ सकता है)।

लैंगिक वेतन अंतर दुनिया भर में प्रचलित है, हालांकि अंतर का आकार देशों, क्षेत्रों और इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट पद्धति के अनुसार भिन्न होता है। 2014 में अमेरिका में लिंग वेतन अंतर 21 प्रतिशत था। यूरोपीय संघ में, 2013 में यह 16.4 प्रतिशत था, और कोरिया (उत्तर या दक्षिण) में, यह 37 प्रतिशत था। न्यूज़ीलैंड में 5.6 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो विकसित दुनिया में सबसे कम है।

बेहतर मूल्यांकन प्रक्रियाओं के साथ डेटा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता मूल्यांकन प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करते समय, किसी को निम्नलिखित तीन चरणों का पालन करना चाहिए:

1. साक्षात्कारकर्ताओं को लैंगिक समानता के साथ अलग-अलग बैचों में विभाजित करना।

2. नौकरी आवेदनों से जनसांख्यिकीय जानकारी हटा दें।

3. पूर्वानुमानित परीक्षणों और संरचित साक्षात्कारों का उपयोग करें।

मूल्यांकन साक्षात्कार आयोजित करते समय, निष्पक्ष लिंग राय वाले सही लोगों को नियुक्त करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अनुसूची में उपयोग की जाने वाली भाषा में लिंग-निष्पक्ष चरणों को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए।

डिजाइनिंग प्रशिक्षण और कार्यान्वयन:

महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्हें यह सिखाना है कि नौकरी के लिए कैसे तैयार रहें और जोखिम लेना स्वीकार करें या जोखिम से बचें। विभिन्न जोखिम प्रकारों को शामिल करते हुए वातावरण बनाना प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा वातावरण डिज़ाइन करना महत्वपूर्ण है जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों पनपें। केन्या और भारत में बच्चों के बीच कृमि मुक्ति पर किए गए विभिन्न अध्ययनों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर लागत प्रभावी और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन प्रशिक्षण और कार्य को डिजाइन करने का एक उदाहरण है। यह भी पाया गया है कि जब जोखिम कारक ज्ञात होते हैं तो पुरुष अधिक जोखिम लेने को तैयार होते हैं और जोखिम भरी स्थितियों का आकलन करते समय अधिक आशावादी होते हैं। महिलाएं कुछ हद तक अति आत्मविश्वासी होती हैं और कुछ मामलों में तो कम आत्मविश्वासी भी होती हैं।

ऐसी स्थितियों में, हमें लिंग-तटस्थ डिज़ाइन का उपयोग करना होगा, लिंग पूर्वाग्रह के प्रभाव को कम करना होगा और लिंग पूर्वाग्रह के कारण होने वाले विभेदक प्रभावों की भरपाई करनी होगी। लैंगिक समानता की रूपरेखा तैयार करने के लिए रोल मॉडल बनाना महत्वपूर्ण है। कुछ अफ़्रीकी देशों में राजनीति, उद्योग और सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं में सफल महिलाओं के चित्र प्रदान करके ऐसे प्रयोग किए गए।

टीम के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता की पूरक विविधता के साथ औसत क्षमता को जोड़कर क्राफ्टिंग समूह बनाना भी महत्वपूर्ण है। विविध दृष्टिकोणों को योगदान देने और सुनने की अनुमति देने के लिए समावेशी समूह प्रक्रियाएं बनाना आवश्यक है।

कार्यक्रमों की विविधता को डिज़ाइन करने के लिए, कई नियम अभिव्यंजक कार्य करते हैं जिनकी अक्सर जांच नहीं की जाती है। वे अनौपचारिक रूप से मंजूरी दे सकते हैं और इनाम दे सकते हैं, जो बदले में एक दायित्व साबित हो सकता है। पुराने मानदंडों को नए मानदंडों से बदलने से लैंगिक विविधता बढ़ाने में दूसरों की सफलताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं (थोड़ी अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है)। हम नए मानदंडों को व्यक्त करने के लिए नियमों, कानूनों और आचार संहिता का उपयोग कर सकते हैं।

माप के लिए जानकारी एकत्र करते समय, हमें कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। लिंग विविधता को बढ़ावा देने के लिए अब बड़ी संख्या में देश पारदर्शी तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा विनिमय बोर्ड कंपनियों से सालाना अपनी विविधता नीतियों और विविधता की डिग्री की रिपोर्ट करने के लिए कहता है। उन्हें समग्र रूप से महिला कर्मचारियों का अंश और वरिष्ठ पदों पर और कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या की रिपोर्ट करनी होगी। इसी तरह, कनाडा में, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों से सामान्य कर्मचारियों के साथ-साथ प्रबंधन बोर्डों के बीच महिलाओं के अनुपात को प्रकाशित करने के लिए कहता है। ऐसी जानकारी मुख्य, सरल और तुलनीय होनी चाहिए।

डिजाइनिंग में बदलाव

पुस्तक में पूरी चर्चा विभिन्न प्रतिष्ठानों में बदलाव की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से व्यवहारिक डिजाइन और "क्या काम करता है" पर विश्वास के साथ अनुसंधान-आधारित अंतर्दृष्टि में। किसी प्रयोग के डिज़ाइन में तीन भाग होते हैं:

1. परिमाणीकरण उपकरणों के लिए डेटा एकत्र करना
2. पारदर्शिता के साथ डिजाइन और प्रयोग करना और इसे कार्यान्वयन योग्य बनाना
3. प्रयोग के सुझाए गए हस्तक्षेपों के लिए रूट मैप तैयार करना

यह पुस्तक चार डिज़ाइन सुझाती है:

1. प्रशिक्षण से क्षमता निर्माण की ओर बढ़ना
2. अंतर्ज्ञान से डेटा की ओर बढ़ना और एक संरचना बनाना
3. असमान से समतल खेल मैदान की ओर बढ़ना
4. नंबर गेम से लेकर सफलता की परिस्थितियों तक विविधता।

यह पुस्तक लैंगिक समानता के लिए नीतियों को डिजाइन करने की उनकी खोज में दुनिया भर की कंपनियों, विश्वविद्यालयों और सरकारों के लिए उपयोगी है, जो एक निष्पक्ष और बेहतर दुनिया के निर्माण की दिशा में सुई को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

अनुराधा पल्ला
सहायक प्रोफेसर,
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उजागर कर राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाली हिन्दी, हमारे राष्ट्र की गौरवशाली परम्परा का प्रतीक है। कहीं अच्छा हो यदि ग्रामीण विकास में निरन्तर सेवारत विद्वान अपना चिन्तन, मनन और लेखन मूलतः हिन्दी में कर अपने कार्य और ज्ञान से करोडों भारतीय जनसाधारण को लाभान्वित करें ।

www.nird.org.in